Thursday, 10 May, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड २, १९६२/१८८४ (शक)

[३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumig 18.10.73

Preservation Unit.
14.5.92
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड २ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खंड २, अंक ११ से २०—३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ बैशाख, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० बैशाख, १८८४ (शक) — पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण — ६६९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६९, २७०, २७२, २८३, २७३ से २८१, २८४ से २८६ और २८८ से २९० — ६६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७१, २८२, २८७ और २९१ से २९८ — ६९४—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५० से ३२६ और ३२८ से ३६२ — ६९८—७४८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — ७४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना — ७४८—५१

१. आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . — ७४९—५१

२. पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिसमें भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है . . . . — ७५१

३. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना — ७५१

समितियों के लिये निर्वाचन . — ७५१—५२

१. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . — ७५१

२. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति — ७५२

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक—पुरस्थापित — ७५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . — ७५३

दैनिक संक्षेपिका . — ७९०—९६

अंक १२—मंगलवार, १ मई, १९६२/११ बैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . — ७९७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९९, ३०१, ३०२, ३०४ से ३०६, ३०८, ३११ से ३१५ और ३१७ से ३१९ . . — ७९७—८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३०७, ३०९, ३१०, ३१६, ३२० से ३३६ . . . . ८२२—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४१२, ४१४ से ४२२, ४२४ से ४३५, ४३७ से ४४८, ४५० और ४५१ ८३३—७३

प्रक्रिया के बारे में ८७३–७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ८७४—७८

१. बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण . . ८७४—७५

२. लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोपड़ियों को आग लगना ८७५–७८

३. सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्व पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार . ८७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८७९-८०

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि ८८०

बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य ८८०–८१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८८१—९१६

कार्य मंत्रणा समिति——

पहला प्रतिवेदन ९१६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ९१७—२३

अंक १३——बुधवार, २ मई, १९६२/वैशाख १२, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४४, ३४६, से ३४९, ३७०, ३५१ और ३५३ ९२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५०, ३५२, ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३७९ ९५०—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ५२३ . . ९६३—९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ९९६—९८

१. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्रचना की आवश्यकता ९९६–९७

२. गुजरात में कपास का अधिग्रहण . . ९९७–९८

३. पूर्वी पाकिस्तान में ढाका तथा राजशाही में दंगे ९९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९९८—१०००

कार्य मंत्रणा समिति——

पहला प्रतिवेदन . . १०००

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . १००१—११

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . . १०११—५७

दैनिक संक्षेपिका १०५८—६७

अंक १४—गुरुवार, ३ मई, १९६२/१३ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण— . .

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . १०६७

तारांकित प्रश्न संख्या ३८०, ३८२ से ३८६, ३९३ से ३९६ और ३९८ १०६७—९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८१, ३९० से ३९२, ३९७ और ३९९ से ४१५ १०९४—११०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ६०२, ६०५ से ६२१ और ६२३ से ६३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

१. स्माल स्केल वुलन मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन और स्क्रीन प्रिन्टर्स द्वारा अपने समवाय बन्द कर देने की धमकी . ११५१—५२

२. हुगली के पायलेटों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी ११५२—५४

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५५—५६

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. पशु कल्याण बोर्ड . ११५६

२. भारतीय लाख उप-कर समिति . . . ११५६—५७

३. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का प्रशासी निकाय ११५७

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलामा—

(१) भारत को चीन को कथित अलटीमेटम ; तथा . ११९३—९४

(२) १५० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान में चले जाना ११९४—९६

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—

दैनिक संक्षेपिका १२०६—१२१४

अंक १५—शुक्रवार, ४ मई, १९६२/१४ बैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १२१५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४१९, ४२१ से ४२५ और ४२८ से ४३३ । १२१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १२३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२०, ४२६, ४२७ और ४३४ से ४५० . . . १२३८--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८, ६३९, ६४२ से ७१३ और ७१५ से ७२१ . . . १२४७--८१

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . १२८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२८२

राष्ट्रपति का संदेश . . . १२८२

सभा का कार्य . . . १२८३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . १२८३--१३१७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--

पुरःस्थापित और पारित . . . १३१८-१९

जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के बारे में संकल्प . . . १३१९--३८

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प . . . १३३८

दैनिक संक्षेपिका . . . १३४४-५०

अंक १६—सोमवार, ७ मई, १९६२/१७ वैशाख १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . . १३५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६१, ४६३, ४६४, ४६६ और ४६७ . . . १३५१--७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६२, ४६५ और ४६८ से ४९९ . . . १३७६--८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७५२, और ७५४ से ७७२ . . . १३८९--१४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर और चीन के सिंक्यांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय . . . १४१०-११

सभा पटल पर रखे गये पत्र--

समितियों में निर्वाचन--

१. राजघाट समाधि समिति और . . . १४१२

२. कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . . १४१३

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . . . १४१३--३८

दैनिक संक्षेपिका . . . १४३९--१३

अंक १७, मंगलवार, ८ मई १९६२ / १८ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०४ और ५०६ से ५१४ . . . १४४५—६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . १४६९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ और ५१५ से ५४६ . . . १४७१—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ से ८६०, ८६२ से ८७८, ८८०, ८८१, ८८३, ८८४, ८८६ से ९१० और ९१२ से ९२३ . . . १४८६—१५५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा लैंड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का गिरना . १५५३—५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र— १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . १५७६—७७

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में . . . . . १५८८—९६

दैनिक संक्षेपिका—

अंक १८, बुधवार, ९ मई १९६२ / १९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५५६ और ५५८ . १५९७—१६१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . १६१९—२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ और ५५९ से ६०९ . . . १६२०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से १०२६ . . . . १६४३—८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई १६८७

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में १६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १६८८—९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . १६९०—१७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . १७१५—२३

अंक १९, गुरुवार, १० मई, १९६२ / २० वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१५, ६१७ से ६२०, ६२३, ६२६ से ६२८, ६३८ और ६२९ से ६३२ . . . १७२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१६, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६३३ से ६३७ और ६३९ से ६४५ . १७५०—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०६९ और १०७१ से १०७७ . १७५७—८०

हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में . . . . १७८०—८२

सूचना प्राप्त करने के बारे में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

चीनी वाणिज्य दूतावास कलिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना . १७८२—८३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में छपाई के कागज की कमी १७८३—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १७२४—१८२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १७२९—३२

अंक २०, शुक्रवार ११ मई, १९६२ / २१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६४९, ६५१ से ६५५ और ६५७ से ६६३ . १८३३—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १८५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५०, ६५६ और ६६४ से ६९१ . . १८५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ से १०८२ और १०८४ से ११८६ १८७०—१९२३

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

माल गाड़ी और ट्रक की टक्कर १९२३—२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. फिजो के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक और दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान १९२८

GMGIPND—LS III—811 AI LSD—12-7-62—150

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १० मई, १९६२
२० वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गोबर से बनने वाली गैस

†*६१०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खादी आयोग ग्राम उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में गोबर से गैस बनाने के संयंत्र की स्थापना के लिये एक नई योजना शुरू करने का इरादा रखता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मध्य प्रदेश में गोबर से गैस बनाने के संयंत्र चालू करने की योजना अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मैं ने एक दूसरे प्रश्न पर परसों अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

+

†*६११. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री बालमीकी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के लिये १५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

759 (Ai)LSD—1

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) योजना आयोग की ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ४० चुनी हुई ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के लिये १५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की है।

(ख) इस योजना पर भारत सरकार अभी विचार कर रही है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या माननीय मंत्री हमें इस की कुछ रूपरेखा बता सकते हैं कि किस प्रकार की परियोजनायें शुरू की जायेंगी ?

†**श्री कानूनगो** : कल्पना यह है कि ४० क्षेत्र चुने जायेंगे जहां विभिन्न ग्रामोद्योगों पर सभी सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जायगा और छोटे उद्योग की परियोजनाओं को इकट्ठा कर दिया जायगा और उन के लिये नियत रकम उन पर खर्च की जायगी और उन क्षेत्रों का काफी विकास किया जायगा। इस का ब्यौरा योजना आयोग के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

†**श्री श्री नारायण दास** : ये परियोजनायें ग्रागाण उद्योग किस प्रकार के होंगे ?

†**श्री कानूनगो** : वे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहां सुविधायें उपलब्ध हैं, भिन्न भिन्न होंगी। मुख्य बात बिजली और कई दूसरी चीजें सप्लाई करना है जिस से ग्रामीण जनता को कुटीर उद्योगों से ले कर मशीनों वाले छोटे उद्योगों के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इन ग्रामीण परियोजनाओं के स्थान चुनने का क्या आधार होगा ?

†**श्री कानूनगो** : ब्यौरे अभी तैयार करने हैं। स्थान वह होंगे जहां संचार साधन उपलब्ध हों, वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो और जहां बिजली तथा दूसरी चीजें आसानी से उपलब्ध हो सकें।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : योजना आयोग की ग्रामीण औद्योगिक समिति ने जिन ४० ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं का सुझाव दिया है, उन में से कितनी संभवतः मद्रास राज्य में होंगी ?

†**श्री कानूनगो** : वह तय नहीं किया गया है।

†**श्री श्यामलाल शर्राफ** : क्या इस का अर्थ यह होगा कि जो उद्योग भी मौजूद हैं उन का एक समूह बनाया जायगा या इन केन्द्रों में नई परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी ?

†**श्री कानूनगो** : विभिन्न बोर्डों के कामकाज समन्वय के प्रयोजन के लिए इकट्ठे कर दिये जायेंगे और अतिरिक्त सुविधायें दी जायेंगी।

श्री बड़े : जापान में जिस प्रकार की काटेज इंडस्ट्री चलती है, क्या उसी प्रकार से यहां इंडस्ट्री चलने वाली हैं ?

श्री कानूनगो : नहीं, हमारे मुल्क में जो चल रही है, उसी को बढ़ाना है।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या सरकार इन उद्योगों के लिए धन देगी या इन उद्योगों को चलाने वाले व्यक्तियों को ऋण देगी ?

†**श्री कानूनगो** : यह जाहिर है कि छोटे उद्योग मालिकों द्वारा ही चलाये जायेंगे। इसलिये धन देने की कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि व्यक्तिगत उद्योगपतियों को ऋण दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांसीसी प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

+

†*६१२. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ़्रांस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, एम० एन्तोन पिने, ने पांच परामर्श-दाता इंजीनियरों के एक दल की भारत यात्रा का नेतृत्व किया और कहा कि उन का देश भारत की सहायता करने के लिये तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । फ़्रांस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा खनन, रेलवे, बिजली, गैस और प्राकृतिक गैस तथा नगर परिवहन के क्षेत्रों में परामर्शदाता इंजीनियरिंग फर्मों के एक समूह के वर्तमान अध्यक्ष श्री एम० एन्तोन पिने अभी हाल परामर्शदाता इंजीनियरों के एक दल के साथ भारत आये थे । उन के आने का उद्देश्य यह था कि उपयुक्त भारतीय अधिकारियों को यह बताया जा सके कि फ्रांसीसी इंजीनियरिंग और परामर्शदाता फर्में विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या सेवाएं कर सकती हैं ।

(ख) उपर्युक्त दल ने संबंधित मंत्रियों और भारत सरकार के मंत्रालयों और योजना आयोग के कर्मचारियों से मुलाकात की । उन के साथ जो चर्चा हुई यह समान प्रकार की थी और मुख्यतः खोजबीन संबंधी थी । इन चर्चाओं को मद्देनजर रख कर वह दल फ्रांस लौटने पर तकनीकी सहायता के ठोस प्रस्ताव भेज सकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राईवेट सैक्टर के उद्योगपतियों से भी उन लोगों की बातचीत हुई थी या नहीं और अगर हुई थी, तो हिन्दुस्तान के कौन कौन से उद्योगों में उन्होंने सहायता देने का आश्वासन दिया है ।

श्री कानूनगो : सहायता का सवाल नहीं है । उन की कनस्लटेन्ट्स की एक फ़र्म है और कन-सल्टेशन के काम में वे जो सर्विस दे सकते हैं, उस के सम्बन्ध में उन्होंने बातचीत की है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि शिपिंग के बारे में भी उन से कोई बातचीत हुई थी और हमारे यहां जो सैकिंड शिपयार्ड बनने वाला है, उस के सम्बन्ध में भी सहायता लेने की कोई बात हुई है ?

श्री कानूनगो : सहायता का कोई सवाल ही नहीं है । उन्होंने कहा है कि वे इन सेवाओं के लिये परामर्श दे सकते हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार या गैर-सरकारी उद्योगपति उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या उन के साथ चर्चा के दौरान हमारी ओर से इस बात का कोई संकेत दिया गया था कि हमें किस प्रकार की तकनीकी सहायता की जरूरत है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : माननीय मंत्री ने बताया कि एक फ्रांसीसी संगठन भारतीय रेलवे की सहायता करने के लिये पहले ही मुकरर किया गया है । वह कौन सा संगठन है और भारतीय रेलवे के सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे मालूम नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रख गये विवरण में कहा गया है कि इस दल का उद्देश्य भारतीय अधिकारियों को यह बताना था कि फ्रांसीसी इंजीनियरिंग और परामर्शदाता फर्में विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या सेवा कर सकती हैं, और उस दल ने संबंधित मंत्रियों, भारत सरकार के मंत्रालयों और योजना आयोग के कर्मचारियों से मुलाकात की । यह बिलकुल अस्पष्ट है । क्या माननीय गृह मंत्री इस पर और अधिक प्रकाश डालेंगे और ठीक ठीक बतायेंगे कि किन किन मंत्रालयों के साथ उन्होंने बातचीत की और किन किन क्षेत्रों के सम्बन्ध में ?

†**श्री कानूनगो** : वह फ्रांसीसी परामर्शदाताओं का एक संघ है और वे परामर्श देकर सेवा करते हैं । वे कई क्षेत्रों जैसे पेट्रो-केमिकल्स, रेलवे, इंजीनियरिंग आदि, में परामर्श देते हैं । वे योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से मिले और उन्होंने बताया कि वे अमुक अमुक सेवा कर सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत में ऐसे कोई क्षेत्र हैं जिनके सम्बन्ध में अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य देश परामर्श नहीं दे रहे हैं और जिनके लिए हमें इन फ्रांसीसी परामर्शदाताओं से सहायता की जरूरत हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न उनकी यात्रा के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य ने बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा है ।

फास्फोरस संयंत्र

+

†*६१३ { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामंत :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फास्फोरस संयंत्र की स्थापना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या इस संयंत्र की स्थापना के लिये कोई विदेशी सहायता की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता आवश्यक है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र में फास्फोरस तैयार करने की परियोजना अभी फिलहाल स्थगित कर दी गयी है

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए आवश्यक बिजली उपलब्ध नहीं है और अभी इस परियोजना के आर्थिक पहलू भी काफी आकर्षक नहीं मालूम पड़ते।

फास्फोरस तैयार करने की बहुत कठिन और पेचीदी प्रौद्योगिक प्रणाली के कारण भारी साज़-सामान और तकनीकी जानकारी के रूप में विदेशी सहायता इस परियोजना के लिए आवश्यक होगी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण में बताया गया है कि बिजली की कमी के कारण परियोजना स्थगित कर दी गयी है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत आकर्षक नहीं है। यदि ऐसा हो, तो क्या भविष्य में भी इस परियोजना पर फिर विचार करने की कोई आवश्यकता है?

†**श्री कानूनगो** : निश्चय ही; जब परिस्थितियां अधिक अनुकूल हों क्योंकि यह एक ऐसा उद्योग है जिसकी हमें जरूरत है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस देश में फास्फोरस की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और वह कैसे पूरी की जा रही है?

†**श्री कानूनगो** : पिछले साल की कुल आवश्यकता, जो अब कम हो गयी है, ३,९२,००० किलोग्राम थी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यह उद्योग कहां स्थापित होगा और फास्फोरस किस जगह काफी मात्रा में मिलता है?

†**श्री कानूनगो** : अभी इसका निश्चय नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना अभी स्थगित कर दी गयी है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह उद्योग राजस्थान में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : निश्चय ही।

गोआ में परती भूमि

†*६१४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में भूमि के बड़े बड़े टुकड़े खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो परती भूमि का रकबा कितना है; और

(ग) इस भूमि पर खेती कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) करीब करीब ९२,००० हेक्टअर्स

(ग) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक दल अभी हाल गोआ गया था और उसकी रिपोर्ट पर जिसमें कृषि सुधार के लिए कार्यवाहियों का उल्लेख है, सरकार विचार कर रही है।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार इन जमीनों को तोड़ने के बाद गोआ के बे-ज़मीन लोगों को या उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को खेती करने के लिए देगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह प्रश्न परती भूमि के सम्बन्ध में है। इतने एकड़ . . . .

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या ये जमीनें खेती के लिए सहकारी समितियों को दी जायेंगी ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : रिपोर्ट की छानबीन के बाद वह तय किया जायगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इस बारे में कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी किया जायगा।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि गोआ में जमीन पुर्तगाली शासन में पले हुए जमींदारों के एकाधिकार में है और यदि हां, तो क्या हमारे देश में जैसे भूमि सुधार हुए हैं वैसे भूमि-सुधार गोआ में भी लागू करने का सरकार का विचार है।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : रिपोर्ट का अध्ययन किये जाने के बाद हम इस बात पर सोचेंगे कि भारत में लागू किये गये भूमि सुधार वहां भी लागू किये जाने चाहिये अथवा नहीं।

श्री जं० ब० सिंह : क्या सरकार यह सोच रही है कि जो पापुलेशन हिन्दुस्तान के अन्दर गोआ के बाहर है, उस में जो बहुत गरीब लोग हैं, उन को वहां ले जा कर और ऊसर जमीन उन को बांट कर बसाया जाय।

अध्यक्ष महोदय : वह तो कह रही हैं कि पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिये।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं जवाब दे दूं। इस का कोई अन्देशा नहीं है। कोई हमारा इरादा नहीं है इस तरह करने का। इस तरह वहां के लोगों में बहुत गड़बड़ी पैदा हो जायेगी कि हम बाहर के लोगों को वहां बसा रहे हैं। वहां काफी लोग रहते हैं, यह तो है नहीं कि वह खाली पड़ा हुआ है। ग़ौर तो हर बात पर होगा, लेकिन बहुत कम अन्देशा है इस बात के होने का।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भूमिहीन गोआनी गोआ में कोई रोजगार न मिलने के कारण बम्बई और दूसरी जगहों में जाने के लिए बाध्य हुए थे उन्हें किस हद तक वहां लौटने और बसने दिया जायगा।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने इस सवाल के बारे में तुरन्त अपनी राय जाहिर की है। गोआनी वहां हमेशा जा सकते हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी जा सकते हैं। लेकिन वहां लोगों के बसाने की योजना का जहां तक सम्बन्ध है, वह एक अलग मामला है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : गोआनी

†श्री जवाहरलाल नेहरू : गोआनी व्यक्तिगत रूप में वहां हमेशा जा सकते हैं और बस सकते हैं।

ओखला स्थित भारत-जर्मन नमूना केन्द्र में दुर्घटना

†*६१५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला (नई दिल्ली) स्थित भारत-जर्मन नमूना और उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र (इण्डो-जर्मन प्रोटोटाइप-कम-प्रोडक्शन ट्रेनिंग सेंटर) के फाउन्ड्री शाप में २४ मार्च,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६२ को एक भीषण दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप एक प्रशिक्षार्थी की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) क्या उस घायल व्यक्ति को एक घंटे के बाद अस्पताल पहुंचाया गया था;

(घ) क्या कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) नमूना उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला, के ढलाई गढ़ाई कारखाने के कुछ कर्मचारी लोहा पिघलाने वाली भट्ठी साफ कर रहे थे और उसकी मरम्मत कर रहे थे। एक प्रशिक्षार्थी कर्मचारियों को इस काम में मदद दे रहा था। प्रशिक्षार्थी ने उस भट्ठी के खुले दरवाजे पर पड़ा हुआ क्रो-बार हटाने के लिए भट्ठी से संलग्न स्किप हॉयस्ट के ढांचे में वेश किया। क्रो-बार हटाते हुए उसने चार्जिंग बकेट को मोड़ दिया जिससे वह उलट गया, उसका सन्तुलन बिगड़ गया और वह उसके सिर पर गिर पड़ा और उससे उसे गह ी चोट लगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) विभागीय जांच की गयी थी। कारखाना-निरीक्षक ने भी जांच की थी।

(ङ) जांच रिपोर्ट से यह पता लगा कि दुर्घटना इस कारण हुई कि प्रशिक्षार्थी स्क्रिप हॉयस्ट के नीचे इस्पात ढांचे में घुस गया था। जो निषिद्ध था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायगी?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि यह दुर्घटना पश्चिम जर्मनी से प्राप्त क्यूपोला ट्राली की डिजाइन में दोष होने के कारण हुई, और न कि पीड़ित व्यक्ति की असावधानी के कारण हुई? क्या कारखाना निरीक्षक ने इस तथ्य की जांच की है?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं। यह दुर्घटना डिजाइन के दोष के कारण नहीं हुई है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इस फाउन्ड्री का जर्मन फाउन्ड्री मास्टर दुर्घटना के दिन अनुपस्थित था? यदि हां, तो किन कारणों से वह अनुपस्थित था?

†**श्री कानूनगो** : किसी खास आदमी के अनुपस्थित रहने के बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वर्कशाप का डाइरेक्टर वहां था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस भारत-जर्मन कारखाने के शिल्पिक सहायकों या पदाधिकारियों ने जर्मन विशेषज्ञों की लापरवाही और उनके दुर्व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की है? यदि हां तो उनकी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : विकास आयुक्त ने कुछ शिकायतों की छानबीन की है । हमें बताया गया है कि इस संगठन में कुछ रद्दोबदल हुआ है ताकि और अधिक झगड़ों की कोई वजह न रहे ।

रेल व सड़क परिवहन में समन्वय

+

*६१७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री लीलाधर कटकी : }

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहिले रेल व सड़क परिवहन में समन्वय स्थापित करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) समिति का काम कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस इस्टेटमेंट में बतलाया गया है कि यह नहीं बताया जा सकता कि कब तक यह कमैटी अपनी रिपोर्ट दे देगी । मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक क्या इसका कार्य पूरा हो जायगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन**: एक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और यह संसद् सदस्यों, विभिन्न सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और अनेक दूसरी संस्थाओं को भेज दी गयी है । सर्वेक्षण अभी किये जा रहे हैं । यह एक मुश्किल समस्या है जिसमें न केवल सड़क और रेल परिवहन बल्कि अन्य प्रकार के परिवहन के सम्बन्ध में भी विचार करना होगा । हम तथ्य और आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस विवरण में यह बतलाया गया है कि अभी तक दो ही राज्य सरकारों ने अपनी सम्मतियां दी हैं । अतः क्या राज्य सरकारों के लिये कोई समय निर्धारित किया गया था और उनको कोई स्मरण पत्र इस बारे में भेजा जा रहा है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : केवल दो सरकारों, अर्थात् पश्चिम बंगाल और केरल, ने ही अभी तक अपनी सम्मतियां भेजी हैं । इस के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इस बात के लिये कार्यवाही की जा रही है कि वे शीघ्र ही अपनी सम्मतियां भेज दें ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुये कि रेलवे के सम्बन्ध में कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया जा चुका है और सड़क परिवहन केवल अनुपूरक क्षमता द्वारा ही प्रभावित होता है, क्या सरकार ने रेल और सड़क परिवहन के अनुपात पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह भी एक समस्या है जिस पर समिति विचार कर रही है। मैं अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकूंगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या जानकारी और विशेषज्ञों की कमी के कारण ही मुख्यतः यह देर हुई है और यदि हां, तो क्या विदेशो के विशेषज्ञों से सहायता लेने का सरकार का विचार है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह बात नहीं है कि जानकारी की कमी है। सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी रिपोर्टें भी आ रही हैं लेकिन इन बातो में समय लगता है और राज्य सरकारे कार्य-पालिका अधिकारी के रूप में हैं। यह भी एक कारण है।

†**श्री वेंकट सुब्बैया** : क्या कुछ राज्य सरकारों का यह विचार है कि सड़क परिवहन का राष्ट्रीय-करण किया जाये और क्या उससे इस समिति के कार्यों पर कुछ असर पड़ेगा ? रेल और सड़क परि-वहन प्रणालियों का समन्वय करने के लिये नियुक्त की गयी समिति का क्या इस ओर ध्यान दिलाया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मुझे इस बारे में मालूम नहीं है।

†**श्री कमल नयन बजाज** : क्या माननीय मंत्री ने इस बात पर विचार किया है कि गैर सरकारी सड़क परिवहन के संबंध में प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग कर हैं और इस कारण बम्बई से कलकत्ते तक परिवहन के लिये बहुत कठिनाई होती है। यदि कोई अखिल भारतीय कर लगाया जाय या कोई संग्रह या और कोई व्यवस्था की जाय, तो लम्बी दूरी के सड़क परिवहन के लिये बड़ी सुविधा होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि पिछले साल प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने के बाद समिति का काम इस लिये रुक गया था कि उसने सरकार से नीति विषयक उन मामलों पर सलाह और स्पष्टीकरण मांगा था जिनके बारे में सरकार अभी तक कोई निश्चय नहीं कर सकी है ?

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : कुछ समय पहिले परिवहन समन्वय समिति के अध्यक्ष ने अपने प्रेस वक्तव्य में यह शिकायत की थी कि इस सम्बन्ध में न केवल राज्य सरकारों को ही दिलचस्पी नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी दिलचस्पी नहीं है। क्या उनके इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हो सकता है कि कुछ विभाग जानकारी भेजने में देर कर रहे हों लेकिन वह किसी सुस्ती के कारण नहीं बल्कि जानकारी प्राप्त करने की कठिनाई के कारण है। यह ठीक है कि अध्यक्ष ने उस बारे में एक वक्तव्य दिया था लेकिन इसके लिये कार्यवाही की जा रही है कि विभिन्न विभाग रिपोर्टें शीघ्र प्रस्तुत करें।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर**: इस बात को देखते हुये कि भारत के कुछ भागों में, खासकर केरल में हजारों कर्मचारी जलमार्गों से माल भेजने-ला के काम में लगे हुये हैं, क्या जलमार्गों को भी इसमें शामिल किया जायगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैंने बताया है कि सभी प्रकार के परिवहन।

श्री बड़े : रेल रोड कोआरडिनेशन कमेटी की रिपोर्ट पर सन् १९६१ में आने के बाद अभी तक क्या इसलिये विचार नहीं हुआ है कि रेलवे ने यह आपत्ति उठाई है कि रोड से ट्रांसपोर्ट रहने से रेलवे को लास हो जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं नहीं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा है। जैसा कि आप को मालूम है, दो रिपोर्टें सरकार को पेश की गई हैं। एक मसानी रिपोर्ट थी और बाद में यह प्रारम्भिक रिपोर्ट।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय कहिये तो हम बाहर उठ कर चले जायें। किसी प्रश्न का उत्तर हिन्दी में नहीं दिया जाता। मैं इसको सहन नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। यह बहुत बुरी बात है कि कोई भी माननीय सदस्य यों खड़ा हो जाये और जो कार्यवाही हो रही है उसमें दखल दें। गवर्नमेंट को अख्तियार है कि किसको मिनिस्टर मुकर्रर करें। और जब उन्होंने मिनिस्टर साहब को रखा है और वह हिन्दी नहीं जानते तो मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता कि वह हिन्दी में जवाब दें। आहिस्ता आहिस्ता हर एक आदमी को हिन्दी सीखनी होगी और मिनिस्टर भी सीखेंगे। लेकिन इस तरह कार्रवाई में दखल देना बिल्कुल उचित नहीं है और इस पर सख्त नोटिस लिया जायगा।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट उनको मंत्री न बनाये। लेकिन मेरा कहना है कि क्या हमको यहां लाकर यूं ही बिठा दिया गया है। होना यह चाहिये कि जो प्रश्न हिन्दी में किये जायें उनके उत्तर हिन्दी में दिये जायें और जो प्रश्न अंग्रजी में किये जायें उनके उत्तर अंग्रेजी में दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वामी जी से कहूंगा कि वह अपनी जगह पर बैठें और इस सवाल को दुबारा न उठायें। मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

लघु उद्योग सेवा संस्था

†*६१८. **श्री बासप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्था के लिये एक सलाहकार समिति बनायें ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस राज्य ने ऐसी सलाहकार समितियां बनाई हैं और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख), विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों को कार्य प्रणाली की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा के लिये दूसरी लोक-सभा की प्राक्कलन समिति (१९५९-६०) ने छोटे उद्योग संबंधी ७७वीं रिपोर्ट (भाग १) में जो सिफारिशें की हैं उनके अनुसार एक समिति बनाई गयी थी। उस समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि प्रत्येक लघु उद्योग सेवा संस्था के लिये एक एक सलाहकार समिति होनी चाहिये। समिति के अन्य सुझावों के साथ साथ इस सिफारिश पर भी विचार हो रहा है।

†**श्री बासप्पा** : इस सम्बन्ध में जो खर्च होगा, क्या उसमें केन्द्रीय सरकार का कोई अंशदान होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : खर्च का कोई प्रश्न नही है । यह तो सलाहकार समितियां बनाने का प्रश्न है ।

कांच का सामान बनाने वाले कारखाने

+६१६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांच का सामान बनाने वाले कारखानों को कोयले की कमी के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन छोटे कारखानों का उत्पादन यथावत् बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सरकार को कांच का सामान बनाने वाले कुछ कारखानों के अभ्यावेदन मिले हैं कि वे कोयले की कमी के कारण अपनी पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करने में असमर्थ हैं। इस उद्योग के लिये भाप वाला कोयला की उपलब्धि का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यों तो कोयले के अभाव में सभी कारखानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि कांच के कारखाने को कुछ समय के लिए भी बन्द कर दिया जाता है, तो उस की उत्पादन-शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने जा रही है कि कोयले की अभाव-पूर्ति के सम्बन्ध में और कारखानों की अपेक्षा कांच के कारखानों को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री कानूनगो : कोयले की तो सब जगह कमी हो रही है और इस की जांच हो रही है । जब ज़रा . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या कांच के कारखानों को प्रफ़रेंस दी जायगी, क्योंकि उन की प्रोड्यूस पर असर पड़ता है ।

श्री कानूनगो : वह असर पड़ता है और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा कोयला मिले ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कांच के कारखानों में भी दो प्रकार के कारखाने हैं—बड़े और छोटे। संख्या की दृष्टि से छोटे कारखानों की संख्या अधिक है और देश में लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से छोटे कारखानों पर पहले ध्यान देना चाहिये। इसलिये क्या उन को कोयला देने में कुछ प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री कानूनगो : यह बात ध्यान में रखी जायगी । लेकिन जिन कारखानों में ज्यादा उत्पादन होता है, वहां ज्यादा और पहले ध्यान दिया जायगा ।

मद्रास राज्य में जिप्सम का कारखाना

†*६२०. **श्री सेझियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में सरकारी क्षेत्र में जिप्सम का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी पूंजी लगेगी ?

(ग) कारखाने की क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) यह कारखाना कब चालू होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मद्रास राज्य के जिला तिरुच्चिरापल्ली में सरकारी क्षेत्र में जिप्सम कारखाना खोलने का कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सेझियान** : तिरुच्चिरापल्ली जिले से प्राप्त जिप्सम के बारे में प्रयोग शाला में किये गये प्रयोगों का क्या परिणाम रहा ?

†**श्री कानूनगो** : इस परियोजना में गैर-सरकारी व्यक्ति दिलचस्पी रखते हैं । परन्तु प्रश्न यह था कि क्या सरकारी क्षेत्र में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सेझियान** : मैं प्रयोगशाला के प्रयोगों के परिणाम जानना चाहता हूं ।

†**श्री कानूनगो** : यह कार्य गैर-सरकारी तौर पर किया गया है ।

†**श्री उमानाथ** : खोजों के परिणामों के फलस्वरूप जिप्सम के ऐसे निक्षेपों का पता लगने पर, जिन से जिप्सम निकाला जा सके, सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वे कठिनाइयां क्या हैं जो सरका ी क्षेत्र के एक कारखाने द्वारा इन निक्षेपों से वाणिज्यिक लाभ उठाने में बाधा डालती हैं ?

†**श्री कानूनगो** : इसे उच्च प्राथमिकता नहीं मिली है, क्योंकि अन्तिम उत्पाद ही भवन निर्माण के लिये प्रयोग होगा । उच्च प्राथमिकता के अन्य उद्योग हैं जिन के लिये योजना में उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या किसी गैर-सरकारी पार्टी ने सरकार से तिरुच्चिरापल्ली में जिप्सम का कारखाना खोलने के लिये लाइसेन्स मांगा है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रार्थना पत्र आये हैं ?

लंका से निष्कासित भारतीय राष्ट्रजन

+

†*६२३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री सेझियान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस सालों में लंका से कितने भारतीय राष्ट्रजन निष्कासित किये गये हैं ;

(ख) उन में कितने केरल राज्य के और कितने मद्रास राज्य के हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई कार्यवाही की ह ; और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) पिछले दस वर्षों में लंका से निकाले गये भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या निम्न है :—

(१) निष्कासित अवैध आप्रवासी . . . २५,८३१ और

(२) जो व्यक्ति देश छोड़-जाओ सूचना पा कर चले आये . ४६,११४

इन के अतिरिक्त ४८,४५४ भारतीय देश-छोड़-जाओ सूचना मिलने से पहिले ही स्वेच्छा से चले आये ।

(ख) लंका से निष्कासित व्यक्तियों के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) और (घ). इन व्यक्तियों के पुनर्वास के उपायों के बारे में भारत सरकार मद्रास सरकार से निरन्तर वार्ता कर रही है । राज्य सरकार ने निकाले गये व्यक्तियों को विभिन्न सुविधायें दी हैं । इस के अतिरिक्त योजना आयोग मद्रास राज्य के थतजवर, रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली जिलों को राज्य सरकार के परामर्श से निवास के लिये कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित करता रहा है । एसा इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि उन लोगों को रोजगार दिया जाय जो अन्यथा अवैध अप्रवासी के रूप में लंका जाना चाहते हैं । इस के अलावा, नजरेठ में एक कताई कारखाना खोलने के लिये भारत सरकार ने मद्रास राज्य को दस लाख रु० का ऋण दिया है । आशा है कि कारखाने में इस वर्ष के मध्य में उत्पादन आरम्भ हो जायगा । संघ लोक सेवा आयोग की योग्यता परीक्षाओं में लंका के प्रत्यावासियों को आयु में छूट दी जाती है । उन के साथ भारत वापिस आने पर अपना पुनर्वास करने में सहायता देने के लिये अपने निजी सामान का आयात करने के लिये बहुत ही उदारता का व्यवहार किया जाता है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : कहा गया है कि इन व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में भारत सरकार मद्रास सरकार से परामर्श कर रही है । इन व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में केरल सरकार से परामर्श न करने के क्या कारण हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : लंका से आने वाले प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिये केरल सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; इस की कोई रिपोर्ट न मिलने के कारण उनसे परामर्श नहीं किया गया है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या केरल के, विशेष कर नटिका परका के लोगों का कोई अभ्यावेदन आया है जहां हजारों लोगों को 'देश छोड़ जाओ' का नोटिस दिया गया है और वे वहां पिछले दो वर्षों से रह रहे हैं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं जानती कि कोई अभ्यावेदन आया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं सरकार का ध्यान २६ अप्रैल को 'हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव' में लंका सरकार के वित्त मंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि लंका सरकार उस समय तक भारतीयों को वापस भेजने के लिये कुछ नहीं कर सकती जब तक कि दोनों सरकारों के बीच समूचे प्रश्न पर बातचीत न हो जाय । यदि हां, तो सरकार इस समस्या को निमटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि हमारे व्यक्तियों को परेशानी और कठिनाई में न डाला जाय ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** व्यक्तियों के अनेक वर्ग हैं। माननीय सदस्य ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिन्हें राष्ट्रहीन कहा जाता है क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं और उन्हें लंका का भी राष्ट्रजन नहीं माना जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस का मेरे साथी के उत्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह उत्तर तो अवैध आप्रवासियों के बारे में है । फिर, वे लोग हैं जिन के प्रवेशपत्र की अवधि समाप्त हो गई है, अर्थात् भारतीय राष्ट्रजन । उन्हें एक निश्चित तारीख तक चले जाने के नोटिस मिले हैं । एक तीसरा वर्ग और है जिसे राष्ट्रहीन कहा जाता है और उनकी संख्या लाखों में है । उन्हें देश छोड़ने के नोटिस नहीं मिले हैं । फिर भी, राष्ट्रहीन लोगों के बारे में लंका सरकार से हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है ।

†**श्री नम्बियार** : माननीय मंत्री ने कहा है कि जो लोग मद्रास आये हैं उन्हें पुनः बसाने के लिये कार्यवाही की जाती है । नजरेठ में एक सहकारी मिल खोलने के प्रस्ताव के अतिरिक्त, मद्रास सरकार ने केन्द्र के परामर्श से क्या अन्य कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सात, आठ उपाय हैं जिन से इन लोगों को पुनः बसाने में सहायता मिलेगी । इन में निम्न उपाय सम्मिलित हैं मैसूर राज्य में मालनाद क्षेत्र में काफी के बागों में लंका के प्रत्यावर्ती व्यक्तियों को काम पर लगाना, जहां-कहीं संभव हो इन लोगों के लिये थजांवर जिले में ऐसे क्षेत्र आरक्षित करना जो नारियल उगाने के लिये उपयुक्त हों, सेतुसन्दरम परियोजना का विकास, सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं का विकास, आदि । ये अवैध आप्रवासी जिन क्षेत्रों से आते हैं, वे सूख क्षेत्र हैं और वहां पानी का अभाव है । अतः लाभप्रद खेती नहीं की जा सकती । रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली क्षेत्रों में सड़कों का विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना में और विद्युत् शक्ति का विस्तार परियोजना विचाराधीन हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार मद्रास राज्य और शायद केरल राज्य पर निर्भर करना चाहती है । सरकार इसे केन्द्रीय जिम्मेदारी क्यों नहीं मानती और उन्हें अन्दमान द्वीपसमूह में या अन्य द्वीपसमूह में क्यों नहीं बसाती जहां नारियल और रबड़ उगाने की काफी गुंजाइश है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कार्यवाही करने के लिये यह एक सुझाव है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या मैं यह बता दूं कि ये लोग जो वापस भेजे गये हैं, सब भारतीय राष्ट्रजन हैं । ये लोग प्रवेशपत्र ले कर या अवैध रूप से वहां गये थे । यद्यपि संख्या काफी बड़ी है फिर भी काफी लोग आते जाते हैं । देश-छोड़-जाओ नोटिसों के अलावा वे आते हैं और चले जाते हैं । ऐसे लोगों को प्रत्यावर्तन अनुदान, सहायता, आदि देने की अनिवार्य रूप से कोई आवश्यकता नहीं है जो व्यापार करते हैं या अन्य व्यवसायों में लगे हैं । दूसरों के लिए निश्चय ही इसकी आवश्यकता है और इस कारण कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री त्यागी** : आजकल लंका में भारतीय उद्भव के राष्ट्रहीन लगभग कितने व्यक्ति हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का सम्बन्ध राष्ट्रहीन व्यक्तियों से नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : लंका के वित्त मंत्री ने "बसे हुए भारतीय" शब्द प्रयोग किये थे । क्या इन शब्दों से वहां पर केवल राष्ट्रहीन व्यक्तियों से ही अभिप्राय है या अभिप्राय इस समूची समस्या से है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उनके वास्तविक वक्तव्य को देखे बिना इसका उत्तर नहीं दे सकता । मैं इसकी विवेचना नहीं कर सकता । साधारणतया भारत और लंका के बीच प्रश्न राष्ट्रहीन व्यक्तियों का है । उन्हें हमारी भांति पूर्णाधिकार है कि वे विदेशियों को प्रवेशपत्र न दें । हम इसका विरोध नहीं कर सकते । हम केवल यह कह सकते हैं कि जब तुम उन्हें प्रवेशपत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

देते हो, तो उन्हें अपना सामान वापस ले जाने का मौका दो। अतः जो लोग वहां से लौट रहे हैं, वे वास्तव में निकाले हुए नहीं हैं। यदि वे निकाले हुए होते हैं तो उन्हें अपने सामान सहित वापस जाने को कहा जाता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि केरल सरकार ने पिछले दस वर्ष से इन बसने वालों के बारे में जो निकाले हुए व्यक्ति हैं, केन्द्रीय सरकार से कभी प्रार्थना नहीं की है? यदि हां, तो इसी कारण केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या पर विचार नहीं किया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : स्पष्ट है कि मैं यह उत्तर नहीं दे सकता कि पिछले दस वर्ष में क्या हुआ। संभवतः, कुछ हुआ हो। मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु भारतीयों के वापस आने में वृद्धि मुख्य कर पिछले दो तीन सालों में हुई है। परन्तु केरल से जाने वाले अनेक व्यक्ति खुशहाल हैं। वस्तुतः, वे वहां प्रायः महाजनी करते हैं। (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

सामाजिक-आर्थिक विषयों का अनुसंधान

†*६२६. { + **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सामाजिक-आर्थिक विषयों का मोटे तौर पर वर्गीकरण करने वाली सूची, जिनका अनुसन्धान तीसरी योजना अवधि में योजना आयोग द्वारा करवाया जाना है, अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी?

†**योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से पता लगता है कि आजकल योजना आयोग के अधीन ४० अनुसन्धान परियोजनायें हैं। इनमें से प्रत्येक की पूर्ति की लक्ष्य तारीख क्या है और यदि वे पूरी नहीं हैं, तो क्या ये सब योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायेंगी?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : ऐसी कोई निर्धारित तारीख नहीं है। केवल अध्ययन का काम है और आशा है कि यह पूरा हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन परियोजनाओं की पूर्ति के लिए योजना आयोग अपने ही संसाधनों पर निर्भर करता है या यह इस कार्य के लिए विश्वविद्यालयों का प्रयोग भी कर सकता है और, यदि हां, तो किन विश्वविद्यालयों का प्रयोग करेगा?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह जानकारी केवल विश्वविद्यालयों को ही नहीं अपितु अनुसन्धान संघों तथा संस्थाओं को भी भेजी गई थी और हम आंकड़े तथा जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अनुसन्धान कार्य विभिन्न केन्द्रों में होता है और, यदि हां, तो अनुसन्धान कार्य का समन्वय करने के लिए क्या एजेन्सी है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्र बनाने के लिए एक **सर्वेक्षण** की योजना का यह एक भाग है। अध्ययन विभिन्न केन्द्रों के प्रसंग से किया जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत भर के लोगों की चिन्ता की एक समस्या यह है कि योजना से प्राप्त लाभ जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में कैसे बांटे गये हैं। क्या योजना आयोग ने इसका पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन किया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : अध्ययन का रूप ही यह है कि जनता पर आयोजन प्रोग्रामों के प्रभाव का पता लगाया जाये।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या योजना आयोग के तत्वावधान में हुए अनुसन्धानों की रिपोर्टें प्रकाशित हो गई हैं और क्या वे पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हां, दो रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। पहिली पहिले योजना-काल के लिए है और दूसरी दूसरे योजना-काल के लिए है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का उल्लेख होता है।

शाहजहां रोड (नई दिल्ली) के समीप क्वार्टरों का निर्माण

†*६२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० पी० एस० सी० (संघ लोक सेवा आयोग) की इमारत के सामने शाहजहां रोड, नई दिल्ली में सी-२ किस्म के क्वार्टर बनाये जायेंगे, जब कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के नये क्वार्टर केन्द्रीय सचिवालय से ६ मील से अधिक दूरी पर बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उच्च वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों के स्थान पर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर केन्द्रीय सचिवालय क्षेत्र के समीपस्थ उपलब्ध स्थानों पर क्यों नहीं बनाये जाते ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) और (ख). शाहजहां रोड पर उपलब्ध स्थान को उच्च श्रेणी के, अर्थात् डी-२ और सी-२ श्रेणी के फ्लेट बनाने के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है। केन्द्रीय सचिवालय के पास क्वार्टर बनाने के लिए शायद ही कोई भूमि उपलब्ध हो। जब कभी कोई भूमि उपलब्ध होती है तो उस किस्म के मकान, जो वास्तु-कला, मितव्ययता, सुविधा, आदि बातों को ध्यान में रख कर वहां उपयुक्त हों, बनाये जाते हैं। अब केन्द्रीय सचिवालय के पास उपलब्ध सभी जमीनों पर इमारतें बन गई हैं, इसलिये क्वार्टर कुछ दूर बनाये जा रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि सी-२ श्रेणी के फ्लेटों के अधिकारी उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों में से अधिकतर के पास अपनी कारें हैं और उन्हें सवारी भता मिलता है, जबकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कोई सवारी-भता नहीं दिया जाता ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : मकानों के निर्माण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका अभिप्राय है कि उच्च पदाधिकारियों को अन्य सुविधायें हैं और वे दूर रह सकते हैं, परन्तु कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दफ्तर आने में परेशानी होती है । अतः उनका अर्थ है कि उनका आवास सचिवालय के पास हो ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: जहां तक प्रश्न के सामान्य पहलू का सम्बन्ध है, हमें कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों, अर्थात् तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ पूरी सहानुभूति है । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मौखिक सहानुभूति है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आजकल हमारी मुख्य कठिनाई यह है कि दिल्ली के आस पास चहुंओर मकान, आदि बन गये हैं । भारत सरकार ही नहीं अपितु दिल्ली भी बहुत तेजी से बढ़ रही है । प्रति वर्ष दिल्ली में अनेक व्यक्ति आते हैं । स्वाभाविक है कि हम दूर जायें । इसका कोई उपाय नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : प्रश्न यह है कि निर्माण की योजना बनाते समय कम वेतन पाने वालों के लिए दूर के स्थानों की अपेक्षा, जहां उनके लिए मकान बनाये गये हैं शाहजहां रोड जैसे पास के स्थानों पर या केन्द्रीय सचिवालय के पास अन्य स्थानों पर मकान बनाने की योजना क्यों नहीं बनाई गई थी ? आयोजनावस्था में इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह सब कहना ठीक नहीं है । कम वेतन पाने वालों के लिए कुछ अमुक प्रकार के मकान राउज एवेन्यु, मिन्टो रोड, पंच कुइंया रोड, आदि पर बने हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : वे पहिले बने ; अब नहीं बने । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह सब जोश क्यों है ? ये क्वार्टर विद्यमान हैं । हमारी योजना यह है कि यथासंभव इन लोगों को, दिल्ली के लिए बनाई गई योजना के नमूने में साधारण विन्यास के अनुसार वहां रहने दिया जाये । मैं कह सकता हूं कि पंच कुइंया रोड पर १००० क्वार्टर चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के हैं । हमने योजना बनाई है और हम उन्हें वहां क्वार्टर देंगे । यदि कोई जमीन उपलब्ध होती है तो हम उसका चौथी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, दूसरी श्रेणी और पहिली श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रयोग करेंगे । हमारी यह इच्छा नहीं है कि इन लोगों को वहां से हटाया जाये जहां वे रह रहे हैं और अन्य लोगों को वहां बसाया जाये ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या नीति यह है कि वेतन जितना अधिक हो, दफ्तर से उतना ही पास, और वेतन जितना कम हो, दफ्तर से उतनी ही दूर मकान मिले ? (**अन्तर्बाधा**) क्या इसे समाजवादी ढंग के समाज के विरुद्ध समझा जाता है और क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करेगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह नीति मंत्रियों पर लागू होती है । मैं भी उनमें से एक हूं । ये बंगले बहुत पहिले बने थे । ये बंगले थे और जब वे दिये गये तो स्वाभाविक है कि वे अधिकारियों तथा अन्य लोगों को दिये गये । मुख्य विचार यह है कि मैं नहीं चाहता कि चौथी श्रेणी के हमारे मित्र दिल्ली से दूर के क्षेत्रों में रहें और यह सब दूरी चलकर आयें । परन्तु इसका कोई उपाय नहीं है । आज मेरे पास ६०,००० मकानों की कमी है और इनमें से कुछ लोगों को मकान पाने का

---

†मूल अंग्रेजी में

इन्तजार करते हुए १५ वर्ष हो गये। यदि ६०,००० मकान बनाये जायें तो केवल अछूते क्षेत्रों में ही बनाये जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जिनका विकास करना होगा और वे क्षेत्र दिल्ली से कुछ दूर हैं। वे दिल्ली के मध्य में नहीं हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : पिछले एक वर्ष में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बने हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा ख्याल हैकि मैं माननीय सदस्य को कोई जानकारी नहीं दे सकता। मैं केवल यह कह सकता हूं कि रामकृष्णपुरम में ४,००० क्वार्टर लगभग पूरे हो गये हैं। उनमें सब श्रेणी के क्वार्टर हैं और हमारा विचार एक या दो महीने में उन्हें देने का है। कठिनाई यह थी कि पानी नहीं मिल पाया था, नाली, आदि की व्यवस्था नहीं हुई थी। अब यह कठिनाई दूर हो गई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विलिंगडन क्रसेन्ट की एक ओर खाली पड़ी बड़ी जमीन के बारे में, जो किचनर रोड की दूसरी ओर तक फैली हुई है, क्या योजना है? क्या इसका प्रयोग केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों के लिए किया जायेगा या यहां तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी बसाये जायेंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि प्रश्न पूछा जाये और मैं दिल्ली की वृत्त योजना को देखूं, तो मैं प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि क्वार्टरों की कमी के कारण तीसरी और चौथी श्रेणी के ६२,००० कर्मचारी प्रतीक्षक सूची में हैं और क्या यह भी सच है कि अधिकतर सरकारी क्वार्टरों में गैर-सरकारी लोग, जैसे भारत सेवक समाज के लोग रहते हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह कहना ठीक नहीं है कि अधिकतर क्वार्टरों में गैर-सरकारी व्यक्ति रहते हैं। परन्तु यदि प्रश्न पूछा जाये कि क्या कुछ क्वार्टरों में गैर-सरकारी व्यक्ति रहते हैं, तो मैं शायद कहूंगा कि हां रहते हैं। द्वितीय, मैं सभा को बता दूं कि मैं स्वयं इन सब मामलों की जांच कर रहा हूं और जहां कहीं मुझे पता लगेगा कि रहने वाला रहने का अधिकारी नहीं है, वह वहां नहीं रहना चाहिये, तो उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इनमें से कुछ लोग वर्षों से रह रहे हैं और उन सबको निकालना ठीक न होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। डा० लक्ष्मीमल्ला सिंघवी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ६३८ भी इस के साथ लें लिया जाये।

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : यदि आप कहें, तो उसका भी साथ ही उतर दिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, प्रश्न ६२८ और ६३८ का उत्तर एक साथ दिया जाये।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय

†*६२८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पाकिस्तानी जेलों में कितने भारतीय बन्द हैं और किन अपराधों के लिये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत सरकार ने ऐसे मामलों में कोई कानूनी सहायता प्रदान की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) लगभग १०० भारतीय राष्ट्रजनों पर निम्न अपराधों के लिये या तो मुकद्दमे चल रहे हैं या वे कारावास का दंड भोग रहे हैं, अवैध प्रवेश, तस्कर व्यापार, दूसरा नाम रख कर नकली पारपत्रों पर यात्रा करना, अवैध शस्त्रास्त्र रखना या जासूसी करना ।

(ख) पाकिस्तान सरकार, उन के द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय राष्ट्रजनों के बारे मे, उन पर मुकद्दमा चलाये जाने की प्रारंभिक अवस्था में सूचना नहीं देती । अधिकांश मामलों में सूचना तब ही दी जाती है जब पाकिस्तनी न्यायालय से किसी भारतीय राष्ट्रजन को दंड मिल चुकता है । इन परिस्थितियों में सामान्य कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती ।

कर्नल भट्टाचार्य

†*६३८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दण्ड के विरोध में कर्नल भट्टाचार्य ने अभी तक कोई अपील दायर नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को तसल्ली है कि कर्नल भट्टाचार्य को अपील के लिये वित्तीय तथा कानूनी सहायता की कमी नहीं है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, नहीं । हमारी सूचना यह है कि लैफ्टीनेंट कर्नल भट्टाचार्य ने १९ अप्रैल को पाकिस्तानी विशेष सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा उसको दंड दिये जाने के विरुद्ध अपील की है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**डा० ल० म० सिंघवी** : क्या सरकर को ऐसे मामलों की सूचना मिली है जिनमें राजनीतिक कारणों पर राजनीतिक प्रयोजनों के लिये पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रजनों के विरुद्ध राजनीतिक अभियोग चलाये जा रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं मूल उत्तर में बता चुकी हूं कि वे किन कारणों से वहां रोक लिये गये थे ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीयों को सीमा से अपहृत किया जाता है हालांकि वे हमारी सीमा के अन्दर होते हैं, जैसे लै० कर्नल० भट्टाचार्य का अपहरण किया गया

†मूल अंग्रेजी में

का अपहरण किया गया था, क्या उन सब पर अभियोग चलाये गये हैं और रिहा नहीं किया गया है या उन में से कुछ को 'लिक्विडेट' किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं, किसी को 'लिक्विडेट' नहीं किया गया। जब हमें इन बातों की सूचना मिलती है तो हम इस मामले को या तो राज्य सरकार की मार्फत या हमारे उच्च-आयुक्त की मार्फत पूर्वी पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : मा० मन्त्री ने बताया है कि वहां जो लोग कारखानों में हैं उनमें से कुछ लोग जासूसी के आरोप पर कैदी बनाये गये हैं उनकी संख्या कितनी है और क्या उस राज्य को सूचना देने की अन्तर्राष्ट्रीय विधि को सामान्य प्रथा का जिस राज्य के नागरिक जासूसी के दोष में कैदी बनाये गये हों, उनके मामलों में पाकिस्तान में पालन किया था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मेरे पास उन लोगों के सही आंकड़े नहीं हैं, जिन्हें जासूसी के आरोप में दण्ड दिया गया है, केवल कर्नल भट्टाचार्य का एक मामला है, जिसमें भी यह सिद्ध हुआ था कि उसे जासूसी के लिये दण्ड नहीं दिया गया था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछ रही हूं। अब जबकि कर्नल भट्टाचार्य को जासूसी के आरोप से मुक्त किया जा चुका है, क्या सरकार इस मामले को उच्च स्तर पर उठा रही है, जैसा कि विधि मन्त्री ने दिसम्बर, १९६१ में प्रतिज्ञा की थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार ने विविध तरीकों से उसकी सहायता की है। अब उन्होंने अपने दण्ड के विरुद्ध अपील की है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार क्या कर सकती है। वास्तव में, यदि सरकार सीधे इस मामले को उठाये तो उससे उसकी अपील पर अच्छी तरह विचार किये जाने के अवसर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी अपील विधिगत अधिकारों पर नहीं, बल्कि अन्य आधारों पर है। सरकार उसकी सहायता कर रही है। उसके अतिरिक्त, यह बात स्पष्ट नहीं है कि इस समय हम क्या कर सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि उन छः व्यक्तियों में से, जो जेल में बन्द हैं, पांच व्यक्ति मछवे हैं जो भारत की भूमि से उठा लिये गये थे और कर्नल भट्टाचार्य के अतिरिक्त, श्री परितोष दास भी वहां हैं, जिसका अपहरण अभी हाल में किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जबतक मुझे उन व्यक्तियों के नाम मालूम न हों, इस प्रश्न का ठीक उत्तर देना मेरे लिये कठिन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं पांच मछवों का उल्लेख कर रहा हूं, मुझे उनके नामों का पता नहीं है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मेरे पास यहां उन सब लोगों की सूची है जो गिरफ्तार किये गये थे और जेल में डाले गये तथा दण्ड की अवधि भी है। क्योंकि सूची में यह लिखा है "अन्य देश में कारावास में एक देश के व्यक्ति" और यदि मुझे नाम पता हो तो मैं आसानी से सूचना दे सकती हूं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या हमारी सरकार उन लोगों को कोई सहायता देती है जो जासूसी के आरोपों पर गिरफ्तार किये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार उन लोगों को किस प्रकार की सहायता दे सकती है, जो गिरफ्तार किये जाते हैं और दण्ड दिये जाने पर पाकिस्तानी जेलों में रखे जाते हैं ।

माप की मीट्रिक प्रणाली

†६२९. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सरकारी विभागों ने अभी तक माप की मीट्रिक प्रणाली नहीं अपनायी है ;

(ख) क्या इससे व्यापार तथा उद्योग की कई शाखाओं में जहां से सरकारी आर्डरों की सप्लाई होती है, भ्रम पैदा हो रहा है ; और

(ग) क्या इस बात के लिये कदम उठाये जायेंगे कि अन्तर्सम्बन्धित कच्चे माल और तैयार मुद्रा उत्पादों के मूल्य माप की एक ही प्रणाली में बताये जायें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सब बड़े सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों, विशेषकर रेलवे, डाक व तार सीमा शुल्क तथा आबकारी विभाग, और आयात तथा निर्यात नियन्त्रण ने, जिनका सार्वजनिक व्यापार और उद्योग से सम्बन्ध पड़ता है, अपने सौदों में मीट्रिक प्रणाली अपनाई है । ऐसे सौदों में, मात्रा और मूल्य आम तौर पर मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त किये जाते हैं । इंजीनियरी विभागों में, विविध वस्तुओं के डिजाइन में और सामान के विशिष्ट ब्योरों में, मीट्रिक प्रणाली पूर्णतया नहीं अपनाई गई, और उसमें समय लगना अवश्यम्भावी है । यहां भी, स्थायी प्रगति की जा रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मा० मन्त्री को पता है कि रेलवे तथा सम्भरण और उत्सर्जन महा निदेशालय इंचों में ही कुंडियों और पेचों के आर्डर देते हैं, मिलीमीटरों में नहीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह सच है, क्योंकि कुछ उद्योग हैं, जो उस पर अब भी आग्रह करते हैं कि किन्तु अधिकतर औद्योगिक इकाइयां मीट्रिक प्रणाली को अपना रही हैं । आगामी कुछ वर्षों में कुछ अतिच्छादन होना अवश्यम्भावी है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मा० मन्त्री को पता है कि निर्माताओं को कच्चा माल मीट्रिक प्रणाली में दिया जाता है जबकि आर्डर पुरानी प्रणाली में दिये गये हैं और इससे बहुत अधिक गड़बड़ी हो रहीहै?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने इस उद्योग को इंचों में इस्पात की चीजें बनाने की हिदायतें जारी की हैं जहां उद्योग और व्यापार के लिये जरूरी हो । क्योंकि, जैसा कि सभा स्वीकार करेगी, पुरानी मशीनें हैं जो इंच प्रणाली में बनी हुई हैं । उनके लिये, इस्पात को इंच प्रणाली में तैयार करना पड़ेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार जानती है या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि जब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा था, यही सवाल उठा कि इंचों और मीट्रिक प्रणाली में गड़बड़ी होगी और उस समय भी इस बात पर आग्रह किया गया था कि यह मीट्रिक प्रणाली में हो, इंचों में नहीं ? अब आप दुर्गापुर में इंचों से मीट्रिक प्रणाली में कैसे बदलने का विचार करते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सब पूर्वोपाय किये गये हैं और वेलन सेक्शन में विविध किस्मों के गैजट लगाये गये हैं । वास्तव में, अधिकतर उत्पादन मीट्रिक प्रणाली में है । और केवल शेष इंच प्रणाली

---

†मूल अंग्रेजी में

में होता है। जब तक पुरानी मशीनें हैं जो इंच प्रणाली का उपयोग कर रही हैं, हम उनको यह नहीं कह सकते कि इंचों में वेतन बिल्कुल नहीं होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सही है कि विदेशों से जो आर्डर आते हैं वे केवल इंचों में होते हैं और इससे भी कुछ गड़बड़ी होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ देश हैं जो केवल मीट्रिक प्रणाली अपनाते हैं और कुछ इंच प्रणाली। परसों ही इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के कुछ लोग मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि उन को कुछ देशों के लिये विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि केवल इंच प्रणाली को अपनाते हैं। इसलिये हमें इंच और मीट्रिक दोनों प्रणालियों को अपने वैदेशिक व्यापार के लिये रखना होगा। किन्तु हमारे आन्तरिक व्यापार में हम मीट्रिक प्रणाली को अपना रहे हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

†*६३०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये अन्तिम रूप से व्यय कितना होगा ;

(ख) क्या इन आंकड़ों में योजना-अवधि में होने वाली लागत में आकस्मिक वृद्धि के लिये पर्याप्त उपबन्ध कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन आंकड़ों के अन्तर्गत योजना में विस्तार करने तथा कमी करने की गुंजाइश कहां तक रहेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** (क) अन्तिम रूप में तैयार, तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में ७५०० करोड़ रुपये के परिणाम तथा गैर सरकारी क्षेत्र में ४१०० करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था है।

(ख) वित्तीय व्यवस्था, तीसरी योजना जिस समय बनाई गई थी उस समय की लागत के प्राक्कलनों के अनुसार है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या यह उपबन्ध दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हमारे अनुभव के आधार पर किया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** निश्चय ही।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या इन आंकड़ों में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों की प्रत्याशित वृद्धि का उपबन्ध किया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** जी नहीं। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय के आंकड़ों पर निर्धारित हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** इस बात की दृष्टि से कि हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी हालत गिर रही है और लड़खड़ा रही है—जिसके बारे में मैंने आज के समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि सरकार के पास अब धन अपर्याप्त होगा—क्या पूंजी माल के रूप में सब आवश्यकतायें प्राप्त करने के प्रश्न को, यह व्यवस्था करते समय, ध्यान में रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वे० रा० पट्टाभिरामन : यह सर्वथा सच है । विदेशी मुद्रा की हालत के कारण कुछ अन्तर हो सकता है। किन्तु उससे अधिक मैं अब कुछ नहीं कह सकता।

†श्री मुरारका : क्या योजना आयोग ने तीसरी योजना के महत्वपूर्ण अंगों का भी निश्चय कर लिया है, जैसा उन्होंने दूसरी योजना के बारे में किया, या क्या वे सब साधन जुटाने में किसी कठिनाई की अपेक्षा नहीं करते ?

†श्री वे० रा० पट्टाभिरामन : कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण अंग बाद में ही निर्धारित किये जा सकते हैं। प्रा भ में नहीं।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : हमारे पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सी परि-योजनाओं के प्राक्कलन बढ़ जाते हैं, क्या ११,५०० करोड़ रुपयों का उपबन्ध बढ़ेगा या कुछ परि-योजनाओं में कमी की जायगी ?

†श्री वे० रा० पट्टाभिरामन : एक या दो के मामले में यह बढ़ सकता है, किन्तु यह घट भी सकता है। हो सकता है कि यह कम भी हो जाय।

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म

†*६३१. श्री सिद्दय्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में एक फिल्म तैयार करने की योजना कई वर्षों से चली आ रही है ;

(ख) क्या फिल्म का निर्माण पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) से (ग). अस्पृश्यता निवारण के लिये एक फीचर फिल्म तैयार करने का काम सितम्बर, १९६० से लम्बित पड़ा है, जब इसके बारेमें निर्माता से संविदा किया गया था। निर्माण में विलम्ब का कारण यह है कि निर्माता को एक संशोधन लेख पेश करना था और उस ने इस महीने के मध्य तक समय को बढ़ाने के लिये कहा है। वह सरकार की ओर से दूसरी फिल्म पूरी करने में व्यवस्त था।

इस विषय पर दो छोटी फिल्में पूरी की जा चुकी हैं और तीन दूसरी छोटी फिल्में बनाई जा रही हैं।

†श्री सिद्दय्या : योजना की अनुमानित लागत क्या है और अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : फिल्म निर्माण करने की लागत लगभग २ लाख रुपये है। हम ने अभी निर्माता को केवल १५,००० रुपये का ऋण दिया है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह फिल्म परियोजना इस कारण आरम्भ की गई है कि इस देश में अस्पृश्यता निवारण विधि होने के छः वर्षों बाद की, सरकार समझती है कि विविध राज्यों में इस सम्बन्धी काम बड़ा असन्तोषजनक रहा है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : यह सन्तोषजनक है या नहीं यह भिन्न बात है। हम सब राज्यों में दिखाई जाने वाली अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चलचित्र चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री थिरुमल राव :** क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि अस्पृश्यता की भद्दी और आपत्तिजनक बातें इस फिल्म में नहीं दिखाई जायेंगी, जिस से इस का उस से विपरीत प्रभाव पड़े, जो हम करना चाहते हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हम निर्माता से संशोधित लेख प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार को ऐसी योजना है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकाधिक चलचित्र बनाने के लिये गैरसरकारी निर्माताओं को कोई प्रोत्साहन दिया जाय, उन को कोई अर्थ-सहायता, ऋण या मनोरंजन शुल्क से छूट आदि दी जाय ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** कुछ चलचित्र गैर-सरकारी निर्माताओं को दिये गये हैं। देवकी बोस ने दो लाख प्रलेख चलचित्र तैयार कर लिये हैं और तीन बनाये जा रहे हैं।

†**श्री कमल नयन बजाज :** भारत सरकार के तत्वावधान में बनाये जाने वाले चलचित्रों को क्या सरकार स्कूलों और कालेजों में निश्शुल्क दिखाने का प्रबन्ध करेगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** सुझाव पर विचार किया जायेगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** निर्माताओं से संशोधित लेख मांगने के क्या कारण थे और इस चलचित्र के निर्माण में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मूल लेख सन्तोषजनक नहीं था और सरकार ने निदेश दिया कि निर्माता संशोधित लेख दे।

†**श्री नंबियार :** क्या उस चलचित्र में अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों तथा गैर अनुसूचित जातियों के लड़कों तथा लड़कियों के बीच अन्तर्जातीय विवाहों के दृश्य होंगे ? क्या वह फिल्म का अंग होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सूचना देनी है। अगला प्रश्न।

राज्य व्यापार निगम

†*६३२. **श्री महेश्वर नायक :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता चलाया है कि किन कारणों से राज्य व्यापार निगम बहुत थोड़ा ही लाभ कमा सका है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ग) निगम की गतिविधियों की विभिन्न शाखायें क्या हैं ; और

(घ) इस की गतिविधियों का विस्तार करने का यदि कोई विचार है तो किस प्रकार ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कुल व्यापार में वृद्धि के बावजूद लाभ में कमी के कई कारण हैं। उन में से महत्वपूर्ण ये हैं :—

(१) कुछ क्षेत्रों में अयस्क के समाहार की ऊंची लागत, जिस में सड़क का परिवहन होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) मैंगनीज़ अयस्क के ऊंचे दामों वाले स्टाक को निकालना ।

(३). पत्तन के किरायों में वृद्धि

(४) मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को नाममात्र लाभ पर बड़ा संभरण ।

(५) विभिन्न संयुक्त विपणन व्यवस्थाओं के अधीन निगम को अनुदेय लाभ में कमी ।

(६) निर्यात संवर्धन की दृष्टि से लाभों में सामान्य कमी ।

(७) निर्यात अर्थात् सीमेंट में हानि को सहायता दे कर पूरा करना ।

(ग) निगम ने लोहा अयस्क, मैंगनीज़ अयस्क, क्रोम अयस्क, नमक, सीमेंट, तम्बाकू, ऊनी कपड़े, जूते, कहवा, मसूर की दाल,पटसन का सामान आदि समेत लगभग ३६ वस्तुओं का निर्यात सीधे तौर पर किया है। रसायन, हल्का इंजीनियरी सामान आदि कुछ वस्तुएं विकास मान वस्तुओं के रूप में हैं, जिन के लिये विदेशों में बाजार ढूंढने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

आयात के सम्बन्ध में निगम ने अत्यावश्यक कच्चे माल, और पूंजी माल, अर्थात् अलौह धातु, विविध रसायनों और उर्वरकों अर्थात् सोडा कास्टिक, सोडा ऐश, अमोनियम सल्फेट, कच्चा रेशम, नकली रेशमी धागा, अखबारी कागज और कपड़ा मशीनरी आदि, के आयात में सहायता की है ।

निगम सीमेंट, लोहा अयस्क, और सौफ्ट कोक जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिये उचित दामों पर, आन्तरिक वितरण भी करता है ।

(घ) इस प्रश्न पर सरकार लगातार विचार करती रही है और अधिक जोर निर्यात के संवर्धन पर होगा ।

†**श्री महेश्वर नायक :** विवरण में उल्लिखित बातें न्यूनाधिक रूप में अन्य व्यापार अभिकरणों में भी विद्यमान हैं। क्या राजकीय व्यापार निगम में लाभों में कमी का कारण यह है कि निगम में ऊपर का खर्च अन्य व्यापारी अभिकरणों की तुलना में बहुत अधिक है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** बात यह नहीं । वास्तव में, ध्यान विदेश व्यापार तथा निर्यात की ओर अधिक है, जो साधारणतया विक्रेता बाजार में मूल्यों की दृष्टि से कम है । इसलिये वहां की हानि अन्य अभिकरणों में कमाये गये लाभ से पूरी करनी पड़ती है । इसलिये कुल मिला कर, हालांकि योग उत्पादन की तुलना में बढ़ गया है, किन्तु उस अनुपात में लाभ नहीं बढ़े हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक :** निर्यात और आयात के मामले में देश के अन्य व्यापारी अभिकरणों की तुलना में राजकीय व्यापार निगम में, किस मात्रा में उत्तम कार्यकारी हालात हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हालत यह है और हम राजकीय व्यापार निगम को निर्यात संवर्धन के लिये प्रमुख अभिकरण बनाने वाले हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो विविध बड़ी बड़ी चीजों के लिये अधिक विशेषीकृत राज्य व्यापार निगम बनाने वाले हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या राजकीय व्यापार निगम समाजवादी अर्थ व्यवस्था वाले तथा पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था वाले देशों के साथ व्यापार करता है और यदि यह पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के देशों के साथ व्यापार करता है, तो क्या इस की अन्य निर्यात अभिकरणों से प्रतियोगिता नहीं होती और उस कारण लाभ कम नहीं हो जाते ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कारण यह नहीं है। वे पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार नहीं करते । यह राजकीय व्यापार निगम का एक अंग है। वे समस्त संसार से व्यापार करते हैं । जैसाकि सभा को

---

†मूल अंग्रेजी में

पता है, अधिकाधिक जोर वैदेशिक व्यापार पर दिया जा रहा है, जिस में आन्तरिक व्यापार की अपेक्षा कुछ कम लाभ होता है। इसी कारण लाभ उत्पादन की तुलना में अधिक नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अब चाय के निर्यात व्यापार में कठिनाई हो रही है, क्या यह बड़ी चीज, जो इतनी अधिक विदेशी मुद्रा कमाती है राजकीय व्यापार निगम के पास चली जायेगी, या यह चाय बोर्ड के अधीन रहेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस समय, चाय के निर्यात न तो चाय बोर्ड के अधीन है और न ही किसी एक अभिकरण के अधीन। यह सब व्यापारियों और सार्वजनिक नीलामी तथा निर्यातकों के द्वारा होता है। जैसा कि सभा को पता है, हाल ही में, वित्त मंत्री ने कुछ रियायतों की घोषणा की है और हम चाय का निर्यात बढ़ाने में अधिक कठिनाई की अपेक्षा नहीं करते। कल ही मैंने कुछ चाय व्यापारियों तथा उत्पादकों से मुलाकात की थी और हमें बहुत आशा है कि हमने जो कुछ हानि उठाई है, पिछले तीन वर्षों में लगभग १० करोड़, उससे अधिक कमा लेंगे।

†**श्री वेंकटा सुब्बैय्या :** क्या राजकीय व्यापार निगम के बहुत कम लाभों का यह भी कारण है कि निगम को चलाने वाले अफसरों में व्यापार चतुरता की कमी है और निगम के असाधारण विलंब हो जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसी तो बात नहीं। यह मतभेद का विषय हो सकता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, विदेश व्यापार पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है और राजकीय व्यापार निगम केवल लाभ कमाने वाला संगठन ही नहीं है। जहां कम लाभ कमा सकते हैं वहां अधिकतम संभव लाभ कमाना हमारा उद्देश्य होता है। किन्तु मुख्य उद्देश्य इस देश के विदेश व्यापार को बढ़ाना है, जहां हमें हानि भी उठानी पड़ती है। इस लिये लाभ कम हो जाते हैं।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी :** क्या बहुत मंत्रालयों का कारण परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अब मैं कहूंगा कि प्रारम्भ में मा० सदस्य द्वारा प्रयुक्त शब्द 'बहुत कम लाभ' सर्वथा गलत है तब मैंने इसका गंभीरता से खंडन करना नहीं चाहा। लाभ ३ करोड़ और ८१ लाख रुपये उल्लिखित वर्ष में कहा है, जो पहिले की अपेक्षा अधिक है और बहुत कम नहीं है। जब निगम आरंभ किया गया तो लाभ २.१३ करोड़ था। वह इतना अधिक है जितना हम इसे चाहते हैं।

†**श्री कमल नयन बजाज** : कुल बिक्री में लाभ की प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग छः प्रतिशत।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति

†*६१६. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) राज्य सरकारें, जो अधिनियम के अधीन उपयुक्त सरकारें हैं, श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति पर ध्यान दे रही हैं। उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों से ऐसा लगता है कि इसमें विहित अधिकांश संस्थान मजूरी समिति के आदेशों को मान रहे हैं। जब कभी कोई शिकायत मिलती है, तो राज्य सरकारों द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

भारत सरकार के मुद्रणालय

†*६२१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालयों में होने वाले काम की किस्म सुधारने और उत्पादन में मितव्ययता करने का प्रयास किया जा रहा है ; और

(ख) क्या भारत सरकार के मुद्रणालयों के प्रबन्धकों के सम्मेलन ने इस बारे में कोई सिफारिश की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) भारत सरकार के मुद्रणालयों में काम की किस्म सुधारने और उत्पादन में मितव्ययता करने के लिये निम्न दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं :

(१) भारत सरकार के बड़े मुद्रणालयों में एक आयोजन विभाग स्थापित करना।

(२) प्रोत्साहन बोनस योजना लागू करना।

(३) कार्य लागत पद्धति पर लागू करना।

(४) उत्पादक शाखाओं में आपरेटिरों के लिये 'ड्रिल' लगाना।

(५) मशीनों का प्रमाणकरणी करना।

(६) स्व-पूरित बिजली-एवं यंत्रीकृत शाखाओं की स्थापना करके निरोधात्मक उपाय।

(७) आपरेटिरों का प्रशिक्षण।

(ख) भारत सरकार के मुद्रणालयों के मैनेजरों के सम्मेलन में इन उपायों के प्राविधिक पहलू पर भी विचार किया गया। इसने कोई नयी सिफारिश नहीं की।

खान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ की कार्यान्विति

†*६२२. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ द्वारा बदली हुई नई धारा ५२ आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के अभ्रक खान क्षेत्र में लागू की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १६ जनवरी, १९६० से।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास में केन्द्रीय सरकार के दफ्तर

***६२४. श्री बालकृष्णन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में केन्द्रीय सरकार के सब कार्यालयों को एक स्थान पर लाने का विचार है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के सब कार्यालयों के लिये उपयुक्त इमारत उपलब्ध है अथवा क्या नई इमारत बनाई जायेगी ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, उनके अतिरिक्त जिनके अपने निर्माण कार्यक्रम हैं, मद्रास में सामान्य पूल में एक कार्यालय इमारत बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित इमारत के लिये योजना और प्राक्कलन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दलाई लामा की प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात

†*६२५. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ मार्च, १९६२ को दलाई लामा उनसे मिले थे और उन्होंने उनके साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो जिन मामलों की चर्चा की गई उनका ब्योरा क्या है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) जिन विषयों पर बातचीत की गयी, वह तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास और स्कूल जाने की आयु वाले तिब्बती शरणार्थी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में थे।

नये बाटों के बारे में पश्चिम बंगाल के व्यापारियों की कठिनाई

†*६३३. { श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नये बाटों तथा मापों के चालू हो जाने के बाद से पश्चिम बंगाल के छोटे व्यापारियों तथा दूकानदारों को नये बाटों को लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है जिससे पश्चिम बंगाल के व्यापारियों तथा खुदरा दुकानदारों को नये बाट उचित मूल्य पर मिल जायें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जिसमें पश्चिम बंगाल में मीट्रिक बाटों के संभरण की स्थिति और उनकी मांग पूरा करने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में बताया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

कलकत्ता हावड़ा क्षेत्र में, जहां ये अक्तूबर, १९५८ से लागू किये गये थे, अब मीट्रिक बाटों की कोई कमी नहीं है। इस क्षेत्र में अधिकांश व्यापारियों ने नये बाट खरीद लिये हैं। राज्य के बाकी भाग में मीट्रिक बाटों का इस्तेमाल १-४-१९६२ से अनिवार्य किया गया। इससे नये बाटों की मांग बहुत बढ़ गई इस समय बाटों का संभरण पूरी मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है और बाटों की कमी अस्थायी है।

बाटों के निर्माताओं और व्यापारियों को राज्य सरकार ने मुक्त रूप से लाइसेंस दिये हैं। निर्माताओं को अपनी अधिकतम क्षमता तक उत्पादन बढ़ाने को प्रेरित किया गया है और पीतल जैसे कमी वाले कच्चे माल की प्राप्ति में सहायता दी गयी है। कमी के ३ या ४ महीनों में पूरी हो जाने की आशा है। इस बीच में, कानून को लागू करने में कुछ ढील दी गयी है और उन स्थानों में जहां नये बाट आसानी से नहीं मिल पा रहे, पुराने बाटों के इस्तेमाल के विरुद्ध कोई दाण्डक कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पीने के पानी की योजना के सम्बन्ध में भारत-नेपाल करार

†*६३४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू में पीने का पानी का संभरण करने की योजना के विकास के लिये भारत तथा नेपाल के बीच करारों पर हस्ताक्षर हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन करारों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी क्या होगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) काठमांडू में पीने के पानी के संभरण के विकास के लिये काठमांडू में दोनों सरकारों के बीच २५ अप्रैल, १९६२ को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) (१) सुन्दरीजाल की तलहटी से पानी को इकट्ठा करना, साफ करना और भेजना।

(२) कच्चे पानी को भरने के लिये जलाशय, कच्चे पानी का मेन, पानी साफ करने का संयंत्र और साफ पानी भरने का जलाशय बनाना।

(३) कम से कम ३ इंच व्यास के पाइप लगाकर वर्तमान वितरण पद्धति को सुधारने के ख्याल से वर्तमान वितरण पद्धति का सर्वेक्षण करना और पुराने मेन्स को बदलना।

(ग) इस योजना की क्रियान्विति के लिये भारत सरकार ने ७९ लाख रुपये देने का आश्वासन दिया है।

मूलभूत रसायनों तथा मध्यवर्ती पदार्थों का कारखाना[1]

†*६३५. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड ने मूलभूत रसायनों तथा मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण के लिये कारखाने की स्थापना के बारे में कोई प्रगति की है;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Basic chemicals and Intermediates Plant.

(ख) क्या योजनायें और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का कुल व्यय क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। स्थान चुन लिया गया है और भूमि समतल बनाई जा रही है। नक्शों और नींव योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इनोर्गेनिक प्लांट्स और यूटिलिटीज के लिये पूछताछ की गयी है और कुछ उपकरणों के आदेश मिले हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है। जर्मनी से प्रांगारिक संयंत्र प्राप्त करने की व्यवस्था पूरी हो गयी है। क्रमशः महाराष्ट्र राज्य सरकार और महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के साथ जल-संभरण और बिजली की व्यवस्था कर ली गयी है।

(ख) प्राथमिक योजना और प्राक्कलन बनाये गये हैं और व्यापक योजना और प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं।

(ग) लगभग १२ करोड़ रुपये।

कर्मचारी भविष्य निधि

†*६३६. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि न्यासियों (ट्रस्टीज़) की २८ मार्च, १९६२ को हुई बैठक में की गई इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली रकमों पर ब्याज की दर बढ़ा कर ३.७५ प्रतिशत कर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) न्यासियों (ट्रस्टीज) की यह सिफारिश, कि चालू वर्ष के लिये ब्याज की दर ३.७५ प्रतिशत होनी चाहिये, सरकार द्वारा मान ली गयी है। यह दर वर्ष १९५७-५८ से लागू है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की सहमति के बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को १ मई, १९६२ को बता दिया गया था।

गंगा के सम्बन्ध में दूसरी फिल्म

*६३७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर फिल्म्स डिवीजन द्वारा गंगा पर दूसरी फिल्म बनाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : इस प्रस्ताव को अब छोड़ दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी

†*६३९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें आकाशवाणी साहित्य समारोह ने देश में अन्तर्भाषा बोध को बढ़ावा दिये जाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या प्रामाणिक अन्तर्भाषा अनुवाद का कोई विशिष्ट सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) साहित्य समारोह कोई औपचारिक सिफारिश नहीं करता । यह साहित्यकारों द्वारा विचारों के आदान-प्रदान और विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये आयोजित किया जाता है ।

(ख) और (ग). बातचीत के दौरान कुछ लाभदायक सुझाव दिये गये हैं । उनमें से जो प्रसारण से सम्बन्धित हैं, उनका आकाशवाणी द्वारा परीक्षण किया जायेगा और अन्यों को संबंधित संगठनों को बता दिया जायेगा ।

चिनाकुरी कोयला खान में दुर्घटना

†*६४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ अप्रैल, १९६२ को चिनाकुरी कोयला खान धंस गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में यदि लोग हताहत हुए तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) कोयला खानों में ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) छत गिरने से दुर्घटना हुई ।

(ख) तीन व्यक्ति मरे, दो सख्त जख्मी हुए और चार को मामूली चोट आयी ।

(ग) यह दुर्घटना सुपरवाइजरी कर्मचारियों की गल्ती से हुई जिसके लिये उनको उनके प्रमाणपत्र निलम्बित करके दण्ड दिया जा रहा है ।

'नान-न्युक्लियर क्लब'

†*६४१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सरकारी तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचना दे दी है कि भारत आण्विक हथियारों का विकास अथवा अर्जन न करने का आश्वासन देने वाले देशों के 'नान-न्यूक्लियर क्लब' में शामिल होगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया था;

(ग) ऐसे अन्य कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने अब तक इस 'क्लब' में शामिल होने का संकेत दिया है;

(घ) क्या ऐसा 'क्लब' बन गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके ध्येय और उद्देश्य क्या होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ङ). संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली ने ४ दिसम्बर, १९६१ को पारित किये संकल्प के अधीन महासचिव से उन परिस्थितियों की जांच करने का अनुरोध किया जिनके अधीन वे देश, जिनके पास आण्विक हथियार नहीं हैं, यह आश्वासन दे सकें कि वे इनका निर्माण नहीं करेंगे और ऐसे हथियार किसी से नहीं लेंगे और अपने प्रदेश में आण्विक हथियारों को नहीं आने देंगे। उतर की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १०]

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने मार्च, १९६२ के अन्त में महा-सचिव को बताया कि भारत का इरादा आण्विक अस्त्रों को निर्माण करने का या स्वीकार करने का नहीं है और भारत इस बारे में किसी सामान्य करार अथवा विशिष्ट आश्वासन में शामिल नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की भावना और विचारों के साथ सहानुभूति के तौर पर कई अन्य राज्यों ने भी अपने विचार दिये हैं परन्तु महा-सचिव को प्राप्त उतरों का पूरा व्योरा अभी प्राप्त हुआ है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

चैकोस्लोवेकिया के प्रतिनिधिमंडल द्वारा केरल का दौरा

†*६४२. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प० कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवेकिया के प्रतिनिधिमंडल ने मार्च, १९६२ में केरल राज्य का दौरा किया था और वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं की जांच की थी; और

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल अथवा राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, प्रतिनिधिमंडल ने त्रावनकोर रबर वर्क्स, त्रिवेन्द्रम और कुन्डारा में मिट्टी के बर्तन बनाने के दो कारखानों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। ये सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

रोजगार दफ्तर

*६४३. श्री भक्त दर्शन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में कुछ नये रोजगार दफ्तर विभिन्न राज्यों में खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं; और

(ग) वर्ष १९६२-६३ में ये दफ्तर किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ११]**

(ग) स्थानों का पता नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में निर्णय लेने की जिम्मेवारी मूलतः राज्य सरकारों की है।

दक्षिण अफ्रीका के भारतीय

†*६४४. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बिगे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 'ग्रुप एरियाज एक्ट' के अधीन जोन्सबर्ग के कुछ क्षेत्रों को केवल श्वेत क्षेत्र बनाने की उद्घोषण की है ; और

(ख) क्या दक्षिण अफ्रीका सरकार की इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कई हजार भारतीयों द्वारा शीघ्र ही अपने घर छोड़ जाने की सम्भावना हो गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

अमरीका को भारतीय चाय शिष्टमंडल

†*६४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६२ में भारतीय चाय शिष्टमंडल अमरीका गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का मुख्य प्रयोजन क्या था : और

(ग) शिष्टमंडल द्वारा उस देश में की गई बातचीत के क्या परिणाम निकले थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :**

(क) जी, हां।

(ख) अमरीका में भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये।

(ग) शिष्टमंडल का प्रतिवेदन प्रतिक्षित है।

शाहदरा (दिल्ली) में घड़ी का कारखाना

†*१०२८. **श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा (दिल्ली) में लगभग १ वर्ष पूर्व स्थापित हुए कारखाने में इसकी स्थापना के समय ही कुल कितने टाइम-पीस बनाये गये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन टाइम-पीसों की लागत क्या है, और

(ग) क्या ये घड़ियां स्तर की घड़ियां हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) ३१-३-६२ तक ४२७२० संख्या ।

(ख) ८,७३,०३६ रुपये ।

(ग) इस फर्म द्वारा बनाये गये टाइम-पीसों की किस्म अन्य मेक के इतने ही मूल्य के टाइम-पीसों से अच्छी है ।

पंजीयित बेरोजगार

†१०२९. **श्री दाजी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६२ को विभिन्न राज्यों मे (राज्यवार) रोजगार के लिये कितने व्यक्ति रजिस्टर्ड थे ;

(ख) वर्ष १९६१ में विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्ति रजिस्टर्ड किये गये;

(ग) उनमें से कितने '(१) मैट्रिकुलेट (२) ग्रेज्यूएट और (३) प्रविधिक रूप से प्रशिक्षित थे, और

(घ) वर्ष १९६० और १९६१ में (पृथक पृथक) प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या १२]

मतदाताओं के लिये चलचित्र

१०३०. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पिछले आम चुनाव के अवसर पर मतदाताओं को मतदान सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए कोई डाक्युमेंट्री (प्रलेख चित्र) बनायी थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने आगामी चुनाव के लिये, ऐसा कोई प्रलेख चित्र बनाने का फैसला किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी हां । "मतदान कैसे किया जाए" नामक एक डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हथ करघे के कपड़े का निर्यात

†१०३१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में ब्रिटेन,अमरीका, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और रूस से , उनको हथ-करघे की बनी चीजें और हथकरघे के कपड़े का निर्यात करके, कुल कितनी धनराशी प्राप्त की ; और

(ख) क्या उसी अवधि में सरकार द्वारा सामान की मांग पूरी तौर पर पूरी की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). यह जानकारी मंत्रालय में तत्काल उपलबध नहीं है । यह एकत्र की जा रही है और प्राप्त हाने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

अखबारी कागज

†१०३२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगें कि:

(क) वर्ष १९६१-६२ में देश में कुल कितने अखबारी कागज का आयात किया गया और कुल कितने अखबारी कागज का उत्पादन किया गया ; और

(ख) उसी अवधि में अखबारी कागज पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वर्ष १९६१-६२ में देश में २५,२७९ टन अखबारी कागज का उत्पादन हुआ और वर्ष १९६१-६२ में (जनवरी, १९६२ तक जब तक के आंकड़े उपलबध हैं) १,०१,५८६ टन अखबारी कागज का आयात किया गया ।

(ख) वर्ष १९६१-६२ में (जनवरी) १९६२ तक, (जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) अखबारी कागज के आयात पर कुल ७,९५,२८,००० रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ।

साइकिलों का निर्यात

†१०३३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में कुल कितनी साइकिलें निर्यात की गयीं :

(ख) जिनको ये निर्यात की गयीं उनके क्या नाम हैं और प्रत्येक देश को कितनी कितनी साइकिलें निर्यात की गयीं ;

(ग) निर्यात द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(घ) क्या इन देशों की पूरी मांग पूरी कर दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). वर्ष १९६१-६२ के अप्रैल १९६१ से फरवरी, १९६२ के दौरान साइकिलों के देश-वार निर्यात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं । मार्च १९६२ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ;

देश	मात्रा (नगों में)	मूल्य हजार रुपयों में
मिश्र	११,०००	९९८
अफगानिस्तान	७८७	९५
पाकिस्तान (पूर्व)	४५६	५५
ईरान	१२०	९
नाईजीरिया	७५	८
न्यासालैंड	१२५	८
सूडान	२५	२
तांगान्यीका	२५	२
अदन	२०	२
कम मूल्य के सौदे	८३	६
कुल	१२,७१६	११८५

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उद्योगों में विदेशी पूंजी

१०३४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ४०२ उद्योगों में से जिन में विदेशी पूंजी और प्रविधिक सहयोग के समझौते किये गए हैं वे १४ उद्योग कौन-कौन से हैं जिनमें ५१ प्रतिशत या अधिक विदेशी पूंजी के लिये स्वीकृति दी गयी है ;

(ख) क्या इन १४ उद्योगों के अतिरिक्त कुछ और ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र आये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे कितने हैं और उनका व्यौरा क्या है ; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कितने उद्योगों के लिये सरकार स्वीकृति देने के लिए तैयार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) १९६१ में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रविधिक और वित्तीय विदेशी सहयोग के ४०२ समझौतों में से १४ मामलों में अधिकांश पूंजी लगाना मंजूर कर लिया गया है । जिन उद्योगों के निर्माण के लिये अधिकांश विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दे दी गई है उनके नाम ये हैं--गैसकट, कोयला धोने के कारखाने, टायर ट्यूब, वाल्व, कैपेसिटर, औद्योगिक प्रशीतन मशीनें, बाल-बियरिंग कागज बनाने की मशीनें, गर्भ-निरोधक वस्तुएं, मोटर गाड़ी वैद्युत् उपकरण, इकहरे तकुये, स्वचालित खरादें, कैल्शियम विनायल पी० ए० एस०, कैल्शियम पी० ए० एस० सोडियम पी० ए० एस०, डाइथेन फफूंदनाशक पदार्थ, प्लास्टिसाइजर्स तथा मोटर गाड़ियों के पहिये ।

(ख) से (घ). अधिकांश विदेशी पूंजी लगाने के बारे में भारत सरकार को निम्नलिखित दो प्रस्ताव मिले हैं :--

(१) मेसर्स फाइबर ग्लास पिलकिंगटन लि०, बम्बई का प्रस्ताव जो मेसर्स आवेन्स कारनिंग फाइवर ग्लास कारपोरेशन, ओहियो (अमेरिका) तथा मेसर्स फाइवर ग्लास लि०, ब्रिटेन के साथ सहयोग करके कांच की ऊन, कांच के कपड़े और नकली रेशम बनायेंगे । विदेशी सहयोगियों की पूंजी ५१ प्रतिशत से कुछ ही अधिक होगी।

(२) मेसर्स प्रेंटिस हाल इंस अमेरिका का प्रस्ताव जो वैज्ञानिक, प्रविधिक तथा अन्य प्रतिमानित पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये एक संगठन स्थापित करने के वास्ते हैं। इसमें विदेशी पूंजी ५१ प्रतिशत होगी ।

दोनों प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

आकाशवाणी में हिन्दी का प्रयोग

१०३५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली तथा अन्य केन्द्रों में धीरे-धीरे हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) उनकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के हिन्दी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अंग्रेजी विभाग में कार्य करने वाले कमचारियों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो यह भिन्नता क्यों रखी गयी है और क्या भविष्य में इसे समाप्त करने की भी कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) और (ख). आकाशवाणी ने हिन्दी प्रसारणों को प्रोत्साहन देने के लिये जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में एक नोट सभा की मेज़ पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]** जहां तक आकाशवाणी के कार्यालयों में पत्र व्यवहार और नोटिंग में हिन्दी के प्रयोग का सम्बन्ध है, गृह मन्त्रालय के अनुदेशों का अनुसरण किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषधियों का आयात

†१०३६. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष काफी मात्रा में विदेशी औषधियों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) उनको यहां पर बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस समय पुराने आयातकर्त्ताओं को पहले आयात के मूल्य का केवल २० प्रतिशत तक आयात करने दिया जाता है और वह भी आवश्यक चीजों का, जो देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाई जातीं।

(ख) ग़ैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मूलतः कई आवश्यक औषधियां बनाई जा रही हैं। अन्य चीजों के बनाने की योजनायें दोनों क्षेत्रों में लागू की जा रही हैं। औषधि निर्माताओं को अपने कार्यक्रम में एक भाग के रूप में मूलतः औषधि बनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है और कहा जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगों में भारतीय सेना

†१०३७. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ मार्च, १९६२ को एलिजाबेथविले में योरोपीय और अफ्रीकी विद्यार्थियों ने इस विरोध में, कि भारतीय सिपाहियों ने विश्वविद्यालय की एक बस के ड्राइवर को पीटा, भारतीय सेना के विरुद्ध प्रदर्शन किया ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :**

(क) ३० मार्च, १९६२ को ऐसी घटना हुई थी।

(ख) उस दिन प्रातःकाल विद्यार्थियों को ले जा रही एक विश्वविद्यालय बस ने, जो बहुत तेज चल रही थी, संयुक्त राष्ट्र के सड़क-रोक स्थान पर एक बैरल को टक्कर मार कर स्थान से हटा दिया जहां भारतीय व्यक्ति थे। ड्यूटी पर तैनात सन्तरी ने बस को रोक कर बस के चालक से कहा कि वह बैरल को ठीक कर दे। जब चालक ने ऐसा करने से इन्कार किया तो सन्तरी ने जबरदस्ती उससे बैरल ठीक करने को कहा। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध कस्बे में छोटा सा प्रदर्शन हुआ जिसे बिना किसी दुर्घटना के तितर बितर कर दिया गया।

ब्रह्माण्ड किरणों का अध्ययन[1]

†१०३८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्माण्ड किरणों की शक्ति का अध्ययन करने के लिये भारत अमरीकी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में टाटा मूलभूत अनुसन्धान संस्था ने मार्च, १९६२ में एक बहुत बड़ा गुब्बारा छोड़ा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सफल हुआ ;

(ग) क्या आण्विक फोटोग्राफिक प्लेटें मिलीं ; और

(घ) इस प्रयोग का क्या अस्थायी परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). जी हां।

(घ) प्रयोग का उद्देश्य बहुत ऊंची आणविक और उप-आणविक बातों का अध्ययन करना था। इस प्रयोग के परिणाम उपलब्ध होने में कई महीने लगेंगे।

कानपुर के चमड़ा उद्योगों के श्रमिकों के लिये भविष्य निधि

†१०३९. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि योजना कानपुर के चमड़ा कारखानों पर लागू नहीं की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Energy spectrum of cosmic rays.

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर ने इस को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधियां अधिनियम, १९५२ तथा उसके अधीन बनाई गई योजना का विस्तार चमड़ा और चमड़ा वस्तु उद्योग के कर्मचारियों पर ३१ अगस्त, १९६१ से लागू किया गया है। मैसर्स कूपर आलान एण्ड कम्पनी लिमिटेड उस तारीख में अधिनियम के उपबन्धों तथा योजना के पालन अनुसार काम कर रहे हैं।

बोनस आयोग

†१०४०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस आयोग से उसका काम पूर्ण किये जाने की कब सम्भावना है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). आयोग ने अपनी प्रश्नावली हाल में ही तैयार करके जारी की है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि आयोग कब अपना काम पूरा कर सकेगा।

कानपुर में औद्योगिक आवास योजना

†१०४१. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये अधिकांश मकानों में कार्यकर्त्ता नहीं आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि उन मकानों के किराये अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो किराया कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) ३१ मार्च १९६२ तक कानपुर में बनाये गये १३३४५ मकानों में से ८५१४ मकानों में कार्यकर्ता रहते हैं, ४७२७ मकान अस्थायी रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के पास थे और केवल १०४ मकानों का आवंटन अभी बकाया है।

(ख) और (ग). योजना के अन्तर्गत कितना किराया निर्धारित किया गया है उससे अधिक किराया किसी कार्यकर्ता से नहीं लिया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

काली मिर्च के दाम

†१०४२. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान की अपेक्षा अधिक स्तर पर काली मिर्च के दाम स्थिर रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय काली मिर्च परिषद् बनाने का सुझाव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध मे क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) भारत सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये भवन

१०४३. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली व नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों के लिये कितने नये भवन बनाये जाने हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक का कितना विस्तार होगा और उस पर अनुमानतः कितना खर्चा होगा; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के निर्माण पर अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग). एक चार मंजिली इमारत, जिसमे २०,००० वर्ग फुट स्थान होगा और जिसकी लागत ९ लाख रुपये प्राक्कलित की गई है, बन रही है । चार बहुतले भवनों के निर्माण के लिये नक्शे और प्राक्कलन विचाराधीन हैं । इन सब में मिला कर १७.६५ लाख वर्ग फुट फर्शी क्षेत्रफल निकलेगा और इन पर लगभग ५.५ करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी

†**१०४४. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान ऐंटी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी द्वारा विटामिन सी तैयार करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा, तथा वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) पिम्परी का प्रस्तावित संयंत्र ४८ टन विटामिन सी प्रति वर्ष तैयार करेगा । वर्तमान संकेतों के अनुसार ७० लाख रुपये की पूंजी लागत का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांस को सिलाई की मशीनों का निर्यात

†१०४५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ७०० भारतीय सिलाई की मशीनें फ़्रांस भेजी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खेप भेजने से पहले यह जांच कर ली गई थी कि मशीनें स्टैंडर्ड चिह्न वाली हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). भारत ने १९६०-६१ में फ़्रांस को ४०१ सिलाई की मशीनें भेजीं और इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् से यह पता चला है कि हाल ही में एक भारतीय फर्म ने ७०० सिलाई की मशीनें भेजने के लिये फ़्रांसीसी फर्म के साथ संविदा किया है।

निर्यात-संविदा, फ़्रांसीसी आयातकों द्वारा अनुमोदित नमूनों के आधार पर किया गया है ।

भारत में समाचार माध्यमों का सर्वेक्षण

†१०४६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानने के लिये कि भारत के लोगों में देश और विदेशों के समाचारों से सूचित रहने के निम्नतम साधन अभी तक किस मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर 'न' है, तो क्या कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, नहीं । कोई विशिष्ट अध्ययन अभी नहीं किया गया ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) ऐसे अध्ययन की एक प्रस्थापना, सार्वजनिक संचार तरीकों के प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्र स्थापित करने की परियोजना के सम्बंध में विचाराधीन है । यह प्रस्थापना अभी प्रारंभिक अवस्था में है ।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड

†१०४७. **श्री वासप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड की वर्तमान इकाइयों के विस्तार का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) क्या वहां अनुसंधान संबंधी सुविधाओं बढ़ा दी गई हैं ; और

(ग) अनुसंधान के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां । हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाला प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम नीचे दिया जाता है :—

डी० डी० टी० फक्टरी दिल्ली

		(टन प्रति वर्ष)
१.	डी० डी० टी० प्रविधिक . . .	१३४०
२.	मोनोफ्लोरोबैनज़ीन . . .	२०००
३.	पारा डाइक्लोरोबैनज़ीन . .	५००
४.	क्लोल हाइड्रेट	५०

डी० डी० टी० फैक्टरी अल्वाये

१.	बन्ज़ीन हैक्सा क्लोराइड	३०००
२.	क्लोरो फार्म	१२५०

कुल लागत १५० लाख रुपये होने का अनुमान है जो कम्पनी द्वारा अपने संसाधनों से दिया जायेगा प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) ५.२३ लाख रुपये ।

आकाशवाणी

१०४८. श्री वाल्मीकी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में पत्रकारिता सम्बन्धी नौकरियों में अभी तक हरिजनों का आम्यंश (कोटा) पूरा नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) और (ख). इस मंत्रालय और इस के अधीन विभागों में, जिस में आकाशवाणी भी शामिल है, जितने भी पत्रकारिता सम्बन्धी पद हैं, वे सभी अब केन्द्रीय सूचना सेवा के अन्तर्गत हैं, जिन में केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों के अनुसार भरती की जाती है । इस सेवा के प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित क़बीलों के लिये जो पद आरक्षित किये जाते हैं वे संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित कर दिये जाते हैं और उस की सिफारिशों के आधार पर हीं नियुक्तियां की जाती हैं । १–३–१९६० से, जब से केन्द्रीच सूचना सेवा आरम्भ हुई है, सीधी भर्ती ग्रेड २ में की गई है, जिस में २ पद अनुसूचित जातियों और १ पद अनुसूचित क़बीथ्लों के लिए आरक्षित किये गये थे । परन्तु आयोग ने अनुसूचित जाति के केवल १ उम्मीदवार की सिफ़ारिश की, जिस को नियुक्त कर के आकाशवाणी में पोस्ट कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में कृषक

†१०४९. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता के साथ खेती के मन्दे मौसम में कृषकों को रोज़गार दिलाने के लिये बिहार में कुछ परियोजनायें चलाने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ग्रौर इन योजनाग्रों के ब्यौरे क्या हैं ; ग्रौर

(ग) खेती के मन्दे मौसम में कितने कृषक बेरोज़गार हो जायेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, योजना के ग्रन्तर्गत ग्रनुमानतः कितने लोगों को रोज़गार दिलाया जा सकेगा ?

†**योजना तथा श्रम ग्रौर रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९६१-६२ ग्रौर १९६२-६३ में खेती के मन्दे मौसमों में ग्रारम्भ करने के लिये बिहार सरकार को ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के निर्माण कार्यक्रमों की तेरह ग्रग्रिम परियोजनाएं ग्रावंटित की हैं । वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के ग्रन्त तक इन परियोजनाग्रों पर खर्च की गई राशि पूर्णतया केन्द्र द्वारा दी जायेगी । वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से, इन परियोजनाग्रों की लागत केन्द्र द्वारा ५० प्रतिशत ग्रनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण के रूप में दी जायगी । प्रत्येक परियोजना की लागत पहले प्रक्रम में (ग्रर्थात् वह ग्रवधि जो एक वित्तीय वर्ष के खेती के मन्दे मौसम में ग्रारम्भ होती है, जब परियोजनाएं ग्रारम्भ की जाती हैं ग्रौर ग्रागामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होती है) २ लाख रुपये होती है ।

पहले प्रक्रम के पश्चात्, प्रत्येक परियोजना को बाद के तीन वर्षों के लिये एक लाख रुपया प्रति वर्ष मिलता रहता है, ग्रौर केन्द्रीय सहायता का रूप वही रहता है ग्रर्थात् ५० प्रतिशत ग्रनुदान ग्रौर ५० प्रतिशत ऋण । बिहार में ग्रग्रिम परियोजनाग्रों के ग्रन्तर्गत ग्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित योजनाग्रों में कच्चे बांधों का निर्माण, पुलियों समेत सड़कें, छोटी ग्रौर मध्यम दर्जे की सिंचाई, पाइनों/जोहड़ों की मिट्टी निकालना, गांव की नालियां तथा जल रोकने के फाटक ग्रादि ।

तेरह परियोजनाग्रों से १९६१-६२ ग्रौर १९६२-६३ के खेती के मन्दे मौसमों में, १०० दिनों के लिये लगभग १३,३०० कृषकों को रोज़गार दिलाये जाने की ग्रपेक्षा की जाती है । मन्दे मौसम में बेकार कृषि मजदूरों की कुल संख्या का ग्रनुमान एक सर्वेक्षण के द्वारा लगाया जा रहा है ।

उड़ीसा में कृषक

†१०५०. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की ग्रर्थ-सहायता के साथ खेती के मन्दे मौसम में कृषकों को रोज़गार दिलाने के लिये उड़ीसा में परियोजनायें चलाने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाग्रों के ब्योरे क्या हैं ; ग्रौर

(ग) इन योजनाग्रों की ग्रनुमानित लागत क्या होगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की जायगी ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार के कहने पर १९६० में खेती के मन्दे मौसम में उड़ीसा सरकार द्वारा ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के निर्माण कार्यक्रमों की दो अग्रिम परियोजनायें आरम्भ की गई थीं। दूसरी माला के अन्तर्गत, १९६१-६२ और १९६२-६३ के खेती के मन्दे मौसमों में आरम्भ की जाने के लिये उड़ीसा सरकार को बारह और अग्रिम परियोजनायें आवंटित की गई हैं । सभी अग्रिम परियोजनाओं का खर्च चाहे वे पहली माला की हैं या दूसरी माला की, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के अंत तक पूर्णतया केन्द्र द्वारा किया गया था। वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से, परियोजनाओं की लागत केन्द्र द्वारा ५० प्रतिशत अनुदान और ५० प्रतिशत ऋण के तौर पर दी जायेगी। पहले प्रक्रम (अर्थात् अवधि जो एक वित्तीय वर्ष के खेती के मन्दे मौसम में आरम्भ होती है जब परियोजनायें आरम्भ की जाती हैं और अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होती हैं । में प्रत्येक परियोजना की लागत २ लाख रुपये है । पहले प्रक्रम के पश्चात्, प्रत्येक परियोजना को बाद के तीन वर्षों के लिये प्रति वर्ष १ लाख रुपया मिलेगी, और केन्द्रीय सहायता का स्वरूप वही रहेगा, अर्थात् ५० प्रतिशत ऋण तथा ५० प्रतिशत अनुदान ।

उड़ीसा में परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत २८ लाख रुपये है। इसमें से वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के अन्त तक खर्च की गई राशि केन्द्र द्वारा दी जायेगी, जब कि बाद की अवधि में इन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता ५००% अनुदान और ५००% ऋण के आधार उडीसा में अग्रिब परियोजनाओं के शामिल योजनाएं हैं खोटी सिंचाई, सड़क निर्माण, मछली पालने के तालाबों की खुदाई, पंचायत पठागारों का निर्माण, स्कूलों की इमारतों का निर्माण, वन रोपण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे उठे मकानों के स्थाद का निर्माण, और वन श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना।

आसाम में कृषकों के लिये रोजगार

†१०५१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता के साथ खेती के मन्दे मौसम में कृषकों को रोज़गार दिलाने के लिय आसान में कुछ परियोजनायें चलाने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के व्यौरे क्या हैं ;

(ग) योजनाओं पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(घ) खेती के मन्दे मौसम में कितने कृषक बेरोज़गार हो जायेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए योजना के अन्तर्गत अनुमानतः कितने लोगों को रोज़गार दिलाया जा सकेगा ?

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार के कहने पर १९६० में खेती के मन्दे मौसम में आसाम सरकार द्वारा ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के निर्माण कार्यक्रमों की तीन अग्रिम परियोजनायें आरम्भ की गई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी माला के अन्तर्गत, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के खेती के मन्दे मौसमों में आरम्भ की जाने के लिये आसाम सरकार को दस और अग्रिम परियोजनाएं आवंटित की गई थीं। पहली या दूसरी मालाओं के अन्तर्गत आरम्भ की गई सभी अग्रिम परियोजनाओं का खर्च १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक केन्द्र द्वारा पूर्ण रूपेण दिया गया था। वित्तीय वर्ष १९६२–६३ से, परियोजनाओं की लागत केन्द्र द्वारा ५० प्रतिशत अनुदान और ५० प्रतिशत ऋण के आधार पर दी जाएगी। पहले प्रक्रम में (अर्थात वह अवधि जो एक वित्तीय वर्ष के खेती के मन्दे मौसम में आरम्भ होती है जब परियोजनाएं आरम्भ की जाती हैं और अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होती है) प्रत्येक परियोजना की लागत २ लाख रुपये है। पहले प्रक्रम के पश्चात्, प्रत्येक परियोजना को बाद के तीन वर्षों के लिये १ लाख रुपये प्रतिवर्ष तक मिलता है, और केन्द्रीय सहायता का स्वरूप वही रहता है, अर्थात् ५० प्रतिशत अनुदान और ५० प्रतिशत ऋण।

आसाम में अग्रिम परियोजनाओं के अधीन प्रस्तावित योजनाओं में सड़कें एवं बांध, तटबन्ध रेगूलेटरों और फाटकों का निर्माण तथा मत्स्यपालन का विकास शामिल हैं। योजनाओं की लागत का अनुमान वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के अन्त तक की अवधि के लिये २६ लाख रुपये लगाया गया है। परियोजनाओं से, १९६१–६२ और १९६२–६३ में खेती के मन्दे मौसमों में १०० दिनों के लिये लगभग १३३०० कृषक श्रमिकों को रोजगार दिलाये जाने की अपेक्षा की जाती है। उन खण्डों में जिनके लिये परियोजनाय प्रस्तावित की गई हैं, मन्दे मौसम में बेकार कृषक श्रमिकों की कुल संख्या का अनुमान एक सर्वेक्षण के द्वारा लगाया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल में कृषकों के लिये रोजगार

†१०५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता के साथ खेती के मन्दे मौसम में कृषकों को रोज़गार दिलाने के लिये पश्चिम बंगाल में कुछ परियोजनाय चलाने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के व्यौरे क्या हैं ; और

(ग) खेती के मन्दे मौसम में कितने कृषक बेरोज़गार हो जायेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, योजना के अन्तर्गत अनुमानतः कितने लोगों को रोज़गार दिलाया जा सकेगा ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार के कहने पर १९६० में खेती के मन्दे मौसम में, ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के लिये निर्माण कार्यक्रमों की दो अग्रिम परियोजनाएं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई गई थीं। दूसरी माला के अन्तर्गत, १९६१–६२ और १९६२–६३ में खेती के मन्दे मौसमों में आरम्भ की जाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को १४ अग्रिम परियोजनाएं आवंटित की गई थीं। सब अग्रिम परियोजनाओं का खर्च, चाहे वे पहली माला की हैं या दूसरी माला की; वित्तीय वर्ष १९६१–६२ की समाप्ति तक केन्द्र द्वारा पूर्णरूपेण किया गया था। वित्तीय वर्ष १९६२–६३ से परियोजनाओं की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा ५० प्रतिशत ऋण और ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाएगी। पहले प्रक्रम में (वह अवधि जो एक वित्तीय वर्ष में खेती के मन्दे मौसम में आरम्भ होती है, जब परियोजनाएं आरम्भ होती हैं और अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होती है) प्रत्यक परियोजना की लागत

†मल अंग्रेजी में

२ लाख रुपय है। पहले प्रक्रम के पश्चात् सब परियोजनाओं को बाद के तीन वर्षों के लिये प्रतिवर्ष १ लाख रुपये मिलेगा, और केन्द्रीय सहायता का स्वरूप वही रहेगा अर्थात् ५० प्रतिशत अनुदान और ५० प्रतिशत ऋण।

पश्चिम बंगाल में अग्रिम परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं में, तालाबों का जीर्णोद्धार, बांधों का निर्माण, नहरों की खुदाई, छोटी सिंचाई, सड़क के काम आदि शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इन परियोजनाओं से, १९६१-६२ और १९६२-६३ में खेती के मन्दे मौसमों में पश्चिम बंगाल में १०० दिनों के लिये लगभग १८,००० कृषक श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा। मन्दे मौसम में बेकार कृषक श्रमिकों की कुल संख्या का अनुमान एक सर्वेक्षण के द्वारा लगाया जा रहा है।

वायदा बाजार आयोग

†१०५३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायदा बाजार आयोग ने कानपुर में गुड़ का सट्टा करने के लिये नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कानपुर के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जब कि उसने कानपुर के दूसरे असोसियेशनों के साथ भी आवेदन किया था, जिनसे, नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (प्राइवेट) लिमिटेड को छोड़कर, इस मामले में परामर्श किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला तय करने के लिये बम्बई, लखनऊ और कानपुर में आयोजित वायदा बाजार आयोग की बैठकों में नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबन्धकों को किन कारणों से नहीं बुलाया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस विषय पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) लखनऊ में आयोग की कोई बैठक नहीं हुई थी। कानपुर और बम्बई में हुई चर्चाओं में चेम्बर ने आयोग से मुलाकात करने की कोई बात नहीं कही।

प्रेस आयोग

†१०५४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) प्रेस आयोग की सिफारिशे कहां तक कार्यान्वित की जा चुकी हैं ;

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हे पूरा पूरा कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (ग) एक विवरण यथासमय लोकसभा के पटल पर रखा जायगा।

आन्ध्र प्रदेश अभ्रक कर्मचारी सम्मेलन

†१०५५. **श्री यल्लमन्दा रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ मई, १९६० को हुए चौथे आन्ध्र प्रदेश अभ्रक कर्मचारी सम्मेलन के संकल्प सरकार को प्राप्त हुए हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय के अलावा, भारत सरकार के कुछ अन्य मंत्रालय और आन्ध्र प्रदेश सरकार भी इन संकल्पों से संबंधित है। संकल्पों की प्रतियां उन्हें दी गयी थीं। मुख्य मांगें और उन पर की गयी कार्यवाही दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]** दो मांगों पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अब भी विचार कर रहा है।

कोयला खानों के लिये माल लादने की सुविधाएं

†**१०५६. श्री यलमंदा रेड्डी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों और व्यापारी रविवार और दूसरी छुट्टी के दिन रेलवे में माल लादने की सुविधाओं का उपयोग नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रविवार तथा दूसरी छुट्टियों के दिन माल लादने की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) से (ग). रविवार और छुट्टी के दिन माल लादने का काम अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत कम होता रहा। कोयला खानों और व्यापारियों को यह समझाने के लिए कदम उठाये गये हैं कि अन्य दिनों में जितना माल छुट्टी के दिन भी लादना उतना ही जरूरी है रविवार और छुट्टी के दिन अधिक माल लादे जाने के उपायों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली के पंखे

†**१०५७. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नयी दिल्ली में अब चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली के पंखे लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कितना खर्च होगा;

(ग) काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस गर्मी में इन क्वार्टरों में खस की टट्टियां लगाने की कोई योजना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) अभी तक इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) खस की टट्टियां लगाने की कोई योजना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागपुर में केन्द्रीय सरकार के दफ्तर

†१०५८. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के दफ्तर जैसे सेन्ट्रल इमरजेन्सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनकम टैक्स आफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन, जो राज्यों के पुनर्गठन के बाद नागपुर ले जाये गये थे, दूसरी जगहों पर ले जाये जाने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** :(क) और (ख). सेन्ट्रल इमरजेन्सी रिलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इनकमटैक्स आफिसर्स ट्रेनिंग कालेज को नागपुर से बाहर इस कारण ले जाने का विचार है कि उनके लिए उपलब्ध जगह उनकी जरूरतों के मुकाबले में बहुत कम है। उस जगह के कुछ भाग की जरूरत हर साल राज्य सरकार को नागपुर में राज्य विधान मंडल के अधिवेशन के सम्बन्ध में पड़ती है। राज्य सरकार वह जगह लौटा देने के लिए प्रार्थना भी करती रही है। इसके अलावा, सेन्ट्रल इमरजेन्सी रिलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास जो जगह है वह उसकी जरूरत के माफिक नहीं है।

सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन दिल्ली में है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय, नयी दिल्ली के अधीन एक खंड कार्यालय है जो १९६० से नागपुर में काम कर रहा है। इस कार्यालय को नागपुर से हटाने का कोई विचार नहीं है।

हज यात्री

†१०५९. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री इम्बीचिबाबा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में प्रति वर्ष भारत के प्रत्येक राज्य से कितने यात्री हज यात्रा के लिये गये;

(ख) क्या केरल से बराबर यह मांग हो रही है कि कोचीन में हज यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जायें; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में भूमि विषयक विधान

†१०६०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेती के जोत के बारे में भूमि विषयक विधान अभी तक उड़ीसा में पारित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं और क्या उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग को यह सूचित कर दिया है कि यह विधान कब तक पूरा करने का उसका विचार है; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) दूसरे किन,किन राज्यों में ऐसे विधेयक विधानमंडल के पास अभी पड़े हुए हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख) उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० में खेती की जोत की अधिकतम सीमा के लिए उपबन्ध शामिल हैं । सितम्बर, १९६१ में एक संशोधनकारी विधेयक भारत सरकार के कुछ सुझावों के लिए व्यवस्था करने के लिए पेश किया गया था । इस विधेयक पर प्रवर समिति ने रिपोर्ट दी थी । विधान मंडल में इस संशोधनकारी विधेयक पर और आगे विचार इसलिए स्थगित कर दिया गया था कि केरल कृषि-संबंध अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभावों की छानबीन अभी बाकी थी । उड़ीसा सरकार अभी भी स मामले पर विचार कर रही है ।

(ग) दूसरे राज्यों में विधान की प्रगति ३०-३-१९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०१ के उत्तर में बतायी जा चुकी है ।

चुराई हुई मोटरगाड़ियां

†**१०६१. श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न राज्यों से चुरायी गयी मोटरगाड़ियां नेपाल में बहुत सस्ते दाम पर बेची गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) यह समाचार मिले हैं कि भारत से चुरायी गयी कुछ जीप गाड़ियां और मोटरगाड़ियां नेपाल ले जायी गयी हैं । फिर भी सरकार को यह जानकारी नहीं है कि ये गाड़ियां नेपाल में बहुत सस्ते दाम पर बेची गयी हैं या नहीं ।

(ख) इस मामले की ओर नेपाल सरकार का ध्यान दिलाया गया है । बिहार पुलिस भारत-नेपाल सीमा के भारतीय इलाके में काफी निगरानी रख रही है ताकि अनधिकृत माल जिसमें चुरायी हुई मोटरगाड़ियां शामिल हैं, नेपाल न ले जाया जा सके ।

हौजरी उद्योग

†**१०६२. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होजरी उद्योग की समस्याओं और कठिनाइयों का सर्वेक्षण करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट संभवतः कब तक सरकार को पेश कर दी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि वह अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट जुलाई, १९६२ के अन्त तक पेश कर देगा ।

---

† मूल अंग्रेजी में

बीकानेर में कांच के सामान का कारखाना

१०६३. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बीकानेर नगर में एक कांच के सामान का कारखाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कारखाने को पुनः चालू करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कारखाने को चलाने के लिये सरकार के पास प्रार्थना-पत्र आये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन फर्मों व कम्पनियों के प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथाशीघ्र सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र

१०६४. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राजस्थान में कितने आकाशवाणी केन्द्र खोले जायेंगे और कहां-कहां खोले जायेंगे;

(ख) उक्त आकाशवाणी केन्द्रों के प्रत्येक भवन पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा; और

(ग) ये केन्द्र कब से चालू हो जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) राजस्थान में निम्नलिखित पांच रिले ट्रांसमीटर लगाने की तजवीज़ है :—

बीकानेर .	१० किलोवाट मीडियम वेव
उदयपुर	५ किलोवाट मीडियम वेव
जोधपुर . .	१ किलोवाट मीडियम वेव
जयपुर .	१ किलोवाट मीडियम वेव
अजमेर	१ किलोवाट मीडियम वेव

(ख) बीकानेर में लगने वाले ट्रांसमीटर के भवन पर खर्च का अनुमान २.७५ लाख रुपये है और उदयपुर में लगने वाले ट्रांसमीटर के भवन पर २.८३ लाख रुपये । अन्य केन्द्रों पर नये भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) आशा है कि ये ट्रांसमीटर क्रमशः अगले दो वर्ष में चालू हो जायेंगे ।

सिंघभूम में यूरेनियम की खानें

†**१०६५. डा० उ० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सिंघभूम जिले के उन निष्कासित व्यक्तियों को जिन की जमीनें जादुगुड़ा यूरेनियम खानों के लिए ले ली गई हैं, कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्षतिपूर्ति की दर क्या है ; और

(ग) अब तक कुल कितनी क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) क्षतिपूर्ति की दर जमीन की किस्म के अनुसार अलग अलग है । बिहार के सिंघभूम जिले में इछरा और मेछाऊ गांवों में अब तक जो जमीनें ले ली गई हैं, उन के लिये रैय्यत के हितों के देय निर्धारित मूल्य इस प्रकार हैं:--

जमीन का ब्यौरा	प्रति एकड़ दर रुपये
धान १	१,७६४
धान २	१,४११
धान ३	८८२
गोरा १	८८२
गोरा २	२६५
गोरा ३	८८
परती जमीन	४४

(ग) १९६० में २५२.९२ एकड़ जमीन ले ली गयी थी जिस के लिए जमीन मालिकों के देय क्षतिपूर्ति की मद में बिहार सरकार के पास २,५५,७८४ रुपये की रकम जमा कर दी गई थी । इस में से २,४१,९५५ रुपये की रकम राज्य सरकार ने सम्बन्धित पार्टियों को वास्तव में दे दी है ।

इस के अलावा ८२,५७९ रुपये की रकम उस क्षेत्र में और १२.४६ एकड़ जमीन ले लेने के लिये राज्य सरकार को दे दी गयी है ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†**१०६६. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय श्रम सम्मेलन के २०वें अधिवेशन की सभावित तारीखें, स्थान और कार्यसूची क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (भारतीय श्रम सम्मेलन नई दिल्ली में ७ से ९ अगस्त, १९६२ तक होने वाला है । संबंधित हितों से कार्यसूची में रखने के लिए अपने-अपने सुझाव भेज देने के लिए कहा गया है ।

तीसरी योजना के लिये पंजाब में उद्योगों के लिये आवंटन

†**१०६७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब के उद्योगों के लिए मूल योजनायें आवंटित रकम बदल दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) 'उद्योग' मद के अधीन पंजाब के लिये तीसरी योजना में पहले कितनी रकम रखी गई थी ;

(घ) क्या किसी अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी ; और

(च) यदि नहीं, तो तीसरी योजना में रखी गई रकम में रद्दोबदल किये बिना ये परिवर्तन किस प्रकार कार्यान्वित किये गये हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं । मूल योजना में आवंटित रकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १४.४ करोड़ रुपया ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

साबुन का उत्पादन

†१०६८. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली से चलने वाले और न चलने वाले कारखानों में अलग अलग कितना साबुन तैयार किया गया ;

(ख) बिजली से चलने वाले और बिजली से न चलने वाले कारखानों से क्रमशः केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी रकम वसूल हुई ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अर्थात् बिजली से चलने वाले और बिजली से न चलने वाले कारखानों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या साबुन उद्योग विदेशों से मंगाया गया कोई कच्चा माल भी काम में लाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस के लिये बिजली से चलने वाले और बिजली से न चलने वाले कारखानों को कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : क) से (ग). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

(घ) जी नहीं ।

(ङ) बिजली से चलने वाले कारखाने

अवधि :	अप्रैल, '६० से मार्च, '६१	६५४.३८ लाख रुपये
	अप्रैल, '६१ से मार्च '६२	४८०.१५ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

बिजली से न चलने वाले कारखाने

अवधि :	अप्रैल '१९६० से मार्च, '१९६१	२५.७६ लाख रुपये ।
	अप्रैल, '१९६१ से मार्च '१९६२	१९.३० लाख रुपये ।

(**) उपर्युक्त जानकारी उन कारखानों के सम्बन्ध में है जो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा की पुस्तकों पर दर्ज हैं।

योजना की परियोजनाओं पर खर्च

†१०६९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो परियोजनाएं योजना में शामिल हैं और जो शामिल नहीं हैं उन दोनों पर खर्च में परस्पर क्या अनुपात है ; और

(ख) विकास परियोजनाओं पर राजस्व से किये जाने वाले खर्च और पूंजी खाते से किये जाने वाले खर्च का क्या अनुपात है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) और (ख). चूंकि यह मालूम नहीं है कि यह प्रश्न किस अवधि या क्षेत्रों के लिये है इसलिये मांगी गयी जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

मध्य प्रदेश का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†१०७१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीब दो साल पहले नैशनल कौन्सिल आफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च ने मध्य प्रदेश का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया था और १० वर्षीय औद्योगीकरण कार्यक्रम का सुझाव रखा था ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की स्थूल रूपरेखा क्या है ; और

(ग) वह कार्यक्रम इस बीच कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आकाशवाणी के 'स्टाफ आर्टिस्ट'

†१०७२. { **श्री अब्दुल गनी गोनी** :
बख्शी अब्दुल रशीद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कुल कितने स्टाफ आर्टिस्ट हैं ;

(ख) उन की ग्रेड और फीस क्या है ; और

(ग) क्या वे ठेके के तौर पर काम करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) १७२७ (३१ मार्च, १९६२ को) ।

(ख) प्रोग्राम प्रोडक्शन स्टाफ के लिए

	रुपये
असिस्टैण्ट प्रोड्यूसर	३००–६००
प्रोड्यूसर .	४५०––८००
डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर .	८००––११००
कन्डक्टर, वाद्यवृन्द	१०००––१२५०
चीफ प्रोड्यूसर	१०००––१५००

दूसरे स्टाफ आर्टिस्ट के लिए

१००––३०० रुपये
२५०––५०० रुपये
४५०––७५० रुपये
७५० और ऊपर

(ग) जी हां ।

भारत सरकार के मुद्रणालय में पदों की श्रेणियां

†१०७३. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में भारत सरकार के मुद्रणालय में पदों की कितनी विभिन्न श्रेणियां हैं ;

(ख) प्रत्येक पद के कितने प्रतिशत स्थान सीधी भर्ती से भरे जाते हैं ;

(ग) प्रत्येक पद के कितने प्रतिशत स्थान पदोन्नति दे कर भरे जाते हैं और यह पदोन्नति किन पदों से की जाती है ; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी के पद की भर्ती व पदोन्नति के लिये समितियों का गठन किस प्रकार किया जाता है ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (घ). चूंकि पदों की लगभग १३५ श्रेणियां हैं इसलिये जानकारी इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा और परिश्रम करना होगा । यदि किसी श्रेणी विशेष के बारे में जानकारी अपेक्षित हो तो वह इकट्ठा की जा सकती है ।

कम्पोजीटरों के वेतन-क्रम का संशोधन

†१०७४. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में भारत सरकार के मुद्रणालय के कम्पोजीटरों के वेतन-क्रम के संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है क्योंकि कम्पोजिटरों को वह अधिकतम वेतन दिया जा रहा है जिसकी सिफारिश वेतन आयोग ने की थी।

भारत सरकार का मुद्रणालय, नई दिल्ली

†१०७५. श्री नम्बियार : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के प्रत्येक अनुभाग और शाखा में पदों की कितनी श्रेणियां हैं ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९६/६२]

भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१०७६. श्री नम्बियार : क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मुद्रणालय के विशेष संग्रह (पूल) में कितने क्वार्टर तथा किस प्रकार के हैं और वे कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या प्रेस के कर्मचारियों के लिये शहर के बाहरी क्षेत्र में और क्वार्टर बनाने का इरादा है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) क्वार्टर का प्रकार	मिण्टो रोड क्षेत्र	नेताजी नगर	श्री निवास पुरी	योग
१. 'सी' टाइप क्वार्टर	१	—	—	१
२. 'डी' टाइप बंगला	१	—	—	१
३. 'बी' टाइप पुराना	१	—	—	१
४. 'सी' टाइप नया	१	—	—	१
५. 'सी' टाइप पुराना	३	—	—	३
६. 'डी' टाइप नया	९	—	—	९

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्वार्टर का प्रकार	मिण्टो रोड क्षेत्र	नेताजी नगर	श्रीनिवास पुरी	योग
७. 'डी' टाइप पुराना	९८	—	—	९८
८. 'ई' टाइप पुराना	५४	—	—	५४
९. 'एफ' टाइप पुराना	९६	—	—	९६
१०. 'जी' टाइप	८०	९६	१९९	३७५
११. 'दफ्तरी' टाइप	१३७	—	—	१३७
१२. 'प्यून' टाइप	६३	—	—	६३
१३. 'एच' टाइप	—	१०४	३०	१३४
१४. 'स्वीपर' टाइप	८	—	—	८
	५५२	२००	२२९	९८१

(ख) नई दिल्ली में भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिये मिण्टो रोड क्षेत्र में और क्वार्टर बनाने का इरादा है।

विदेशों के बच्चों के लिये उपहार

†१०७७. **श्री राम सेवक यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने प्रधान मन्त्री की हैसियत से गत दस वर्षों में विदेशों के बच्चों को किस प्रकार के उपहार भेजे हैं; और

(ख) उन देशो के नाम क्या हैं और उन्हें प्रत्येक वर्ष क्या उपहार भेजे गये ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). विदेशों के बच्चो से प्रार्थनायें प्राप्त होने पर प्रधान मन्त्री उन्हें समय-समय पर उपहार भेजते रहे हैं। ये उपहार आम तौर पर गुड़िया, किताबें, चित्र, फोटोग्राफ, टिकट, सिक्के आदि होते हैं जो ज्यादा कीमती नहीं होते। ऐसे उपहारों का कोई विस्तृत रिकार्ड नहीं रखा जाता। इस जानकारी को इकट्ठा करने में जितना समय और श्रम लगेगा उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। किन्तु कुछ अवसरों पर कुछ देशों के बच्चो को हाथी, और शेर के बच्चे जैसे जानवर भेजे गये थे।

हुगली पोत चालकों के बारे में

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैंने कलकत्ता में हड़ताल के बारे में सूचना दी थी। वहां पर नई परिस्थिति पैदा हो रही है। लगभग ११ नदी पोत सह-चालकों ने इस्तीफा दिया है। क्या माननीय मन्त्री इस विषय पर वक्तव्य दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझ इस पर एतराज है। मैंने पहले ही माननीय सदस्यों से कहा हुआ है कि यदि सूचनाओं पर मेरे फैसलों पर उन्हें कोई ऐतराज हो तो मेरे कक्ष में आ जाएं और मुझे सभी कुछ बताने की कोशिश करें। यदि मैं उनसे सहमत हो जाऊंगा, तो वह मामला सदन में रखा जाएगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैंने इस का उलंघन नहीं किया है। मुझे कोई कारण नहीं बताया गया। मुझे आधे घण्टे की चर्चा उठाने के लिय कहा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं यहां पर कारणों पर बहस नहीं करूंगा। इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। इस तरह नहीं करना चाहिये। क्या मन्त्री महोदय वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** इस सम्बन्ध में कुछ दिन हुए मैंने एक विस्तृत वक्तव्य दिया। इसी दौरान में पत्तन न्यास के सभापति यहां आए और हमने उनके साथ इस विषय पर चर्चा की।

जहां तक इस विषय विशेष का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण लेने वाले नदी-पोत सहचालक कोई वर्ग नहीं है। हम इस विषय पर सूचना प्राप्त करेंगे, और वह जानकारी यथा समय में देंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जैसे 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कहा गया है, मुझे पता नहीं कि क्या नदी-पोत सहचालक प्रशिक्षण ले रहे हैं। बन्दरगाह सहाधिकारी (हारबर मास्टर्ज) हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भूतपूर्व अंग्रेज पोत चालकों को इन जहाजों को चलाने के लिये लगाया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर :** हमें तो पत्तन में काम चालू रखने के लिये कुछ कदम उठाने हैं। पोत सह-चालक तो नहीं है। बन्दरगाह सहाधिकारी हैं। उनका मामला तो बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं कि यदि हुगली पोत चालकों को कोई वेतन-अन्तर दिया जाता है, तो यही उनकी शिकायत रहेगी इसलिये परिस्थिति खराब है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी।

श्री बागड़ी (हिसार) : स्पीकर साहब, मेरी तो सिर्फ इतनी अर्ज़ थी कि जनाब ने इस सदन में कहा था कि एजर्नमेंट मोशन के बजाय कालिंग अटेन्शन नोटिस दिया जाय। आज मैंने कालिंग अटेन्शन नोटिस दिये, तो उसके जवाब में एक सज्जन मुझे कह कर गये हैं कि उसके बारे में मैं क्वस्टियन का नोटिस दूं। मैं अर्ज़ करूंगा कि एजर्नमेंट मोशन से तो कालिंग अटेन्शन नोटिस आया और कालिंग-अटैन्शन नोटिस से क्वस्टियन आया। (interruptions) मैं पूछना चाहता हूं कि एक बारात के गाड़ी में लूटे जाने से अहम सवाल इस सदन में और क्या हो सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह विषय प्रश्न के लिये ही उचित है गाड़ियों में चोरी और डाके इत्यादि के मामले स्थगन प्रस्तावों द्वारा नहीं उठाए जाने चाहियें। यदि माननीय सदस्य जो वह चाहें कहें तो हम सदन की कार्यवाही को नहीं चला सकेंगे।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि अभी आपने जो यह फरमाया कि जो एजर्नमेंट मोशन या कालिंग अटैन्शन नोटिस अस्वीकार कर दिये जायें, उन के बारे में आप से मिल लिया जाये, लेकिन जब आप उन्हें अस्वीकार ही कर देंगे, तो फिर आपसे किस लिए मिलें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं इसका जवाब देता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : आप मेरी पूरी बात सुन लें। तभी उसका उत्तर मिल सकेगा। आपने ट्रेन में राबरी वगैरह के विषय पर कालिंग अटेन्शन नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। माननीय सदस्य ने ट्रेन में बारात के लूट लिये जाने की तरफ ध्यान दिलाया है। इस तरह की और भी बहुत सी घटनायें हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सिर्फ आप के जवाब की ही ज़रूरत नहीं है। हम उसके बारे में यहां पर बहस करना चाहेंगे और मन्त्रालय की तरफ से दिया गया उत्तर सुनना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई दफ़ा आप को कहा है--और किसी भी मेम्बर को इस में शक नहीं है--कि मेरे सामने जो नोटिस होता है, मैं उस पर फैसला लेता हूं। उसके बाद अगर मेम्बर साहब मेरे पास आ जायें और मुझे इस बात का यकीन दिला दें कि मेरा फैसला ग़लत है, तो मैं उसको बदलने के लिए तैयार हूं। क्या वह इतना भी बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं कि वह मेरे कमरे में आकर मुझ से बात करें ? यहां पर खड़े होकर मेरे फ़ैसले को चैलेंज करना और बयान देना बहुत नामुनासिब है। मैंने आपसे कहा है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, माननीय सदस्य मेरे कमरे में आ सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। अगर मैं मुनासिब समझूंगा, तो मैं ज़रूर उसको यहां पर पेश करने दूंगा।

तीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाएं आई हैं।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** जब मैं बोल रहा हूं तो उन्हें बैठ जाना चाहिये।

श्री बागड़ी : मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता चाहता हूं कि. . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को कुछ नियमों और अनुशासन का पालन करना चाहिए।

श्री बागड़ी : मैं पूछना चाहता हूं कि. . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** थोड़े दिनों में मैंने देखा है कि माननीय सदस्य को इन बातों में प्रसन्नता मिलती है।

श्री बागड़ी : हिन्दी में समझा दीजिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

चीनी वाणिज्य दूतावास कालिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय :** कैलिमपोग में चीनी व्यापार अभिकरण में आग के बारे में श्री, श्री ब्रजराज सिंह, श्री लहरीसिंह, श्री हेम बरुआ और श्री रामसेवक यादव के नाम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाएं है। क्या माननीय प्रधान मन्त्री जी के पास सदन को जानकारी देने के लिये है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। हम जांच करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह तो अखबारों में आया है। जब कभी देश की सुरक्षा से सम्बन्धित कोई ऐसा मामला होता है, सदस्यों ने सम्बन्धित मन्त्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अब यह जानकारी है कि भारतीय पुलिस के सदस्य पर गोली चलाई गई। प्रधान मन्त्री जी कहते हैं कि उन्हें इस के बारे में कुछ पता नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : आपने और सहकारी सदस्यों ने यह जानकारी समाचार पत्रों से ली है। सरकार भी इस बात का पता लगा रही होगी। जब उनके पास जानकारी होगी तो वे दे देंगे।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : इस घटना को घटे एक महीना हो गया है, श्रीमन्

†श्री हेम बरुआ : इस का मतलब यह हुआ कि अखबारों के पास सरकार से अधिकतर अच्छे जानकारी के साधन हैं।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : अखबारों ने कहा कि इस घटना को एक महीना हो गया और सरकार के लिये काफी समय था।

†श्री हेम बरुआ : हमें यह जानकारी प्राप्त करने के लिये सहायता दीजिये।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पता है कि सरकार से जानकारी लेने के क्या तरीके अपनाने चाहियें।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस के विषय में कुछ पता नहीं। मैं पता कर सकता हूं और यदि यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी, तो मैं सदन को बता दूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व विषय की ओर ध्यान दिलाना

मद्रास में छपाई के कागज की कमी

श्री उमानाथ (पुदुक्कोट्टई) : नियम, १५७ के अन्तर्गत मैं उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :—

"मद्रास में छपाई के कागज की कमी से पैदा हुई स्थिति"।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : अब मद्रास शहर में छपाई के कागज की कमी नहीं है। कागज के कारखाने पहले की तरह कागज देते हैं। पिछले महीने कलकत्ता-मद्रास रेलवे लाइन पर जो दुर्घटना हो गई उस के कारण उस लाइन पर आने जाने में गड़बड़ हो गई। थोड़े ही दिनों में साधारण यातायात चल पड़ा और रोहतास उद्योगों से कागज ले जाने के लिये डालमिया नगर से मद्रास तक विशेष गाड़ियां चला दी गई। यातायात में गड़बड़ी थोड़े दिनों के लिये थी। अब स्थिति ठीक है। मद्रास को कागज पहले की तरह जा रहा है और कमी के बारे में नहीं सुना है।

†श्री उमानाथ : क्या 'मद्रास मेल' में कागज की कमी के बारे में जो खबर थी उसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया गया है ?

†श्री कानूनगो : यदि अखबारों में यह खबर है तो सर्वथा गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय बायलर्स एक्ट के अन्तर्गत पुनरीक्षण आवेदन पत्र (प्रक्रिया) नियम, १९६१

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं श्री मेहर चन्द खन्ना की ओर से भारतीय बायलर्स ऐक्ट, १९२३ की धारा २८-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ में प्रकाशित पुनरीक्षण आवेदन पत्र (प्रक्रिया) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--९५/६२ ।]

सामान्य आय-व्ययक---सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय:** अब १९६२-६३ के सामान्य आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी रहेगी । २० घंटों में से १४ घंटे २५ मिनट खत्म हो गये हैं । ५ घंटे ५ मिनट बाकी रहते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : माननीय वित्त मंत्री कल भाषण दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे ४ बजे आरम्भ करके पांच बजे समाप्त कर सकते हैं । श्री विद्यालंकार ।

†**श्री अ०.ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर): वस्त्रों पर जो उत्पादन शुल्क लगा दिया है उस से गर्म कपड़े के उद्योग को जो कि हाथ करघा उद्योग है बहुत धक्का लगा है । अमृतसर और पंजाब के दूसरे क्षेत्र छोटे उद्योगों के कारण तो खुशहाल हुये हैं । ऊनी धागे और ऊनी कपड़ों पर १० प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाने के कारण हथ करघा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । इस समय अमृतसर में छोटे कारखानों में हड़ताल हो रही है । इस शुल्क का मोटे वस्त्र पर जो अधिकतर गरीब व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं, भी पड़ा है । इसलिये इस से, हथ करघा उद्योग और ऊनी उद्योग पर से शुल्क हटा देना चाहिये ।

उद्योगीकरण के विषय में पंजाब को यथोचित स्थान नहीं मिल रहा है । पंजाब में कोई भारी उद्योग नहीं है । पंजाब में भारी उद्योग के कुछ कारखाने होने चाहियें ।

विरोधी दल के सदस्यों ने बड़ी काली तस्वीरें पेश की हैं । यह कहा है कि देश प्रगति नहीं कर रहा है । गोपालन ने कहा है कि कांग्रेस के शासन में देश में समाजवाद नहीं लाया जा सकता । यदि कांग्रेस नहीं ला सकती तो और कौन लायेगा ?

यह बात सत्य है कि विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी तेजी से होना चाहिये । परन्तु विरोधी दलों ने निरुत्साह का वातावरण बना दिया है । इस लिये लोग देश के निर्माण में भाग लेने के लिये आगे नहीं आ रहे हैं ।

विकास के कार्य के लिये लोगों में जोश पैदा करना चाहिये । उन के सामने सही तस्वीर रखनी चाहिये ।

यह कहा गया है कि लोगों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसीं कही जाती है । यह कुछ हद तक ठीक है । परन्तु यह कहना कि लोगों की हालत अच्छी नहीं हो रही है, गलत होगा । राष्ट्रीय आय

---

†मूल अंग्रेजी में

का विभाजन ठीक नहीं है। परन्तु यह कहना कि लोगों की हालत पहले से अच्छी नहीं हुई है, उचित नहीं ।

मध्य आय वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है। थोड़ी आय वर्ग के लोग मध्य आय वर्ग के लोगों में शामिल हो रहे हैं ।

यह कहा गया है कि विदेशी पूंजी ने हमारी राजनैतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रभाव डाला है। यह गलत है । हम तो विदेशी पूंजी को विकास के लिये प्रयोग करते हैं।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : यह रेलवे बजट की तरह हौसले का बजट है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन पैदा करना वित्त मंत्री का उत्तरदायित्व है आम तौर पर यह कहा जाता है कि गरीबों पर अधिक से अधिक कर लगाये जाते हैं। यदि सब अमीरों की सम्पत्ति भी छीन ली जाये तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिये साधारण आदमी को भी यथा-शक्ति बोझ उठाना पड़ेगा।

जहां तक संसाधनों के खर्च का सम्बन्ध है यहां पर प्रशासन पर आलोचना की जा सकती है। अधिकतर कार्यकुशलता और फजूल खर्चे को बन्द करने की आवश्यकता है। संसद् का बजट पर आर्थिक नियंत्रण अधिक होना चाहिये । इस संसद् के आरम्भ में स्थायी वित्त समिति थी । यह महत्वपूर्ण समिति थी जिस ने बहुत अच्छी तरह काम किया। मैं वित्त मंत्री से इस पर विचार करने के लिये कहूंगा ।

मूल्यों के समर्थन के लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। परन्तु इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिये ।

उर्वरक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस पर लाभ नहीं उठाना चाहिये। "न लाभ, न हानि" के असूल पर ही उर्वरक बेचे जाने चाहियें। यदि मुनाफा उठाना भी हो तो भी उसे किसानों की बेहतरी पर ही खर्च करना चाहिये ।

भारत सेवक समाज, किसानों के लिये सहकारी बैंकें शुरू करने जा रहा है। इस बैंक में जीवन बीमा और अंश पूंजी को साथ साथ लिया जायेगा। हमारा जीवन बीमा की किश्त बहुत अधिक है। अब आम लोगों की सेहित अच्छी हो गई है। इसलिये जीवन बीमा की किश्त कम करनी चाहिये। यह मालूम करने के लिये कि क्या किश्तें अधिक नहीं हैं कोई समिति अथवा आयोग नियुक्त करना चाहिये । यदि जीवन बीमा की किश्तें कम कर दी जायें तो किसानों की सहकारी बैंकें बहुत अच्छा काम कर सकेंगी ।

हमारे कार्यालयों के कुछ पहलू और भी हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहूंगा हूं । सहकारी ऋण संस्थाओं ने काफी प्रगति की है। इनके द्वारा २४० करोड़ रुपये के ऋण बांटे गये हैं लेकिन यह राशि २,१०,००,००० व्यक्तियों में बांटी गई है जिसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रति व्यक्ति को औसतन . ११८ रुपये मिले। इनसे होता क्या है। अत: यह उधार एक प्रकार से कृषि के लिये उधार नहीं बल्कि घरेलू काम के लिये उधार समझा जायेगा। अत: ऋण की राशि बढ़ानी चाहिये वर्ना इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुये ही किसान सहकारी बैंक खोलने का प्रस्ताव रखा गया तथा इस प्रकार ऋण की मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। जब उनका बैंक हो जायेगा तो वे अधिक ऋण ले सकेंगे अथवा अधिक धन जमा कर सकेंगे। इसलिये सरकार इस बारे में विचार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने और समन्वय की जरूरत है। हमारे बेसिक शिक्षा, बहु-प्रयोजन स्कूलों आदि के प्रयोग जनता को हानि पहुंचा कर किये गये हैं। हम लक्ष्य कुछ निर्धारित करते हैं परन्तु करते सर्वथा भिन्न काम हैं। स्कूलों तथा संस्थाओं को समय पर सहायता नहीं मिलती। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम भी एक परीक्षा कम करने के लिये किया गया था किन्तु अब उसके स्थान पर दो परीक्षायें करनी पड़ती हैं।

†श्री महीडा (आनन्द) : स्वतन्त्र दल और उसकी नीतियों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा रहा है। वास्तव में स्वतंत्र और कांग्रेस दल में दो तीन बातों को छोड़ कर अन्य सभी बातों में बहुत साम्य है। जहां तक समाजवाद की बात है स्वतन्त्र दल इसके विरुद्ध नहीं है जैसा कि कहा गया है। यह तो केवल उस शब्द के विरुद्ध है जिसकी उचित उत्पत्ति पश्चिम में हुई है। हमारा देश तो मानवता का पक्षपाती है। हम तो साधारण व्यक्ति का समर्थन करते हैं और उसका पक्ष लेते हैं। कांग्रेस ने किसानों के प्रति जो नीति अपनाई है हम तो उस का विरोध करते हैं। हम तो सहकारी कृषि के विरुद्ध हैं। मैंने गांवों का भ्रमण किया है और सैंकड़ों ऐसी सहकारी संस्थायें देखी हैं जो ऋणग्रस्त हैं। जनता उससे छुटकारा चाहती है। इसी प्रकार सहकारी फार्म भी घाटे में चल रहे हैं और किसान उनसे अलग होना चाहते हैं।

कांग्रेस हमारे दल की आलोचना करती है। हम भी कांग्रेस के विरुद्ध हैं। हम कांग्रेस में साम्य-वाद और राज्यसत्तावाद के विरुद्ध हैं। कांग्रेस की इस नीति से देश को बहुत हानि होगी।

हम चाहते हैं कि देश में आज जो गरीबी व्याप्त है वह दूर हो जाये। हम चाहते हैं कि लोगों का जीवनस्तर अच्छा हो। इस सम्बध में कांग्रेस ने जो नीति अपनाई है उससे हम सहमत हैं। सरकार की इस नीति के भी हम विरुद्ध हैं कि वह धनी लोगों को लूटकर निर्धन बना रही है। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमारा विचार तो यह है कि उन पर जितने चाहे उतने कर लगायें किन्तु उनको मारिये नहीं।

समाजवाद के नाम पर सरकार कुछ और ही काम कर रही है। हमारा दल भारी उद्योगों के विरुद्ध है क्योंकि हम समझते हैं कि धन को अपने गांवों में शिक्षा, बिजली, पानी आदि सुविधाओं की व्यवस्था में लगाना अधिक उपयोगी है। भारी उद्योगों की खातिर कृषि की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। मेरे विचार से शिक्षा और कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहियें।

जहां तक सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों की बात है हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र का काम बहुत निराशाजनक रहा है। उदाहरण के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाज नहीं बेच सका क्योंकि विदेशों में वे कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। १९६०–६१ तक उसे ४५६ करोड़ रुपये की राज सहायता दी गई। सिंदरी उर्वरक कारखाना हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न अन्य उपक्रमों में भी बहुत भारी घाटा हो रहा है तथा इन सब का भार गरीब आदमी को वहन करना पड़ता है। यदि देश में समाजवाद की स्थापना करनी है तो गैर सरकारी क्षेत्र को भी काम करने का अवसर मिलना चाहिये। सरकारी क्षेत्र जनता पर थोपने नहीं चाहियें।

वैसे तो सत्तारूढ़ दल समाजवाद की बात करता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि वे लोग बात साधारण करते हैं परन्तु रहते ऊंचे ढंग से हैं। जबकि देश के एक भाग में मीलों दूर तक पीने

†मूल अंग्रेजी में

का पानी भी नहीं मिलता, सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में 'वाटर कूलर' और एयर कन्डीशनर लगाये जा रहे हैं।

अब वह समय आ गया है जबकि कांग्रेस तथा स्वतंत्र दल में मुकाबला होगा। हम प्रतिक्रियावादी नहीं हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि देश का उत्तर और दक्षिण में विभाजन हो। स्वतंत्र दल एक राजनीतिक दल है।

जहां तक बजट की बात है, मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। लेकिन मैं उन से निवेदन करता हूं कि चाय तथा तम्बाकू जैसी वस्तुओं पर कर के सम्बन्ध में वह फिर से विचार करें। गुजरात राज्य में तम्बाकू एवं चाय की खपत बहुत है। यदि उन पर अधिक कर लगाया गया तो गुजरात राज्य पर काफ़ी भार पड़ जायेगा।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जन साधारण की शिक्षा, उनके जीवनस्तर को ऊंचा उठाने और कृषि को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। उद्योगों को भी महत्व मिले किन्तु इतना नहीं जितना कि कृषि और शिक्षा को मिले।

श्री वीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : यद्यपि भारत के अधिकांश समाचारपत्र साम्यवादी दल की नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं, तो भी इस बार हमारे देश के नेता श्री अ० क० गोपालन की नीतियों और सुझावों का सभी समाचारपत्रों ने स्वागत किया है।

उन्होंने जो सुझाव रखे हैं उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं : बैंकिंग संस्थाओं, खनन उद्योग, निर्यात व्यापार, बागान, भारी मशीनों इत्यादि का राष्ट्रीयकरण किया जाय। विदेशी पूंजी लगाने वालों तथा भारत से लाभ की राशि बाहर भेजने पर रोक लगायी जाय। धनी व्यक्तियों पर विशेषतः निगम कर में वृद्धि की जाय। कर अपवंचन तथा सरकारी प्रशासन में अपव्यय को रोका जाय और सरकार तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोका जाय।

मैं आशा करता हूं कि इन सुझावों को क्रियान्वित करने से राष्ट्रीय परिपक्वता आयेगी और वित्त मंत्री इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देंगे।

संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के नाम पर किया जाने वाला व्यय बढ़ता जा रहा है तथापि यदि आप व्यय की जांच करें तो आप को ज्ञात होगा कि योजना के अतिरिक्त व्यय में वृद्धि होती जा रही है।

त्रिपुरा प्रशासन से प्रकाशित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कृषि की उत्पादन दर घटती जा रही है। किसानों पर ऋण बढ़ता जा रहा है। तथा परिवहन का कोई साधन नहीं है और वहां खाद्यान्न इसी कारण बहुत महंगे हैं।

हम लोग बहुत समय से यह मांग कर रहे हैं कि त्रिपुरा में एक रेलवे लाइन बनायी जाय लेकिन इस ओर कुछ नहीं किया गया है। डम्बोरो झरने से बिजली पैदा करने की संभावनायें हैं तथापि अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। वहां उद्योगों के विकास के लिये कोई कोयला भी नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार त्रिपुरा के उपेक्षित प्रदेश का ध्यान रखेगी। त्रिपुरा का प्रशासन सीधे केन्द्र से होने के कारण इस सम्बन्ध में सरकार आसानी से कदम उठा सकती है।

[श्री बीरेन दत्त]

यद्यपि सरकार ने वहां एक क्षेत्रीय परिषद् की स्थापना की है तथापि इससे प्रशासन के काम में वैधता उत्पन्न हो गयी है। हम चाहते हैं कि वहां के लिये एक विधान सभा की स्थापना की जाय। यह ज्ञात हुआ है कि वहां विधान परिषद् की स्थापना इस कारण नहीं की जा रही है कि वहां की जनता बहुत गरीब है यदि यह बात है तो यह गलत है मैं चाहता हूं कि क्षेत्रीय परिषद् की शक्तियां बढ़ाने के स्थान पर वहां विधान परिषद् की स्थापना की जाय।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज से १० वर्ष पूर्व त्रिपुरा में १५,००० से अधिक जनसंख्या वाला एक भी शहर नहीं था। अब वहां कई नगरों की जनसंख्या १,००,००० से अधिक और कई नगरों की जनसंख्या ३०,००० से अधिक है। तथापि वहां की जनता के लिये न तो कोई रोजगार है और न ही कोई उद्योग धंधा। यदि इस जनसंख्या को रोजगार के साधन नहीं दिये जायेंगे तो इससे लोगों में अपराध वृत्ति बढ़ेगी जिसके घातक परिणाम होंगे।

श्री राम सेवक यादव (बाराबांकी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिंड आज सुबह हम लोगों को राष्ट्रपति भवन से एक पत्र मिला है कि १३ तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को आप लोग नेशनल ड्रेस में आयें। और नेशनल ड्रेस बताया गया है चूड़ीदार पाजामा और अचकन। वह सदस्य जो धोती कुरता पहनते हैं उनके लिये बड़ी मुश्किल होगी और हम तो इसे राष्ट्रीय पोशाक नहीं मानते। वह तो मुगल दरबार की पोशाक है जिसे शाहजहां का तबलची पहनता था। तो हम लोग क्या करें।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : नेशनल ड्रेस के लिये यह कहना कि उसे शाहजहां का तबलची पहनता था उचित नहीं। इसको एक्सपंज किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : यह परिपत्र गृह मंत्रालय ने जारी किया है अतः इसका हम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री पाराशर** (शिवपुरी): मैं वित्त मंत्री के प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। हमें इस बात से हर्ष हुआ है कि उन्होंने उपभोक्ता सहकारिताओं को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया है मुझे विश्वास है कि इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में रोक लगेगी।

मेरा सुझाव है कि व्यय कर के साथ नमक उपकर भी हटा दिया जाय। इससे सरकार पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा लेकिन जनता को बहुत राहत मिलेगी।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी भी देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पीने का पानी लाने के लिये वहां की स्त्रियों और बच्चों को मीलों तक जाना होता है। और तब कहीं जाकर उन्हें पानी मिल पाता है। मुझे ज्ञात हुआ सरकार के पास एक राष्ट्रीय जल संभरण योजना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसके द्वारा उक्त गांवों को सहायता दी जाय।

जहां तक आवास समस्या का प्रश्न है यदि इस समस्या का हल करने के लिये सहकारी आन्दोलन की सहायता ली गयी तो काफी सहायता मिल सकती है विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में आवास समस्या का हल दूर करने के लिये यह सब से अच्छा साधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्यप्रदेश के उत्तरी भागों में विधि और व्यवस्था की दशा बहुत शोचनीय है। वहां चोर डाकुओं का इतना भय है कि लोग सुरक्षापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी नहीं सकते हैं। मेरे विचार से इस स्थिति का शीघ्रता से निराकरण किया जाना चाहिये।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार की आपत्ति का सामना करने की क्षमता हमारे देश में बहुत कम है। अभी हाल गोआ कार्रवाही में जब थोड़ी सी फौजों को दक्खिन जाना पड़ा था तो भारत की सारी परिवहन व्यवस्था बिगड़ गयी थी इतना ही नहीं अपितु ग्वालियर से दिल्ली तक जाना भी असंभव हो गया था। यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाय तो भगवान जाने क्या अवस्था होगी अतः प्रतिरक्षा मंत्रालय को चाहिये कि मध्यप्रदेश से सीधे बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान व पंजाब को मिलाने वाले अन्य संचार साधनों का विकास करना चाहिये।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग में और विशेषतः लोकतंत्रीय समाज और शासन व्यवस्था वाले देश में जो बहुत बड़े पैमाने पर योजनाओं के दौर से गुजर रहा है, बजट हमारी ऐस्टिमेटेड आय और व्यय का ब्यौरा नहीं हुआ करता है। बजट हमारी सरकार की नीति की एक ठोस तस्वीर हुआ करता है। मैं श्री मुरारजी देसाई के बजट भाषण पर इसी नुक्तेनिगाह से गौर करना चाहती हूं। यूं तो इस सदन में और सदन के बाहर देश के कोने कोने में इस बजट की चर्चा ही नहीं हुई है इस पर बड़ा विवाद चल रहा है और उद्योगपतियों ने, चैम्बर आफ कामर्स ने इस की तीव्र आलोचना भी की है। उन के कहने में, उपाध्यक्ष महोदय, चंद बातें महत्व की भी हैं। हमारे देश की मिक्सेड एकोनामी में पब्लिक सैक्टर के साथ प्राइवेट सैक्टर (गैर सरकारी क्षेत्र) भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और फौरेन ऐक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) प्राप्त करने वाली वस्तुएं जैसे चाय, जूट, लौह इत्यादि प्राइवेट सैक्टर में अवस्थित हैं। ऐसी परिस्थिति में उन के ऊपर टैक्स का बोझ लादने का अंजाम यह होगा कि कैपिटल शाई हो जायगा और उस का बुरा प्रभाव एम्पलायमेंट और उद्योगों के विकास पर पड़ेगा। उन का यह भी कथन है कि जिन शेयर्ज़ पर पिछले पांच सालों में वैल्थ टैक्स से मुक्ति थी, उन पर टैक्स लादने का अंजाम कैपिटल फ़ार्मेशन के लिए बुरा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि कार्पोरेशन टैक्स में पांच प्रतिशत वृद्धि का बजट परस्पर-विरोधी बजट है, क्योंकि जहां उस में ईक्विटी कैपिटल पर ज़ोर दिया गया है और कार्पोरेशन-पूंजीको ब्राड-बेस्ड बनाने की बात कही गई है, वहां उस पर टैक्सिज़ का बोझ भी लादा गया है।

हमारे देश की फ़ारेन-एक्सचेंज की स्थिति असंतोषजनक है। श्री जी० एल० मेहता ने कहा है कि कीमतों की सतह की ऊंचाई के कारण हम आज एक्सपोर्ट मार्केट खोते जा रहे हैं। पता नहीं कि वित्त मंत्री साहब ने निर्यात के लिए जो सुविधायें प्रदान की हैं, वे कहां तक समुचित हैं। इस के सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। लेकिन फिर भी मैं इतना देखती हूं कि आज इन प्रतिवादों के बावजूद मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के शेयर-मार्केट्स में खुशियां मनाई जा रही हैं और बम्बई स्टाक एक्सचेंज के प्रैज़िडेंट, श्री के० आर० पी० शराफ़ ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह एक परपज़फुल बजट है।

जो भी हो, मैं वित्त मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने डायरेक्ट टैक्सिज़ का बोझ ३ करोड़ से २७ करोड़ बढ़ा दिया है। आज तक डायरेक्ट टैक्सिज़ के मामले में समाजवादी दृष्टिकोण से हम आलोचना के पात्र रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि वित्त मंत्री महोदय इस २७ करोड़ की रकम को बढ़ा कर कुछ और अधिक कर देते।

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

लेकिन इस बात पर ग्राश्चर्य है कि एक्सपेंडीचर टैक्स को क्यों खत्म कर दिया गया है। कैम्ब्रिज के समाजवादी ग्रर्थशास्त्रीतिज्ञ, श्री कैल्डर, ने एक्सपेंडीचर टैक्स को वैल्थ टैक्स के रोल में लाया था, इसलिए कि इनकम टैक्स ग्रौर एक्सपेंडीचर टैक्स के सहारे वेल्थ टैक्स को नापा जा सके।

खैर, जो भी हो, इस बजट की चन्द खूबियां भी हैं, जिन पर सारे देश के लोगों को सन्तोष भी हुग्रा है ग्रौर वे हैं दवा-दारू के सम्बन्ध में, वेतन ग्रौर पेन्शन के सम्बन्ध में, जहां इनकम टैक्स ५ परसेंट से ढाई परसेंट कम किया गया है, निर्यात के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में, डफ़िसिट को पूरा करने के सम्बन्ध में ग्रौर भारत के चन्द नये नये उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, जहां विदेशी इस्पात, लोहे, मोटर-गाड़ियों ग्रौर बनावटी रेशम के ग्रायात पर रुकावट डाली गई है।

वित्त मंत्री के शब्दों में ही इस बजट के जो चन्द मुख्य पहलू सतह पर ग्राते हैं, वे ये हैं—— नेशनल ग्राय में इज़ाफ़ा, प्राइस लाइन को होल्ड कर के रखना, निर्यात को प्रोत्साहन देना ग्रौर उद्योगों का विकास। मैं चाहूंगी कि वित्त मंत्री महोदय के बजट के ये चारों लक्ष्य पूरे हों। लेकिन जब मैं इस बजट के भीतर जाती हूं, तो समाजवादी उद्देश्यों ग्रौर लक्ष्यों को देख नहीं पाती हूं। राष्ट्रपति जी ने भी ग्रपने भाषण में समाजवादी प्रोग्रामों की चर्चा की थी ग्रौर हमारे इलेक्शन मेनिफेस्टो का भी ग्राधार यही है। लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने ग्रपना बजट पेश करते समय राज्य सरकारों को यह चेतावनी दी है कि वे शीघ्रता से ग्रपने ग्रपने राज्यों में ग्रतिरिक्त कर लगायें, उसपर बहुत ग्राश्चर्य होता है। ग्रब समझ में नहीं ग्राता कि ग्रौर कौन कौन से नये करों का शुभारम्भ हमारे देश में होने वाला है। फिर भी यह खुशी की बात है कि वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्सिज़ को बढ़ाया है।

लेकिन डायरेक्ट टैक्सिज़ के साथ साथ इनडाइरेक्ट टैक्सिज़ के बोझ में, जोकि ५७.५ करोड़ था, उस में ४४.५ करोड़ की ग्रौर वृद्धि की गई है। मैं नहीं समझती कि इस प्रकार के डायरेक्ट टैक्सिज़ ग्रौर इनडायरेक्ट टैक्सिज़ के संतुलन को हम समाजवाद कह सकते हैं।

जहां तक एक्साइज़ ड्यूटी का सवाल है इस सदन के सदस्यों ने भी उस तरफ़ संकेत किया है ग्रौर मैं भी कहूंगी कि चाय, तम्बाकू, दियासलाई, बर्तन ग्रौर कपड़े ग्रादि छोटी छोटी चीजें उस की लपट में ग्रा गई हैं, जिन का सीधा सम्बन्ध देश के निम्न ग्रौर मध्यम श्रेणी के लोगों से है। ये मध्यम श्रेणी के लोग ग्राज़ादी की लड़ाई में, निर्माण के युग में ग्रौर समाज के हर पहलू में ज़िन्दगी ग्रौर मौत के बीच झूलते रहे हैं, किन्तु बराबर ग्रपने त्याग, कुर्बानी ग्रौर तपस्या की बदौलत समाज की रीढ़ बने रहे हैं। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री महोदय को मध्यम श्रेणी की तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिये था।

जहां तक नेशनल इनकम को बढ़ाने का सवाल है, इस पर हर देशभक्त को नाज़ होगा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि जहां वित्त मंत्री ने ग्रपने बजट में नैशनल ग्राय की वृद्धि का तज़किरा किया है, वहीं पर ग्रगर वह पर-कैपिटा इनकम को बढ़ाने की भी बात करते ग्रौर साथ साथ ईक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन ग्राफ वैल्थ की तरफ भी कदम बढ़ाये होते, तो मुल्क को संतोष होता। ग्राज हमारे देश की पूरी ग्राय का तीस प्रतिशत देश के चार प्रतिशत लोगों के बीच में महदूद रह जाता है। ग्रौर सब से नीचे ग्रौर सब से ऊपर के बीच ३० गुणा का ग्रन्तर है। काश इस खाई को पाटने की ग्रोर भी मुरारजी भाई का ध्यान जाता।

वित्त मंत्री महोदय ने नेशनल सेविंग्ज़ स्कीम का विस्तार कराया और इस के माध्यम से नेशनल आय बढ़ी है। लेकिन मेरी इच्छा है कि अगर इस के साथ ही मजदूरों और ग़ैर-मजदूरों के बीच में प्राविडेंट फ़ंड स्कीम को विस्तृत किया जाता और उस के साथ सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें भी गुंथी होतीं, तो ग़रीबों का कल्याण हो सकता था।

कल इस सदन में उप-वित्त मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट के दरमियान एक शब्द कहा था, जोकि अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है। श्री भगत ने बताया कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य योजना के टारगेट्स को पूरा करना है। योजनायें तो इसीलिये बनती हैं कि उन के टारगेट्स को पूरा किया जाये और तभी देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। लेकिन मैं उन से पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ़ तृतीय पंच-वर्षीय योजना के टारगेट्स को पूरा करने का लक्ष्य उन का है, या पहली और दूसरी योजनाओं के जो टारगेट्स पूरे नहीं हो सके हैं, उन्हें भी वह पूरा करेंगे। यदि इस तरह से चार बरस में टारगेट्स परे करने हैं, तो पन्द्रह बरस के टारगेट्स उन्हें इन तीन चार बरसो में पूरे करने होंगे। मैं चाहती हूं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हर एक विभाग के लिए बने, जो इस बात की देख-रेख किया करे कि जो हमारे टारगेट्स हैं, वे सचमुच इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं।

मैं सभी विभागों के सम्बन्ध में तो नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप इतना समय नहीं दे सकेंगे और मैं इस की आवश्यकता भी नहीं समझती, क्योंकि बहुत से सदस्यों ने इस बारे में कहा है, लेकिन मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में कहना चाहती हूं कि देश की अपार धन-राशि उस में खर्च हो रही है, किन्तु उसके टारगेट्स निचली सीढ़ियों तक जाते-जाते विकृत हो जाते हैं——वे संचिकाओं और फ़ाइलों तक ही महदूद रह जाते हैं और क्षेत्र में उन का समुचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता है।

मैं श्रम नीति के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि तीन चार साल पहले वर्कर्ज़ एजूकेशन की स्कीम बनी और देश के चार स्थानों में वर्कर्ज़ एजूकेशन के लिये शिक्षण-केन्द्र खोले गये। लेकिन आप को जान कर ताज्जुब होगा और सदन के लिये यह एक हास्यास्पद बात होगी कि धनबाद में जो वर्कर्ज एजूकेशन केन्द्र खुला, उस के चार साल हो गये, लेकिन आज तक मुश्किल से दो तीन दर्जन मजदूर भी शिक्षितनहीं हो सके हैं। इस लिये टारगेट्स के इम्प्लीमेंटेशन पर सब से अधिक ध्यान देना जरूरी है।

प्राइस लाइन को होल्ड करने की बात वित्त मंत्री ने कही है। पिछले अगस्त महीने से प्राइस लाइन को होल्ड करने की वजह से देश में सन्तोष सा हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस के साथ जनता की क्रय-शक्ति का भी विकास होना चाहिये, क्योंकि जिस हिसाब से देश में प्राइसिज़ में उथल-पुथल हुई है, चीज़ों के दाम आस्मान को छूने लगे हैं, वैसी स्थिति में आज मजदूरों के वेतन और डीयरनेस अलाउन्स में जो वृद्धि हुई हैं, वह नकारात्मक साबित हो रही है और उन के रीयल वेजिज़ उस अनुपात से नहीं बढ पाये हैं। इस की तरफ भी वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

जहां तक यातायात की सुविधाओं का सम्बन्ध है, फरनेस आयल के आयात का प्रबन्ध किया गया है और रेल के भाड़े में भी कुछ और सुविधायें प्रदान की गई हैं। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूं कि यातायात की सुविधाओं के साथ साथ वह कोस्टल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन की ओर भी ध्यान दें। हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के पहले गंगा में इनलैण्ड नेवि-गेशन के माध्यम से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा बहुत लाभान्वित होता था। छोटे

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

छोटे उद्योगों को भी फलने फूलने का मौका मिलता था और छोटे छोटे वणिक भी उस से लाभान्वित होते थे। आज उन्हें फिर से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं मुरारजी भाई को इसलिये भी धन्यवाद देती हूं कि वे अप्र।[टैक्सेज के माध्यम से राज्यों के लिये रेवेन्यू का एक अच्छा हिस्सा प्राप्त करा सकेंगे। मैं कोई प्रान्तवादिनी नहीं। यह रकम प्लानिंग कमिशन के जिम्मे रहेगा और वह निर्णय करेगा कि हर राज्यों में इस का किस तरह से बंटवारा हो। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहती हूं कि बिहार भारतवर्ष की रूर रहा है। अपने तमाम खनिज पदार्थों के बावजूद भी वह आज भी पिछड़ा है और गरीब है। इसलिये सरकार का ध्यान बिहार की तरफ कुछ अधिक जाना ही चाहिये।

एक शब्द कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूं। इस सदन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सैक्टर के ऊपर काफी नुक्ताचीनी हुई है। मैं जब डैट सर्विसेस की तरफ देखती हूं तो ध्यान बरबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सैक्टर की तरफ चला जाता है। दोनों देश की अपार धनराशि इन क्षेत्रों में लगी हुई है। फिर भी यह इकोनोमी और एफीसिएन्सी से कोसों दूर है। श्री वी० के० आर० वी० राव ने इकोनोमिक सर्वे की रिपोर्ट में, एपलबाई कमेटी रिपोर्ट में, गोरवाला कमेटी की रिपोर्ट में, उन तमाम कमेटियों की रिपोर्टों में यही कहा गया है कि दोनों क्षेत्रों में इनएफिशियेंसी आ गई है और प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गया है। हमारा नारा पब्लिक सैक्टर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेंसी और इकोनोमी का होना चाहिये। इन क्षेत्रों को बिजिनेस लाइंज पर एफिशियेंसी के साथ चलना चाहिये। पब्लिक सैक्टर में नो प्राफिट नो लास का सिद्धान्त सर्वथा अनुचित है। हमारी पब्लिक सैक्टर में डिविलेपिंग इकानामी के लिये यह आवश्यक है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग सरप्लस प्राप्त करें और उसे डेवेलपमेन्ट फाइनेंस जोड़ा जाये। कम से कम इनपुट में अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करना पब्लिक सैक्टर का उद्देश्य होना चाहिये। इसी में देश का कल्याण है और हमारे लक्ष्य को सार्थकता मिल सकेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में काफी चर्चा सदन के बाहर और सदन के अन्दर भी हो रही है। माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां रखे हैं। मैं ने भी इस का कुछ अध्ययन किया है। जहां तक मैं समझा हूं इस में समाजवाद की कुछ झलक तो नजर नहीं आती है। हो सकता है कि मेरी समझ में कुछ कमज़ोरी हो या नातजुर्बाकारी की वजह से यह बात हो।

बहरहाल जब इस देश में टैक्सिस लगाये जाते हैं तो कहा यह जाता है कि बड़े आदमियों पर कितने टैक्स लगाये जा सकते हैं। उन पर आगे ही टैक्सों का बहुत भार है। इस सदन में काफी बार वित्त मंत्री महोदय तथा उपवित्त मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया है कि अप्रत्यक्ष कराधान अब इस से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यह कहा जाता है कि ८० परसेंट, ८५ परसेंट या ८७ परसेंट टैक्स लेने के बाद आज जो टोटल नम्बर आफ एसेसीज हैं इतना कम है कि अगर और टैक्स किया जाय तो शायद टैक्स देने की सीमा का अतिक्रमण हो जाये और वे टैक्स दे न सकें।

ज्यादातर यह कहा गया है और चुनाव के पहले भी हमारी रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने जब भाषण दिये तो उनके दौरान में भी एक बात लोगों से कही कि अगर तुम ज्यादा स्कूल चाहते हो, पढ़ाई लिखाई चाहते हो और चाहते कि तुम्हारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें लिखें और साथ ही साथ चाहते हो कि देश उन्नति करे, तो तुम को टैक्स देने ही पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी जब लोगों को यह

महसूस होता है कि टैक्स देने का फायदा उन्हें नहीं पहुंचा है तो उन्हें मायूसी का अनुभव होने लगता है । पहली योजना मैं समझता हूं कि किसानों के लिए बनाई गई थी। उस में आबपाशी के साधन मुहैया किए गए और दूसरी चीज़ें की गई। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत कर के अपने खेतों से सोना उगाया क्या वाकई में उनको फायदा हुआ ? इसका प्रमाण कि उनको फायदा नहीं हुआ मैं देना नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी खुद इसके बारे में सोच लें।

दूसरी योजना जब आई तो मुझे याद है कि १२ या १६ फरवरी १९५६ को अखबारों में सुर्खियां निकाली गई कि ८ मिलियन यानी ८० लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उसके बाद क्या हुआ ? इसके ठीक तीन चार महीने बाद ३६,००० आदमी पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर, दोनों से निकाल दिये गये। लोगों को ताज्जुब हुआ कि ८० लाख को कहां नौकरियां मिलने जा रही हैं जब कि ३६,००० आदमियों को निकाल बाहर कर दिया गया है । एक मजदूर के सामने सवाल उठा कि क्या दूसरी योजना में भी उस से कुर्बानी मांगी जाएगी ऐसी हालत में ? हम से कहा यह जा रहा है कि तुम त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ, देश के निर्माण के लिये त्याग या बलिदान तुम को करना ही होगा । लेकिन क्या इसका भी कुछ लाभ उसको हुआ । तीसरी योजना की बात हो रही है । मैं योजना का समर्थक हूं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय उद्योग आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि देश की तरक्की हो। मैं चाहता हूं कि संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोणों से इन योजनाओं को न देखा जाए। लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना पड़ता है कि आखिर यह प्लान, यह योजना किस के लिए है। क्या हिन्दुस्तान का किसान, हिन्दुस्तान का मजदूर इसलिए पैदा हुआ है कि वह प्लान के लिए कुर्बानी देता चला जाए और प्लान से उसको कोई फल न मिले । यह मुख्य सवाल आज हमारे देश के सामने है, देश की जनता के सामने है । जब भी कोई सवाल आता है तो यह कह कर कि अभी और त्याग और बलिदान तुम को करना होगा, नए टैक्स लगा दिए जाते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ ४५ करोड़ के टैक्स लगे हैं; अभी और भी टैक्स लगेंगे । यप सभी बाल बच्चों के नाम पर किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे अच्छी तरह से रहें तो तुम्हें इन टैक्सों का बोझ सहन करना ही होगा ।

लेकिन एक सवाल उठ खड़ा होता है । चुनावों के दौरान में मैं ने देखा है कि माननीय मंत्री लोग, मेरा इशारा वित्त मंत्री महोदय की तरफ नहीं है क्योंकि मैं ने उन के भाषणों को नहीं सुना है, अपने भाषणों में कई कई बातें कह जाते हैं। एक भाषण में उन्होंने अचानक किसी फटे पुराने कपड़े पहने हुए लड़के की तरफ देख कर और उंगली दिखा कर कहा कि प्रजातंत्रीय युग में आने वाले हिन्दुस्तान का होने वाला प्रधान मंत्री यहां बैठा हुआ है । बड़ी खुशी हुई उस बच्चे को यह बात सुन कर और साथ सी साथ उस के पिता को । उस के पिता उस बच्चे को लेकर घर गये और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि सुना है कि मुख्य मंत्री जी क्या कह गए हैं ? वह कह गए हैं कि तुम्हारा यह बच्चा आने वाले हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री होगा। उसको भी बड़ी खुशी हुई । लेकिन जब वह बच्चा पांचवीं क्लास से चढ़ कर छठी क्लास में गया तो होने वाले हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री का नाम ही स्कूल से कट गया और वह भी इस लिए कि किताबों की इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट दे दी गई थी कि उन के दाम उसके पिता नहीं दे सकते थे। उसके बाद आने वाले हिन्दुस्तान के

[श्री स० मो० बनर्जी]

प्रधान मंत्री की शक्ल दिखाई पड़ी, एक होटल में जूठे बरतन मांजते हुए। समझ में नहीं आता है कि हम भी जब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग वजाहत मांगते हैं और कई तरह के सवाल ला खड़े कर देते हैं जिन के जवाब देना मुश्किल हो जाता है । जब टैक्स कौलैकशंज़ का सवाल आता है और . . .

श्री दी० चं० शर्मा : परन्तु इन पलेट धोने वालों वालों में से बहुत से बड़े आदमी बन गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : छोट छोटे दुकानदारों से इंस्पैक्टर लोग टैक्स वसूल करने जाते हैं तो मैं ने देखा कि सेल्ज़ टैक्स और इनकम टैक्स इंस्पैक्टर लाल पीली आंखें कर के उसे डराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दुकान को मैं तबाह कर दूंगा अगर टैक्स नहीं अदा किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने उसी इंस्पैक्टर को और उस के गुस्से को और उसकी लाल पीली आंखों को भी देखा है । जब वह किसी बड़े सरमायदार के पास जाता है तो उसका गुस्सा सलाम में बदल जाता है । समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : माननीय सदस्य ने ऐसे आदमी के बारे में सरकार को लिखा क्यों नहीं । यदि वह लिखते तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं लिखता तो ।

यहां पर टैक्सों की वसूली का भी सवाल आता है । एक सवाल इस सदन में मैंने किया था ९ मई १९६२ को। मैं अपने आप को पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने का लीडर नहीं समझता हूं और न ही मेरी ऐसी सूरत है और न हीं सीरत । बहरहाल कानपुर एक मामूली जगह है जहां से मैं चुनकर आया हूं और उसका मैं नेतृत्व करता हूं । मैं ने सवाल पूछा था कि क्या आय-कर सम्पदा-कर और दान-कर की कानपुर से बकाया राशि वसूल की जा चुकी है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका जबाव दिया था— वसूल हो रहे हैं। उनके बताये आंकड़ों के अनुसार कानपुर शहर में अगर आप का १ करोड़ ९३ लाख यानी लगभग २ करोड़ रुपया बाकी है । ४ करोड़ ९८ लाख में से तो पूरे हिन्दुस्तान भर के पैमाने पर तकरीबन १२३ करोड़ रुपये ही हो सकते हैं जो बाकी हों । इस से कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकते हैं। मुझे इसका ठीक मालूम नहीं है। बहरहाल इफैक्टिव एरियर्ज़ और नान-इफैक्टिव एरियर्ज़ का सवाल आयेगा । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि टैक्सेज के कलेक्शन के बारे में कि अगर उनका कलेक्शन नहीं होगा तो आप गरीब आदमी को टैक्स करने की कोशिश करेंगे, और वह गरीब आदमी फिर एक सवाल पूछेगा, वित्त मंत्री जी से, कि क्या हम सिर्फ टैक्स देने के लिये पैदा हुए हैं? टैक्स देने के बाद जो देश का निर्माण होगा उस का फल भोगने के लिये हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, दूसरे लोग पैदा हुए हैं?

बेकारी की बात इस सदन में कही गई। जब बेकारी की बात कही जाती है तो कोशिश यह होती है कि बेकारी को दूर करने के लिये जो हमारे बड़े बड़े आदमी बेकार हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाती है और उसको काम दे दिया जाता है बेकारी दूर करने का। एक सवाल इस सदन में किया गया

†मूल अंग्रेजी में

सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में। सवाल यह था कि १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने ग्रेजुएट और गैर-ग्रेजुएयों को पंजीयित किया गया और उनमें से कितनों को रोजगार जुटाया गया ?

इसका जवाब माननीय श्री जयसुख लाल हाथी ने दिया था कि १९६१-६२ में ग्रेजुएटों की संख्या २०,६९४ थी। जिनमें से २,६४६ को रोजगार मिला और गैर-ग्रेजुएटों की संख्या १,८०,३५० थी जिनमें से १८,००० को काम दिलाया गया। यह मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात कह रहा हूं, और वह भी रजिस्टर्ड बेकारों की बात कह रहा हूं। अनरजिस्टर्ड की बात तो मैं कह ही क्या सकता हूं। लेकिन मेरे शहर में जितने आदमी रिक्शा चलाते हैं वह कोई सेहत ठीक करने के लिये नहीं चलाते हैं, और वह अनरजिस्टर्ड बेकार हैं जिन की बेकारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस लिये प्लैनिंग के सिलसिले में मैं कहुंगा कि इस से हमारे देश में बेकारी कम नहीं हुई है। योजनायें हमारे देश में बनी हैं, मैं उनका समर्थक हूं और समझता हूं कि उससे देश की तरक्की हुई है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं कि तरक्की नहीं हुई है। लेकिन तरक्की के साथ लोगों की क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। चुनावों के दौरान कहा गया कि आपको मालूम है कि आज लोगों की क्रय शक्ति कितनी बढ़ी है ? पहले जिसको १ रु० मिलता था उसको अब १ रु० ५ आ० मिलने लगा है। यह बात इससे भी जाहिर होती है कि पहले देश में १० हजार रेडियो बनते थे और उनकी खपत थी लेकिन अब २० हजार रेडियो बनते हैं और बिकते हैं। कितना जबर्दस्त मजाक है कि कहा गया कि कानपुर शहर में, जहां पर जाड़े से सिकुड़ कर ६५ आदमी मर गये, वह उनका कुसूर था। उनकी जेब में रुपया था, मंत्री महोदय के कहने के अनुसार, लेकिन उन्होंने गलती यह की थी कि जब कि उनको कम्मल खरीदना चाहिये था, उन्होंने उसकी जगह पर रेडियो खरीद लिया था। मैं दंग रह जाता हूं कभी कभी जब इन्सान की जिन्दगी के साथ जबर्दस्त मजाक किया जाता है।

दूसरा सवाल है कि साधनों को किस तरह से लाया जाये। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में वित्त मंत्री ने बैंक मैगनेट्स को विश्वास दिलाया था कि कोई ऐसी बात नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। कंसेंट्रेशन आफ वेल्थ जो है, हमारी नैशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा जो कुछ लोगों के हाथों में बंट गया है, उसको जानने की कोशिश आप कैसे करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर जो यह टैक्स इवेजन कर के होर्ड्स में जो रुपया रख लिया गया है, जो चांदी सोना लोगों के पास पड़ा है उसको कैसे जाना जायेगा और कैसे वह देश के निर्माण के काम मे लाया जायेगा, अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता। हमारे जनरल इंश्योरेन्स का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, और यह जरूरी है। इसके बाद कुछ हमारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मैं समझता हूं हमारी कोल इंडस्ट्री की माइन्स हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। शुगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। हमें शुगर मैगनेट्स को बता देना चाहिये कि तुमने देश में बहुत कमाया है, अब देश के हित में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। मेरे ख्याल में अगर कोई राष्ट्रीयता का जर्रा उन से छू गया होगा तो वे उस में आपत्ति नहीं करेंगे।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी चीज के बारे में कहना चाहता हूं। प्राविडेंट फंड के बारे में बार बार इस सदन में कहा जाता रहा है कि वह अगर ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ कर ८ १/३ प्रतिशत हो जाय तो काफी पैसा मिलेगा, और यहां पर जितने बड़े बड़े सरमायेदार हैं वे दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वे दे नहीं सकते। लेकिन हिम्मत कुछ कम है हमारी सरकार में और वह कह नहीं सकती कि तुम को इसे बढ़ाना चाहिये। तुम्हारे अन्दर देने की शक्ति है और तुम को देना पड़ेगा। ऐसा किया जाय तो काफी रुपया इस सिलसिले में मिल जायेगा।

इसके बाद सवाल आता है लगाये जाने वाले टैक्सेज का। मेरे मोअज्जिज दोस्त भगत साहब ने दामों के बारे में कल बतलाया और कहा कि हमने माचिस को भी देखा, सिगरेट को भी देखा, चाय को भी देखा कोचीन के सिवा कहीं उसके दाम नहीं बढ़े हैं। माचिस के दाम आज दिल्ली शहर में ७ नये पैसे हैं। आज अगर वे कष्ट कर के सेन्ट्रल हाल से बाहर जाने का प्रयत्न करें हालांकि वे स्मोक नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग करते हैं बहरहाल अगर वे चले जायें तो उनको ७ नये पैसे में ही माचिस मिलेगी। उनको देख कर भले ही वह ६ नये पैसे में मिल जाये, मुझे को देख कर तो ७ नये पैसे ही में मिलेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माचिस के बारे में कहा जा चुका है। आपका समय समाप्त हो चुका है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। तो मैं कह रहा था कि जो चीजें बाहर जा कर मिलती हैं वे सब मंहगी हो गई हैं। १५ नये पैसे का चाये का कप मिलता है। इस लिये आप इन चीजों को देखिये कि वे किस तरह से बढ़ी हैं।

अन्त में एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक रिप्रेजेन्टेशन आल इंडिया मैनुफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है जिसमे उन्होंने कहा है कि मीडियम और कोर्स क्लाथ पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का जो असर पड़ा है अगर उसकी जांच कर के देखा जाये तो बड़ी मेहरवानी होगी।

एक छोटी सी बात है फुजूलखर्ची के बारे में। रोरकेला से एक दफ्तर जो कि पर्चेज डिपार्टमेंट है रोरकेला स्टील प्लान्ट का, उसे पहले उन्होंने सन् १९५७ में शिफ्ट किया रोरकेला मे, बड़ी मुश्किलों के बाद जब यह महसूस हुआ कि उसको रोरकेला में रखने से नुक्सान होगा तो उसको कलकत्ते में ले आया गया, और अब फिर कोशिश हो रही है कि उसे कलकत्ते से रोरकेला लाया जाये क्योंकि कुछ आदमी चाहते हैं, हो सकता है कि बीच में कुछ पोलिटिकल रीजन हो जिस की वजह से ऐसी बात हो रही है। इन तमाम चीजों पर हमारे मंत्री महोदय ध्यान दें। टैक्स लेने के लिये जो उन्होंने अप्रत्यक्ष कर लगाये हैं वह बिल्कुल गलत होगा। इस लिये गलत होगा कि जब इस देश का निर्माण करना है तो सरमायेदारों से सरमाया और गरीबों से मेहनत लें तभी काम बनेगा।

मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री राज्य सभा में जो जवाब दे चुके हैं उसके अलावा यहां पर कोई नई बात कहने को नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा हिन्दुस्तान की हालत को देखें। उसे देखने के बाद उनकी समझ मे आ जायेगा कि यहां के लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ती नहीं घटती जा रही है इस लिये वे मेहरवानी कर के इस टैक्सेशन को कम करें।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवल्ला): अन्य सदस्यों के साथ, मैं भी इस कुशलतापूर्ण आय-व्ययक के लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। आय व्ययक का काम देश की आवश्यकताओं और संसाधनों में संतुलन पैदा करना है, और हमारे जैसे देश में यह बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि हम कम से कम अवधि में आधुनिक औद्योगीकरण के स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

कम से कम समय लगाने के अतिरिक्त हमारा एक और भी उद्देश्य है कि समाजवादी की बुनियाद डाली जाये। इतना ही नहीं, हमें लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद की नींव डालनी है। वित्त मंत्री ने इन सभी को बड़ी कुशलता से निभाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कम्युनिस्ट दल के सदस्य ने विदेशी पूंजी के विनियोजन और अप्रत्यक्ष करों पर आपत्ति की है और गैर-सरकारी क्षेत्र का गला घोंट देने का सुझाव रखा है। लेकिन ऐसा कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया कि उसके स्थान पर फिर किया क्या जाये।

कुछ उद्योगपतियों ने भी कहा है कि यह देश के उद्योगों को चौपट कर देगा। यह तो उद्योग-पति हर बार कहते आये हैं, पर उद्योग चौपट आज तक नहीं हुआ।

सभा के सभी सदस्य सहमत हैं कि देश में समाजवाद की बुनियाद डाली जाये। समाज-वाद बिना औद्योगीकरण के नहीं लाया जा सकता, और औद्योगीकरण बिना पूंजी और मशीनों के नहीं किया जा सकता। देश की दशा को देखते हुए हमें विदेशी पूंजी विनियोजन की अनुमति देनी ही पड़ेगी।

विदेशी पूंजी का विनियोजन हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतिकूल नहीं है। हमारा समाजवाद कठमुल्लेपन का समाजवाद नहीं है।

यह कोई नहीं कहता कि यह आय-व्ययक पूर्णरूप से समाजवादी आय-व्ययक है। समाजवाद के निर्माण में आखिर समय तो लगेगा! इसी लिये इस आय-व्ययक में कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो देश को समाजवाद की दिशा में ले जायेंगे।

अप्रत्यक्ष करों की बड़ी कटु आलोचना की गई है। आज संसार का कोई भी देश केवल प्रत्यक्ष करों पर निर्भर नहीं रह सकता। कर दाताओं की संख्या और उनकी क्षमता सीमित है, पर देश के विकास की आवश्यकतायें कहीं व्यापक हैं, इसलिये अप्रत्यक्ष करों का सहारा लेना ही पड़ता है। कम्युनिस्ट देशों में भी अप्रत्यक्ष कर लगाये जाते हैं।

व्यय-कर के हटाये जाने का भी उल्लेख किया गया है। मेरा विचार है कि व्यय-कर अभी भी देश के लिये उपयोगी है।

मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि राष्ट्रीय आय के बंटवारे और आम जनता के हिस्से में पड़ने वाले उसके भाग के सम्बन्ध में जांच की जाये। प्रादेशिक विकास की असमानता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। केरल की जनता के दिमाग में यह बात जमती जा रही है कि केन्द्र उसकी जानबूझ कर उपेक्षा कर रहा है। यह भावना देश के एकीकरण के लिये घातक है।

†**श्री मोहसिन (धारवार दक्षिण)**: मैं इन आय-व्ययक प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। इस आय-व्ययक पर परस्पर विरोधी प्रतिक्रियायें हुई हैं।

जो भी हो, मैं नहीं मान सकता कि यह एक समाजवादी आय-व्ययक है: यह तो सही है कि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है। लेकिन अब बड़े-बड़े भू-स्वामी और जागीरदार उद्योगों में अपना रुपया लग रहे हैं। इसलिये उचित तो यही था कि उद्योगों से प्राप्त आय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाना चाहिये थी। परन्तु इन प्रस्तावों में उसका कोई उल्लेख तक नहीं है।

भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियां देना बताता है कि हम अभी भी गुलाम बने हुए हैं। लोकतांत्रिक समाज में निजी थैलियों के लिये कोई स्थान नहीं। वे बन्द कर दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यय कर हटाना बड़ा अच्छा है। इसलिये कि धनी लोग जो व्यय करते हैं उससे, समाज को ही तो लाभ होता है। रहता तो वह देश में ही है।

आज कल साधारण जनता आय-व्ययक में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। केवल उद्योग-पति ही आय-व्ययक के सम्बध में चर्चायें किया करते हैं।

दावा किया जाता है कि देश के हर क्षेत्र में विकास परियोजनायें बढ़ रही हैं। लेकिन साथ ही गंदी बस्तियां, निरक्षरता, और बेरोजगारी भी तो बढ़ती जा रही है। जनता के रहन-सहन का दर्जा केवल कागज़ों पर ही ऊंचा हुआ है। गांवों में कोई भी अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। लोग आज से सौ वर्ष पहले कहीं अधिक सुखी थे। देश में इतने सारे विनियोजनों और परि-योजनाओं के बाद भी सुख में वृद्धि नहीं हुई है। आज साधारण जनता की दशा बड़ी दयनीय है।

और दक्षिण भारत की जनता के दिमाग़ में यह बात घर करती जा रही है कि उसकी उपेक्षा हो रही है। हम इस भावना को अनदेखे नहीं कर सकते। दक्षिण भारत के औद्योगी-करण के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। सभी राज्यों में समान बंटवारा होना चाहिये।

देश की एकता की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, पर देश की स्वतंत्रता के बाद मैसूर राज्य में एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं डाली गई है।

देश भर में सड़कों के निर्माण के लिये २९ करोड़ रुपये रखे गये हैं, लेकिन उनमें से केवल २९.२ लाख ही मैसूर राज्य को दिये गये हैं। सारे देश में कुल मिला कर १३,२५८ मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं, लेकिन मैसूर राज्य में केवल ५३३ मील ही हैं।

अर्से से हुबली में हवाई अड्डा बनाने की मांग की जा रही है पर सर्वेक्षण के बाद भी योजना को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। केन्द्र को मैसूर के साथ न्याय करना चाहिये अन्यथा देश की एकता नष्ट हो जायेगी। देश के किसी भी भाग की उपेक्षा नहीं होनी चहिये।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। उसमें मैसूर का भी एक सदस्य रखना चाहिये।

†**डा० ल० म० सिंघवी** (जोधपुर) : श्री विद्यालंकार ने विरोध के लिये विरोध करने की प्रवृत्ति की बड़ी कटु आलोचना की है। मेरा ख्याल है कि बिरोधी दलों की आलोचनाओं से सरकार को अपना सुधार करने में सहायता मिलती है।

हमने बड़ी महती, महत्वकांक्षापूर्ण योजना हाथ में ली है। वह तभी पूरी हो सकती है जब हम किसी सिद्धान्त पर कठमुल्लों की तरह अमल न करके, साहस और आत्मालोचना के बल पर, विनम्रता से अपना काम आगे बढ़ायें।

इस आय-व्ययक ने सामान्य जनता की बिल्कुल उपेक्षा की है। मध्यवर्गीय जनता की दु:ख-तकलीफों का इसमें कोई ध्यान ही नहीं रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

और जब तक जनता में उत्साह और सहयोग की भावना नहीं जगाई जायेगी तब तक कोई भी योजना सफल नहीं बनाई जा सकती। देश के नेताओं ने इसी की ओर ध्यान नहीं दिया है।

माननीय वित्त मंत्री ने आंकड़ों को पेश करने में हाथ की सफाई दिखाई है। लेकिन उससे जनता के आर्थिक जीवन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी और दुख:तकलीफ तो ज्यों की त्यों बनी रहती है।

मैं सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध नहीं हूं। पर सरकारी उपक्रम ऐसे तो हों कि देश को उनका घाटा न भरना पड़े।

सरकार ने निर्यात संवर्धन की बड़ी बड़ी बातें की हैं, पर वास्तव में लाभ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता।

श्री नाथपाई ने बताया है कि खेतिहर मजदूर की आय ४४७ रुपये प्रति वर्ष से घटकर ४३७ रुपये ही रह गई है। तब फिर प्रगति का क्या अर्थ हुआ?

सरकारी उपक्रमों पर देश का इतना रुपया खर्च किया गया है, लेकिन उनकी दशा शोचनीय हैं।

१९६१–६२ से १९६२–६३ तक सरकारी उपक्रमों पर ८९६.४० करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। लेकिन उनसे मुनाफा केवल ०.३ प्रतिशत हुआ है। जिन उपक्रमों में उत्पादन शुरू हो गया है, उन से भी कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा है। १६ सरकारी समवायों, जिनमें ९१.४ प्रतिशत सरकारी समवाय आ जाते हैं, के सर्वेक्षण से पता चला है कि १९६०–६१ में सरकारी समवायों को केवल ६ प्रतिशत मुनाफा हुआ, जब कि गैर-सरकारी समवायों को ८.२ प्रतिशत मुनाफा हुआ है। यह भी तब जब सरकारी उपक्रमों को अपने ऋणों के लिये गैर-सरकारी उपक्रमों के बराबर ब्याज नहीं देना पड़ता।

सिंदरी उर्वरक कारखाने में ९ 'जेनेरेटर' इसलिये बेकार पड़े हैं कि सही किस्म के कोयले का उपयोग नहीं किया गया था। इसकी जांच की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि देश में तैयार हुए उर्वरकों को प्रतिटन ४२० रुपये दिया जाता है, जब कि आयात किये जाने वाले उर्वरक भी २०० रुपये प्रति टन पर मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि सरकारी उपक्रम कितने कार्य क्षम हैं।

रूरकेला का भी यही हाल है। वित मंत्री का अनुमान है कि इस योजना काल में सरकारी उपक्रमों से ३०० करोड़ रुपये मिल सकेंगे? लगता है कि अनुमान पूरा नहीं होगा, क्योंकि १९६०–६१ में केवल २ और १९६१–६२ में केवल १.६५ करोड़ रुपये ही अभी तक मिले हैं। जरूरत इस बात की है कि सभी सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन की अच्छी तरह छानबीन की जाये।

श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय : आजादी के बाद से कांग्रेस ने जब से सरकार बनानी शुरू की है, तब से वह हर बरस बजट पेश करती जा रही है। हमेशा ही उस बजट का एक खास तरह का नजरिया रहा है। वह यह रहा है कि हिन्दुस्तन में सोशलिस्टिक पैटर्न पर सोसाइटी कायम की जाए। इस नज़रिये के तहत को जो बजट साल-ब-साल

पेश किये गये हैं, उनके नताइज आहिस्ता आहिस्ता हिन्दुस्तान के सामने आ रहे हैं। आज यह बात फख्र के साथ कही जा सकती हैं कि चाहे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बजट पर होता रहा है, सोशलिस्टिक बुनियादों पर हमारा इक्तसादी ढांचा जो कायम होना है उसकी बुनियादें रखी जा चुकी हैं। सोशलिस्टिक पैटर्न पर इकोनोमी कायम करने के लिये सब से जरूरी यह है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं वे पब्लिक सैक्टर में हों। इस बात की यकीनन हमें खुशी है और इस बात के लिये सरकार मुबारिकबाद की मुस्तहिक है कि स्टील, फर्टिलाइजर्स और दूसरी बेसिक इंडस्ट्रीज़ तमाम की तमाम १९४७ के बाद से जो भी कायम की गई हैं, उनमें से ज्यादा तर पब्लिक सैक्टर में कायम की गई हैं : इसी वजह से आज हमारी इकोनोमी इस स्टेज पर पहुंची है कि आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक सैक्टर तरक्की कर रहा है और हम सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राडक्शन में नुमाया इज़ाफ़ा हुआ है और इसी वजह से आहिस्ता आहिता मुलक की दौलत बढ़ रही है। आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम उस मोड़ से मुड़ चुके हैं जिस के आगे यकीनी तौर पर हमारे लिये बेहतर दिन आएंगे।

एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। यह ठीक है कि पैदावार बढ़ी है। यह भी ठीक है कि मुल्क की दौलत बढ़ी है। इसके साथ ही साथ यह भी एक हकीकत हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ी है। लेकिन जब उसे हम डिवाइड करते हैं लोअर क्लासिस में और अपर-क्लासिस में तो यह मानना पड़ेगा कि उसका बहुत ज्यादा हिस्सा अपर क्लाँसिस को गया है लोअर क्लासिस को नहीं गया है। हमें कोई न को ढंग या तरीका सोचना होगा कि आगे के लिये ऐसी बात दोहराई न जा सके। आइंदा के लिये ज्यों ज्यों देश की बेहतरी हो, ज्यों, ज्यों देश कीं खुशहाली बढ़े, उसके मुफायद लोअर क्लासिस को मिले, वर्किंग क्लासिस को मिले।

यह ठीक है कि हमारे देश के रिसोर्सिस बहुत महदूद थे। इसलिये यह जरूरी था कि बजट में टैक्सेशन प्रोपोजल्ज रखी जातीं। अब तक जो कुछ होना था हो गया। लेकिन आगे के लिये मैं कहना चाहता हूं कि लग्ज़री गुडज़ पर ज्यादा टैक्स लगें, कंज्यूमर गुड्स पर कम लगें ताकि जो लोयर-क्लासिस के लोग हैं उन पर कम बोझ पड़े। अपर-क्लासिस के लोग टैक्स एफोर्ड कर सकते हैं, उनपर इसका ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और अगर उन पर थोड़ा सा ज्यादा बोझ पड़ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन लोअर क्लासिस को हमें हर कीमत पर बचाना होगा, हर कीमत पर उनकी मदद के लिए हमें आना होगा क्योंकि लोअर क्लासिस के लोग मजीद बोझ बरदाश्त करने के काबिल नहीं हैं।

जब मैं लोअर क्लासिस का जिक्र करता हूं तो मेरे सामने हिन्दुस्तान के देहातों का नक्शा आ जाता है। लोअर क्लासिस का बहुत बड़ा तबका देहातों में रहता है। यह ठीक है कि वर्किंग क्लासिस के जो लोग पेड एम्पलायीज़ हैं वे भी लोअर क्लासिस में आते हैं। लेकिन उनके मुकाबले में लोअर क्लासिस की बहुत बड़ी तादाद गांवों में रहती है और गांवों के लिए अभी तक हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं और न हम फक्र के साथ सिर बुलन्द कर के कह सकते हैं कि हम बहुत कुछ उनके लिये कर रहे हैं। अगर हम अपनी एग्रीकलचरल इनकोनोमी को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि उसके जरिये ही किसान का भला हो सकता है, उसके जरिये ही गांवों में रहने वाले लोगों का भला हो सकता है, तो उसके लिये सब से जरूरी और बुनियादी बात जो है वह कोआप्रेटिव फार्म्स की है। हमने हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लैंड रिफार्म्स लागू किए ह, सीलिंग्ज़ मुकर्रर किए हैं। लेकिन जब फैगमेंटेशन आफ लैंड होंगे, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होंगे तो उसके बाद पोज़ीशन क्या होगी? यह नहीं हो सकता आज के हिन्दुस्तान के हालात में और कांग्रेस की जो पोज़ीशन है और हिन्दुस्तान के अव्वाम जो चाहते हैं, उस में कि बढ़े बड़े प्राइवेट फार्म्स हिन्दुस्तान में कायम रहें। लेकिन यह तो हो सकता

है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के उसूलों पर ज्वाएंट फार्म्स कायम किये जायें और उसके लिये मुल्क के किसानों को तैयार किया जाय ? मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इस मद में हम बहुत कम कर पाये हैं, बल्कि मुझे यह कहना चाहिये कि इस मामले में हमने जो कुछ किया है वह मायूसी की हद तक नाकाफी है। और अगर हम इस देश की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं उनकी किसी न किसी ढंग से बड़ी-बड़ी यूनिट्स में ग्रुपिंग करनी होगी, और वह सिर्फ कोआपरेटिव फार्मिंग के ढंग से हम कर सकते हैं। वह सिर्फ कोआपरेटिव बेसिस पर हो सकता है। नागपुर सेशन को अब कई साल हो गये हैं, उसके बाद हमने कुछ ग्रान्ट्स इस हाउस के अन्दर कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के लिये पास की हैं, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि अभी तक हिन्दुस्तान की हर तहसील में एक-एक कोआपरेटिव फार्म भी कायम नहीं किया जा सका ? क्या यह हकीकत नहीं है कि कोआपरेटिव फार्मिंग का जो हमारा प्रोग्राम है वह एक हद तक कागजों में ही बन्द पड़ा है ? और जब तक कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ हम खास तवज्जह नहीं देंगे तब तक हम ऐग्रेरियन एकानमी को बेहतर नहीं कर सकेंगे, हम अपनी पैदावार को नहीं बढ़ा सकेंगे ? क्योंकि छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग्स से न तो इंटेन्सिव कल्टिवेशन हो सकता है और न लोगों के पास वह रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनके जरिये वे फर्टीलाइजर वगैरह खरीद सकें। इस लिये मेरी तजवीज है कि जैसे भी हो हमें कोशिश करनी चाहिये और अपनी तवज्जह मरकूज कर देनी चाहिये कि कोआपरेटिव फार्मिंग कामयाब हो जाय और हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा भी न रहे जहां कम से कम नमूने के तौर पर एक-एक ब्लाक में एक-एक कोआपरेटिव फार्म कायम न हो जाय।

दूसरी बात जो देहात की बेहतरी के लिये कही जा सकती है वह यह है कि जो हेवी इंडस्ट्री हैं, बिग इन्डस्ट्रीज हैं उनके लिये तो यह मुमकिन नहीं है कि वह गांवों में कायम हों लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज काटेज इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में और पार्टिकुलरली गांव में या छोटे-छोटे कस्बों में बिखरने में कुछ मुश्किल नहीं आ सकती है। उस में एक ही मुश्किल है जो इस वक्त तक सगे राह रही है। वह मुश्किल यह है कि जो रॉ मैटीरियल्स हैं उनकी यूनिफार्म प्राइस कायम नहीं हो सकी है हिन्दुस्तान में अगर हमें अपनी इंडस्ट्रीज को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखेरना है तो यह जरूरी है कि किसी न किसी किस्म का इक्वलाइजेशन फंड कायम किया जाय जिस के जरिये चाहे कोई इंडस्ट्री पठानकोट में कायम हो, चाहे कोई इंडस्ट्री डलहोजी में कायम हो, चाहे कोई इंडस्ट्री मैसूर के किसी कस्बे में कायम हो, चाहे कोई इंडस्ट्री बंगाल के किसी हिस्से में कायम हो हर जगह रा मैटीरियल्स तकरीबन एक कीमत पर मिल सके। जब तक ऐसा नहीं हो जायेगा, मैं नहीं समझता कि छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हम गांव में बिखेर सकेंगे। इसलिये अगर हम चाहते हैं, और सही तौर पर चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं, कारखानों को तमाम हिन्दुस्तान में बिखेरना, तो मेरी राय में यह बहुत जरूरी है कि हम अपने ऐसे हालात पैदा करें कि छोटी इंडस्ट्री वहां पर कायम हो सके।

इस के बाद जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि मैं एक ऐसे हिस्से से आया हूं जो हर लिहाज से पसमांदा है। मेरी रियासत को जम्मू और काश्मीर कहते हैं। क्या हिन्दुस्तान में जम्मू काश्मीर के अलावा कोई और भी स्टेट ऐसी है जहां पर कोई हेवी इंडस्ट्री न हो, जहां कोई रेल लिंक न हो, जहां कोई रिसर्च के लिये इन्स्टिट्यूट न हो और जहां पर पावर पोटेंशल को एक्स्प्लायट करने के लिये कोई बड़ी प्रोजेक्ट न चलाई गई हो ? जब मैं ने पहली दफा इस हाउस में कदम रखा, और अपने बुजुर्ग साथियों के साथ कसम लेने के लिये आगे आया तो तमाम हाउस ने हमें आवेशन दिया, जिससे मेरे जिस्म में एक अजीब सरसराहट पैदा हुई और मैंने कहा कितनी मोहब्बत और कितना एहतराम, कितने दिली जज्बात, दिली हमदर्दी काश्मीर और जम्मू के लिये इस हाउस के दिल में मौजूद है ? लेकिन मैं देखता हूं कि काश्मीर में रेल लिंक नहीं है। इस के लिये पिछले दस वर्षों से बाकायदा हर सेशन में यहां चिल्लाहट होती रही है, यहां मतालबा किया जाता रहा है, लेकिन आज भी

[श्री गोपालदत्त]

पोजीशन यह है कि यही जवाब मिलता है कि सन् १९६४ तक सिर्फ कठुआ तक रेल जा सकेगी। इस का मतलब यह है कि सिर्फ ४ मील तक रेल जायेगी। अगर १४ वर्षों में चार मील रेल की गई तो मैं पूछता हूं कि जम्मू तक, काला कोट तक और रियासती के उन हिस्सों में जहां मादनियात के बेशुमार जखायर ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं और एक्स्प्लायटेशन का इन्तजार कर रहे हैं, वहां तक रेल ले आने में क्या सदियां नहीं लगेंगी? इस लिये मेरी अर्ज यह है कि जहां तक ताल्लुक है रियासती सरकार का वह अपना फर्ज अदा कर रही है, उसने पिछले दो प्लैन्स के अर्से में एजुकेशन को फ्री कर दिया और वहां डिस्पेन्सरीज का जाल बिछा दिया। वहां पर छोटी मोटी सड़कें बनाईं, लेकिन जहां तक ताल्लुक सेन्टर का है, मुझे यह कहने में कुछ मायूसी होती है, लेकिन कहना पड़ता है कि सेन्टर की तरफ से हमदर्दी तो हुई लेकिन अमली तौर पर काश्मीर के लिये कुछ नहीं हुआ। यहां जब कि बख्शी सरकार जद्दोजहद कर रही है लोगों का मेयार उठाने का, वहां पर बजाय इस के कि हमारे लिये कुछ किया जाता, फाइनेन्स कमिशन ने तकरीबन १ करोड़ रु० सालाना की हमारी ग्रान्ट को खत्म कर दिया।

श्री रघुनाथ सिंह : यह तो वापस होनी चाहिये।

श्री गोपालदत्त : मैं अर्ज कर रहा था कि जो स्टेट की सरकार है वह कोशिश कर रही है लेकिन सेन्टर को भी इस तरफ तवज्जह करनी चाहिये और प्लैनिंग कमिशन से और सेन्टर गवर्नमेंट से यह मतालबा करूंगा मैं भीख नहीं मांगता, **ऐज ए मैटर आफ राइट** मतालबा करता हूं कि वह काश्मीर की तरफ तवज्जह दें। वह देखें कि काश्मीर को भी हक है कि वहां रेलवे लाइन जल्द से जल्द हो जो कि माइन्स तक जानी चाहिये, उनको हक है कि वहां के नैशनल हाई वे ठीक हों। वहां पर जो नैशनल हाई वे हैं वह मामूली सी बारिश हो जाय तो कई कई दिन बन्द रहता है। वहां रेल नहीं है। हेवी इंडस्ट्रीज कोई नहीं है, तब वहां की खुशहाली का क्या इन्तजाम किया जा सकता है? इस लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और उसके साथ-साथ प्लेनिंग कमिशन को काश्मीर के मसायल की तरफ खास तवज्जह देनी चाहिये।

श्री दि० सि० चौधरी (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे योग्य वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस का मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की जो समाजवाद लाने की नीति है उसकी ओर यह एक छोटा सा कदम है, और हमारी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसकी सफलता का एक अंग है। मैं ज्यादा विस्तार में न जा कर यह बतलाना चाहता हूं कि बजट में क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये। अगर उनके आंकड़े मैं आप को सुनाऊं तो उसके लिये बहुत समय चाहिये जब कि वह बहुत थोड़ा है। लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

मुझे इस बारे में कहने में समय नहीं लेना चाहिये कि हमारा जो बजट है उसकी बहुत सी विशेषतायें हैं। जैसा कि मेरे एक साथी कह रहे थे, एक दृष्टि से बहुत आश्चर्य होता है कि कम से कम सब पार्टियों के लोगों ने एक न एक तरह से उसका समर्थन किया है। कम्यूनिस्ट भी कहते हैं, सोशलिस्ट भी कहते हैं, जनसंघ वाले भी कहते हैं। कुछ का समर्थन करते हैं और कुछ का विरोध करते हैं। मैं इस बारे में ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि इस देश में किसी भी पार्टी का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिस ने इस बात का समर्थन न किया हो कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। किसी पार्टी का ही नहीं, हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि विदेश का हर आदमी, चाहे वह कम्यूनिस्ट देश का हो चाहे सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट देश का हो क्यों न हो, इसका समर्थक है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे बड़े-बड़े बांध, और बड़े-बड़े कारखाने शक्तिशाली सेना इस बात के साक्षी हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारी राष्ट्रीय आय

बढ़ी है, केवल आंकड़ों से ही नहीं बल्कि वास्तव में बढ़ी है। लेकिन इस के साथ ही साथ मैं इस संबन्ध में ज्यादा न कह कर कुछ थोड़ी सी बातें आलोचना की दृष्टि से कहना भी चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि समाजवाद जो हम लाना चाहते हैं उस समाजवाद को लाने के लिये जो रास्ता हम चल रहे हैं वह बहुत धीमा है। इतना धीमा है कि आम जनता को यह विश्वास नहीं होता कि उनके या उनके बच्चों के समय में यह समाजवाद आ सकेगा।

मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, लेकिन उसका वितरण इस तरह हो रहा है कि वह आम आदमी तक नहीं पहुंच रही है। मैं एक उदाहरण दूं। जसे कभी-कभी दावतों में होता है जहां वैरा वगैरह सामान लाते हैं। तो जो लोग सामने होते हैं वे उस सामान को साफ कर देते हैं, दोबारा जब वे फिर लाते हैं तो आगे वाले फिर उसको साफ कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि कुछ आदमी जो कि पीछे होते हैं उनको नहीं मिल पाता। इसी तरह से देश तरक्की कर रहा है लेकिन उसका लाभ कुछ आदमी ही उठा लेते हैं। हम देखते हैं कि जितने लोग पांच सौ तनखाह पाते थे उनकी संख्या बढ़ गयी है। हम यह भी देखते हैं कि जिन लोगों की आमदनी चार और पांच हजार थी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गयी है, आप बड़े-बड़े कस्बों और शहरों में देखेंगे कि बड़े-बड़े मकानों की भी संख्या बहुत बढ़ गयी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर आप किसी झोंपड़ी को जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें जितना फंस पहले होता था वह भी कम हो गया है। अगर आप किसी किसान और मजदूर के घर की हालत को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके खाने में दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है।

हम यह भी देखते हैं कि कपड़े का उत्पादन बढ़ा है। उसका उपयोग चाहे बड़े—बड़े मकानों में परदे डालने के लिए या फर्श पर बिछाने में अधिक होने लगा हो लेकिन एक गरीब के घर में जाकर देखिए कि जितना कपड़ा पहले इस्तैमाल होता था उससे अधिक नहीं होता। मैं उनकी हालत को जानता हूं क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाखडा नंगल को दिखाकर, या चित्तरंजन और दुर्गापुर के कारखानों को दिखाकर या दिल्ली के महलों और सड़कों को दिखाकर देश की उन्नति का सबूत आम जनता को नहीं दे सकते इसके लिये तो हमें जनता के उनके स्वयं के घर को दिखाकर कहना पड़ेगा कि स्वयं भी हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हो। ताकि जनता यह न कह सके कि जो गरीब है वह और अधिक गरीब होते जा रहे हैं और जो धनी हैं वह और अधिक धनी होते जा रहे हैं।

यह भी कहा जाता है कि बेकारी दूर की जा रही है। इसके सबूत में जो आंकड़े दिए जाते हैं उनसे ठीक पता नहीं चल सकता। यह ठीक है कि बेकारी दूर हो रही है, लेकिन यह इस तरह हो रहा है कि जिस घर में ६ आदमी नौकर थे और दो बेकार थे उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन जिस परिवार में कोई भी नौकर नहीं है उस परिवार के व्यक्तियों को दो योजनाएं पूरी हो जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। जिनकी पहुंच होती है उनको स्थान मिल जाता है। इस प्रकार जिनके घर में पहले से चार आदमी नौकर थे उस घर के ही अन्य व्यक्तियों को नौकरी मिलकर बेकारी दूर हो जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़े लेकिन उसका हिस्सा गरीब आदमियों को भी मिले। कभी-कभी हमारे पंडितजी कह देते हैं कि हम गरीबी को बांटना नहीं चाहते। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें गरीबी को बांटना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विषमता के कारण लोगों में असंतोष पैदा होता है। जब हम लोग चुन

[श्री दि० सिं० चौधरी]

कर आते हैं और देखते हैं कि एक को तो रहने को अच्छा फ्लैट मिल गया और दूसरे को वैसा नहीं मिला तो हमको भी बुरा मालूम होता है। अगर सबके लिए एक ही प्रकार के मकान होते तो किसी को यह ख्याल न होता। इसी तरह से जब एक आदमी देखता है कि एक आदमी साधन सम्पन्न है और वह नहीं है तो उसको दुःख होता है और वह इसको बरदाश्त नहीं कर सकता।

मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो आपने टैक्स लगाए हैं अगर इनके बजाए आप प्राइवेट मोटरों पर टैक्स लगाते तो सड़कों की भीड़ कुछ कम हो गयी होती। डिनर और डांस के लिए जो मोटरें दौड़ी फिरती हैं वे कम हो जातीं। मैं कहता हूं कि आपको टैक्स लगाना चाहिए प्राइवेट मोटरों के पट्रोल पर और पाउडर और लिपस्टिक पर जिनको केवल बड़े आदमी इस्तैमाल करते हैं। ऐसा किया जाए तो आम जनता के दिल में उत्साह पैदा होगा। अगर समाजवाद लाना है तो इस तरह के कदम उठाने चाहिएं। धीमे ढंग से समाजवाद लाने का प्रयत्न करेंगे तो जनता इन्तिजार नहीं करेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिस पर जनता को विश्वास हो। उसका नतीजा यह हुआ कि यद्यपि जनता ने पिछले चुनावों में पार्टियों के अच्छे नेताओं को हरा दिया क्योंकि उनका विश्वास हो गया है कि पार्टियों से उनकी भलाई नहीं होती।

मेरा निवेदन है कि यदि हमने पूंजीवाद को खत्म नहीं किया तो ये पूंजीवाद हमें खत्म कर देगा। आप वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। यह तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई आदमी जो चारों ओर डकैतों को पकड़ना चाहता है वह ऐसा पहले से कह कर उनको आगाह कर दे ताकि वे बच जाएं। हम अगर कोई ऐसी योजना या कार्यक्रम बनाते हैं तो लोगों को पहले से कह देते हैं। जैसे कि सीलिंग का ही मामला लीजिए। पहले से कह दिया था इसलिए लोगों ने पहले से जमीनों का बटवारा कर लिया। इसी तरह से हम समाजवाद लाने के लिए कह रहे हैं लेकिन अगर हमने पूंजीपतियों की पूंजी खत्म न की तो मैं कहता हूं कि उसी पूंजी से वे हमको खत्म कर देंगे। अगर आप पूंजीपतियों को खत्म कर दें तो देश का भ्रष्टाचार आज खत्म हो जाए और हम अपने सरकारी कर्मचारियों से अच्छे काम की आशा कर सकें। क्योंकि योग्य पूंजीपति स्वयं पूंजीपति न रहने पर सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करके पूंजीपति न बनने देंगे।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे गांवों की जितनी उन्नति सरकार को करनी चाहिए वह नहीं कर रही है। मैं इसका सबूत देना चाहता हूं। खादी उत्पादन आदि में सरकार मूल्य कम करके आर्थिक सहायता देती है। जिन चीजों को पूंजीपति बनाते हैं, जैसे कार है, उनके बाहर से लाने पर सरकार टैक्स लगाती है इससे बाहर की चीज यहां सस्ती नहीं हो पाती। और पूंजीपति उन चीजों को यहां बना कर ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेच लेते हैं। मगर किसान जो अपना उत्पादन करता है उसके गल्ले के मुकाबले में हम बाहर से गल्ला मंगा कर सस्ता बेचते हैं। जिससे किसान को अपनी पैदावार के उचित दाम नहीं मिल पाते जहां हम पूंजीपतियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता देते हैं वहां किसानों के लिए उलटा करते हैं।

मुझे तो उस समय यह सुन कर दुःख हुआ जब कृषि मंत्री ने कहा कि किसान उस चीज का उत्पादन करना चाहता है जिसमें कि उसे पैसा ज्यादा मिले। और उन्होंने कहा कि वे कोई

ऐसा कानून बनाएंगे जिससे ऐसा न हो सके। मैं कहता हूं कि किसानों की हालत वैसे ही खराब है। यदि सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद लाने के लिए हमें कोई और मजबूत कदम उठाने चाहिएं। इस धीमी गति से नहीं चलना चाहिए। अगर हमने अपनी गति नहीं बदली और हमनें जमाने को नहीं बदला तो जमाना हमें बदल देगा। मैं कहता हूं कि ये पूंजीपति अपनी पूंजी के द्वारा चुनावों में विजय प्राप्त करके और दूसरे तरीकों से ऐसी व्यवस्था ले आएंगे जिसको हम नहीं चाहते। और जिस व्यवस्था को हम लाना चाहते हैं उसको नहीं लाने देंगे। अगर हमने मजबूत कदम उठाए तो हमारे किसान और मजदूर यह समझ जाएंगे कि पूंजीपतियों के साथ भी उचित व्यवहार हो रहा है और जब उनको पता चल जाएगा कि पूंजीपतियों की भी स्थिति खराब हो रही है और उनकी स्थिति हम से अच्छी नहीं है तो वे मेहनत से काम करेंगे और आपको पूरा सहयोग देंगे क्योंकि उनको विश्वास हो जाएगा कि अब गरीब अधिक गरीब नहीं होगा और पूंजीपति अधिक धनी नहीं होगा।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र मथुरा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वहां के किसानों की हालत बहुत खराब है। मैं एक बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर होने के नाते जानता हूं कि बीस लाख से उनका कर्जा प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। मथुरा नगर कृष्ण भगवान की जन्म भूमि है। इसने बड़े-बड़े प्रहार सहे फिर भी अपने को कायम रखा। मथुरा का अपना एक विशेष स्थान है। केवल उत्तर प्रदेश के नाते या हिन्दुस्तान की दृष्टि से नहीं उसका संसार में एक विशेष स्थान रहा है। आज वहां की हालत यह है कि आर्थिक कठिनाई के कारण लोग बाहर से वहां आकर कम दान देते हैं इसलिए वहां के पंडा पुजारियों और जनता को हालत खराब हो रही है और उनको कोई आमदनी नहीं है। कोई उद्योग वहां नहीं हैं। परिणाम यह है कि वहां के चतुर्वेदी जो पहले भांग पीते थे और पहलवानी करते थे उनको आप देखें उनकी सूरत ही बदल गयी है। उनकी हालत पहले के मुकाबले में बहुत खराब हो गयी है। इस प्राचीन नगरी व इस किले की गरीबी और भुखमरी दूर करने के लिये यहां कोई बड़ा उद्योग खुलना चाहिये।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों के मजदूर और किसान पूरा सहयोग दें, अगर हम चाहते हैं कि लोगों में जो अविश्वास पैदा हो गया है वह दूर हो जाए तो हमें मजबूत कदम उठाने होंगे और उसके लिए हमारे मंत्री महोदय और हमारे प्रधान मंत्री पूर्ण रूप से समर्थ हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है कि हम कोई क्रान्तिकारी कदम उठाएं और समाजवाद को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था अथवा आर्थिक स्थिति उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब कि वह देश विकास की ओर अग्रेसर हो रहा हो, उसकी आर्थिक स्थिति का संतुलन रखना अत्यन्त आवश्यक है। पिछले कई वर्षों का अनुभव इस बात का साक्षी है कि हमारे देश की नीति आदर्शवादी पक्ष की ओर अधिक बढ़ती जा रही है और उस में व्यावहारिकता का अभाव है। आकस्मिक परिवर्तन जो वित्तीय नीति में समय-समय पर होते रहते हैं उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि उत्पादन के उपक्रमों पर

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और देश में टैक्सों की व्यवस्था का भार भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है ।

दूसरी बात जो मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो रहा था उस समय यह निश्चय किया गया था कि हमारे देश पर ११०० करोड़ रुपये के कर लगाये जायेंगे । इस ११०० करोड़ रुपये के करों के सम्बन्ध मे उस समय भी पर्याप्त आलोचना हुई थी परन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय अथवा हमारी सरकार इस को और भी तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। पिछले वर्ष हमारे देश पर जो टैक्स लगाये गये थे उनकी संख्या ४५० करोड़ रुपये थी लेकिन जैसे कि सरकार की नीति है कि राजस्व की प्राप्ति को वह हमेशा कम कर के दिखाती है और उस आधार पर अपना बजट बनाती है, उसे ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि हमारे देश में पिछले वर्ष में लगभग ५५० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी । इस वर्ष जो भी प्रस्तावित करों की योजना सामने आई है उस में भी ६०० करोड़ रुपये की प्राप्ति हो सकेगी । ५ वर्षों में जो ११०० करोड़ रुपये के कर लगाये जायेंगे वह तो इन दो वर्षों में पूरे हो रहे हैं। इस से प्रतीत होता है कि आने वाले ३, ४ वर्षों में हवा का रुख बहुत ऊंचा उठेगा । मैं नहीं कह सकता कि हमारी सरकार अर्थ नीति में इस प्रकार के आकाशीय परिवर्तन क्यों कर रही है और देश के कंधों पर करों का और टैक्सों का इतना भारी बोझ किस दृष्टि से लादा जा रहा है ? यह स्थिति सामान्य करों के सम्बन्ध में है जब कि रेलवे बजट से भी २५० करोड़ रुपये हमें प्राप्त होने हैं।

तीसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि इस समय हमारे देश की राष्ट्रीय आय १३ खरब रुपये की है । इस १३ खरब रुपये की आय में से १ खरब ७० अरब रुपये अर्थात् १४ प्रतिशत धन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें करों के रूप में हम से ले लेती हैं . . .

वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : रेलवेज के बारे में माननीय सदस्य ने क्या कहा ? २५० करोड़ रुपये की आमदनी हमको रेलवेज से होगी यह जो उन्होंने कहा वह सही नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि जो सामान्य कर लगाये जा रहे हैं उस के अतिरिक्त रेलवेज से जो आय होगी वह २५० करोड़ रुपये की होगी। इस लिए पहले ही जब आय इतनी पर्याप्त थी तो उस के होते हुए इतने अधिक करों का भार दश के कंधों पर लादना यह समय और परिस्थिति को देखते हुए संगत नहीं प्रतीत होता......

श्री मोरारजी देसाई : २५० करोड़ रुपये की रेलवेज़ से कैसे आमदनी होगी, मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी रेलवेज ने जो अपना टैक्स बढ़ाया है वह तथा अन्य आय, २५० करोड़ रुपये की होने का अनुमान है.....

श्री मोरारजी देसाई : आगामी चार साल ही तो रहे । उन में सालाना २१, २२ करोड़ रुपये के कर लगेंगे तो भी यह ८५, ८६ करोड़ रूपये से ज्यादा नहीं होगा । यह २५० करोड़ रुपये आप कहां से ले आये ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा अनुमान समस्त आय के सम्बन्ध में है । इन सब को मिला कर ही मैं अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं ।

चौथी बात केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में है । १३ खरब रुपये की हमारे देश की राष्ट्रीय आय हैं । उस १३ खरब रुपये में से १ खरब ७० अरब रुपये हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें टैक्सों के रूप में ले लेती हैं अर्थात् १४ प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आय का सरकारें ले लेती हैं । इस में जो देश की ४४ करोड़ ३० लाख की जनसंख्या है करीब दस लाख व्यक्ति एसे हैं जो आय कर देते हैं और यही १० लाख व्यक्ति एसे हैं जो छोटे और बड़े सब मिला कर निर्माण का कार्य भी करते हैं । मैं चाहता हूं कि जो प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारें टैक्सों के रूप में जो रूपया प्राप्त करती हैं, थोड़ा अपने व्यय के ऊपर संतुलन रक्खें जिस से कि देश पर करों का भार अधिक मात्रा में न बढ़े ।

पिछले पांच वर्षों मे ८ अरब रूपये का कराधान हुआ है किन्तु केन्द्रीय सरकार का खर्च आमदनी से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है । इस में आधे के लगभग व्यय तो इस प्रकार का है कि जिस से कोई उत्पादन होता ही नहीं । अनुत्पादक कार्यों पर पैसा खर्च होता है । प्रतिरक्षा पर व्यय होता है और असैनिक प्रशासन पर होता है अथवा जो हमारे ऊपर ऋण है उसका सूद अदा करने में यह खर्च हो जाता हैं । बाकी रुपया कुछ इस प्रकार का है जिस से कुछ उत्पादन का औसत बढ़ता है और उस में सरकारी उद्योगों का पब्लिक सैक्टर का नम्बर विशेष रूप से आ जाता है ।

सरकार के द्वारा जो उद्योग चालू हैं उन की संख्या ७३ है । मार्च १९६१ के अन्त तक कुल मिला कर इन ७३ उद्योगों में ६०६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी । १९६०–६१ में केवल २.१ करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो कि ·३५ प्रतिशत है । १९६१ और १९६२ में १०३.५ करोड़ रुपये की और अतिरिक्त पूंजी इन में लगायी गयी पर यह आय १.६५ करोड़ रुपये से अधिक होने की आशा नहीं है अर्थात् .२४ प्रतिशत लाभ है । बजट जो इस साल प्रस्तुत हुआ है उस को देखने से यह भी प्रतीत होता है कि सन् १९६२–६३ में १६०.१० करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोग इन में और किया जायगा । इस प्रकार कुल मिला कर सरकारी उपक्रमों में ८६९ करोड़ रुपये की पूंजी हो जायेगी । इतनी अधिक पूंजी जहां लगी हुई हो और उस से जो आय होनी चाहिये वह सर्वथा नगण्य न होनी चाहिये लेकिन चूंकि वास्तविक स्थिति यह है कि वह नगण्य है इसलिये यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उस में कोई दुर्बलता अवश्य अपेक्षित है ।

सरकार के इन ७३ उद्योगों में केवल एक उद्योग हिन्दुस्तान मशीन टूल्स इस प्रकार का है जो सरकार और देश दोनों के संतोष का विषय है बाकी जो ७२ उद्योग

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हैं उनको देखते हुए जितनी अपेक्षित आय उन से होनी चाहिए उस की संभावना कम है ।

एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह असैनिक व्यय के सम्बन्ध में है । सरकार जहां देश के कंधों पर इतना भारी बोझ लाद रही है मेरा अभिप्राय: सैनिक व्यय से नहीं है, हमारे देश में जो प्रतिरक्षा के ऊपर व्यय होता है वह तो परिस्थितियों को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक ही है, हां, सावधानी उस में भी अपेक्षित है यह बात दूसरी है । परन्तु मैं असैनिक व्यय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उस की मात्रा जो आज बराबर बढ़ती जा रही है, सरकार जब देश से यह अपेक्षा करती है कि वह त्याग करे और कर दे तो सरकार को भी उस में मितव्ययता बर्त्तनी आवश्यक है । दूसरे देशों में जो कर लिये जाते हैं उन की अपेक्षा हमारे देश में करों की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है । व्यक्तिगत आय पर हमारे देश में जो टैक्स लगता है वह सब मिला कर ८७ प्रतिशत के लगभग लगता है । अमरीका में एक लाख रुपये की आय पर २३ प्रतिशत और ब्रिटेन में ४६ प्रतिशत टैक्स है लेकिन भारत में यह ५४ प्रतिशत से लेकर ६३ प्रतिशत तक आकर बैठता है । अमेरिका में करों की अधिकतम दर १५ लाख रुपये की आय पर व ब्रिटेन में २ लाख रुपये की आय पर लागू की जाती है जब कि भारत में यह ७० हजार रुपये के निम्न स्तर पर ही लागू हो जाती है । दूसरे उन देशों में भारत की तरह सम्पत्ति कर भी नहीं है ।

श्री मोरारजी देसाई : यह मैं कह सकता हूं कि यहां की एक लाख की आमदनी अमरीका में ५० लाख की आमदनी से भी ज्यादा होगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सम्भव है आप के कहने में कुछ सचाई हो . . .

श्री मोरारजी देसाई : काफी सच्चाई है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस देश की स्थिति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि हम जब संसार के साथ प्रगति में कंधे से कंधा मिला कर खड़ा होना चाहते हैं तो आर्थिक व्यवस्था में हम इतना संतुलन अवश्य रक्खें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिये वर्तमान समय संतोष का कारण बन सके ।

एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हम जिस समय टैक्सों का बोझ अपने देश के कंधों पर लादें तो इस बात का ध्यान अवश्य रक्खें कि विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक विनियोग हम देश में करें, हम देश में करों को लगाते समय इस बात को न भूल जांय कि हमारे देश में पूंजी लगाने की अपेक्षा वह लोग दूसरे देशों में पूंजी लगाना अधिक पसन्द करते हैं । इस लिए इस सम्बन्ध में भी सतर्कता आवश्यक है ।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए एक ज़रूरी बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो टैक्सों को प्राप्त करने वाली मशीनरी है, वह शुद्ध नहीं है जहां हमारे वित्त मंत्री जी प्रतिवर्ष नया कर देश के कंधों पर लगा कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं उससे कहीं अधिक अच्छा हो कि जितने टैक्स अब तक देश पर लगे हुए हैं उनको व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने की दिशा

में भी वह उतने ही सतर्क रहें। मेरा यह विश्वास है कि जितने टैक्स अब तक हमारे देश पर लगे हुए हैं अगर वह टैक्स पूरे प्राप्त हो जायं तो देश में और कोई नया टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि जितने टैक्स लगे हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा भाग इस प्रकार का है जो कि बीच में ही अटक कर रह जाता है और सरकार के कोष तक वह पूरा भाग नहीं पहुंच पाता।

एक दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है जिसकी कि ओर हमारे माननीय राष्ट्रपति ने अभी परसों अपने बिदाई भाषण में संसद सदस्यों को संकेत दिया और वह है निर्वाचन व्ययों के सम्बन्ध में।

हमारे देश में लोक सभा के जो निर्वाचन होते हैं उनके लिए २५ हजार रुपये की राशि आपने निर्धारित की है। अब आर्थिक दृष्टि से कितने व्यक्ति इस देश में आपको मिलेंगे जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे? जैसा मैंने पहले आपको बतलाया कि हमारे भारतवर्ष में ४४ करोड़ ३० लाख की जनसंख्या में केवल १० लाख व्यक्ति ही ऐसे हैं जो कि आय कर देते हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसके रहते कितने व्यक्ति इस देश में लोक सभा का चुनाव लड़ सकेंगे। इस में एक सब से बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग चुनाव लड़ कर आते हैं, बम्बई का चुनाव ही मैं उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं, बम्बई में अभी हाल में जो चुनाव हुआ, उन व्यक्तियों का नाम लेना संसदीय परम्परा के विपरीत हो जायगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे बम्बई का नाम लेने से ही सब लोग समझ गये होंगे कि मैं किस ओर संकेत कर रहा हूं। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उस चुनाव के ऊपर केवल २५,००० रुपये व्यय हुए थे? जब ऐसी स्थिति हो तो यह कहना कि २५,००० रुपये से जो उम्मीदवार चुनाव में अधिक व्यय करेगा उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जायगा कहां तक तर्कसंगत है? क्या सरकार निष्पक्ष होकर इस दिशा में कोई निर्णय ले सकेगी और कोई जांच कर सकेगी कि वास्तविकता क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का नियम और विधान बनाने की क्या आवश्यकता है जो कि वास्तविकता पर आधारित न हो, या जिसमें चोरीयां झूंठ सिखायें जायें।

एक अन्तिम बात जो कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि अभी परसों हमारी सरकारी बैंचों पर बैठने वाले एक व्यक्ति ने अपने भाषण में यह संकेत दिया था कि समाजवाद का नारा हमारी सरकार लगाती तो है लेकिन पंडित जी के दांयें बांयें कुछ ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जिनके कि गले के नीचे समाजवाद का शब्द बिलकुल नहीं उतरता है। पर मैं उससे बिलकुल उल्टी बात कहना चाहता हूं कि समाजवाद का नारा तो हमारी सरकार लगा रही है, लेकिन कहीं पंडित जी के दायें बायें ऐसे व्यक्ति तो नहीं बैठते, जो कि समाजवाद की आड़ में साम्यवाद को देश पर ठूंसना चाहते हैं या इस देश में साम्यवाद को लाना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों दिशाओं से ही देश को सजग रहने की आवश्यकता है। पूंजीपतियों के हाथों से भी हम बचें और साम्यवाद के भी शिकार न हो जायें।

श्री चं० ला० चौधरी (महुआ): उपाध्यक्ष महोदय, आज कई दिनों से बजट पर बहस-मुबाहसा हो रहा है। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, सारे देश के हितों को सामने रखते हुए और इस मुल्क से ग़रीबी को ज्यादा से ज्यादा दूर करने के उद्देश्य से यह बजट हाउस के सामने रखा है। वह इस मुल्क से गुरबत को दूर करने के लिए सारे दिलों-दिमाग़ और बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।

[श्री चं० ला० चौधरी]

मेरा अपना ख्याल यह है कि जिस देश की इकोनोमिक हालत खराब हो जाय और अ ब्लीक स्तर गिर जाय, उसके नागरिक और नौजवान कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने देश की सेनाओं पर ज्यादा खर्च किये जाने का आरोप लगाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सोलजरस लद्दाख जैसे क्षेत्र में दुश्मन के मुकाबले में डटे हुए हैं, जहां यह स्थित है कि अगर कोई बर्फ़ की चट्टान से गिर जाय, तो वह दो तीन हज़ार फीट नीचे लुढ़क कर मर जाय। आज वे लोग अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन पर जितना भी खर्च किया जाय वह उचित है। जो लोग इस बात की नुक्ता-चीनी करते हैं, वे मुल्क को कमज़ोर करते हैं और दुश्मनों के हाथ मजबूत करते हैं।

मैं समझता हूं कि जब हमारी भारतीय सेना एटम बम या मशीनगन व राइफल लेकर दुश्मनों के सामने खड़ी होती है, तो वह अपनी जान की परवाह नहीं करती और अपनी भूमि के एक-एक इंच टुकड़े के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार रहती है। इस नुक्ताएनिगाह से मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट में सेना के लिए जो खर्च रखा है, वह बहुत कम है। अगर अपने सोलजर्स पर हम उस से भी अधिक खर्च करें, जिससे हम अपने तमाम दुश्मनों पर कामयाब हो जायें और उनके छक्के छुड़ा दें, तो फिर यह बजट एक बिल्कुल कामयाब बजट होगा।

माननीय सदस्यों ने बजट के सम्बन्ध में कई बातें कही हैं। कई माननीय सदस्यों ने हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में कहा और कुछ ने यह कहा कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि कृष्ण की जन्म-भूमि पर जो पंडे लोग रहते हैं, जो कि भांग भूरा पी कर मस्त रहते और और मक्खन मलीदा खाकर और जिनके चेहरों पर सुर्खी और लालिमा रहा करती थी उनके हितों का ख्याल रखा जाय। मैं समझता हूं कि मुल्क को गंगा के किनारे पर भांग पी कर मस्त रहने वालों की ज़रूरत नहीं है। मुल्क को उन लोगों की ज़रूरत है, जो कि मार्च करें और लद्दाख पर दुश्मनों का मुकाबला करें।

श्री रामसेवक यादव : गंगा के किनारे तो प्रधान मंत्री जी रहते हैं।

श्री चं० ला० चौधरी : वे रहते हैं, इसीलिए मुल्क में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। वह मुल्क का अकेला जवाहर है।

हिन्दुस्तान में इस वक्त जो फ़िर्कापरस्ती और जातीयता फैली हुई है, में उस के सख्त खिलाफ़ हूं। मैं कह देना चाहता हूं कि हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज़ और शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर जो छात्रवृत्तियां और स्कालरशिप्स दिये जाते हैं, वे बड़े बड़े धनाढ्यों के बच्चों को मिल जाते हैं और ग़रीबों, मस्कीनों और यतीम बच्चों को नहीं मिलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूलों और कालेजों में जो ब्राह्मण, राजपूत या कायस्थ बच्चे पढ़ते हैं, जिनके फ़ादर या ग्रांड-फ़ादर सौ या पचास रुपए महीने पर सरकारी दफ़्तरों मे काम करते हैं, उन के लिए इस युग मे पढ़ना बहुत मुश्किल है। सरकार हरिजनों को तरजीह दे, इस में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आप का ध्यान उन ग़रीब ब्राह्मणों तथा दूसरी जातियों की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं, जो दरवाज़े-दरवाज़े भिक्षाटन कर के संस्कृत के विद्वान बनते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वे पढ़ने से मजबूर हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि हमारा देश विद्या से खाली होता जा रहा है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस तरफ़ ध्यान देंगे।

पिछली दफ़ा भी मैंने इस सदन में कहा था कि भारतवर्ष की स्थिति यह है कि जो स्त्री विधवा हो जाये और उस के चार बच्चे हों और उन के पास आजीविका का साधन न हो, तो फिर उन मासूम बच्चों के खाने-पीने, दूध और एडूकेशन का कोई उपाय नहीं होता है। हमारे यहां दूसरी शादी की गुंजायश नहीं होती है। हमारे यहां की स्त्रियां जान दे देती हैं, लेकिन दूसरी शादी करना पसन्द नहीं करती हैं। कुछ वर्गों में जिन का नाम मैं नहीं लेना चाहता, दूसरी शादी हो जाती है। इसलिए मैं नम्रनिवेदन करना चाहता हूं कि उन ग़रीबों की तरफ़, उन बेवाओं की तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक मेरा ख़याल है, मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुसलमानों में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाह वाले ही व सल्लम की धार्मिक तौर पर रवायत है कि मस्कीनों और बेवाओं की मदद करनी चाहिए। धार्मिक तौर पर उन का यह कर्तव्य है। हमारे धर्म में भी कहा गया ह कि विधवाओं और उनके बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस से मुल्क शक्तिशाली होगा। मालूम नहीं, उनमें से कोई कितना बड़ा इंजीनियर हो, अगर हम उनके पढ़ाने का इन्तज़ाम करें और उनकी मदद करें। मैं यह नहीं कहता कि हरिजनों और बैकवर्ड लोगों की मदद न की जाये, लेकिन विधवाओं की तरफ़ ख़ास तौर पर तवज्जह दी जानी चाहिए।

मैं अपने दो तीन लड़कों को पढ़ाता हूं। एक एक बच्चे पर चालीस पैंतालीस रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं। मैं करता हूं। लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट या यू० पी० गवर्नमेंट में ५०,६० रुपए पर मुलाज़िम किसी क्लार्क के चार बच्चे हों, तो वह कैसे उन को पढ़ा सकता है? इसलिए उनके बच्चों की एडूकेशन का ख़ास इन्तज़ाम किया जाना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क शक्तिशाली हो।

माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट हाउस के सामने रखा है मैं उस का तह-दिल से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर बराबर इस किस्म का बढ़िया बजट आता रहा, तो हमारा मुल्क निहायत कामयाब होगा। आज़ादी के बाद सारे मुल्क ने जो तरक्की की है, शायद दूसरी पार्टी वालों ने अपने मुल्क के गोशों में जा कर उस को देखने की कोशिश नहीं की है।

हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद हरिजन आदि कई वर्ग, जो कि ज़ात-पात पर आधारित होते हैं, अपना अपना हक मांगने के लिए खड़े हो गए हैं। मैं इस बात का क़ायल नहीं हूं। मैं इस बात का कायल हूं कि महज कांग्रेस ही ऐसी संस्था है, जिस के ज़रिये अलग अलग वर्गों का नहीं बल्कि हर एक हिन्दुस्तानी का भला सोचा जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : अर्थ मंत्री जी ने जो बजट पेस किया है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

इस बजट पर दो तीन दिन से बहस हो रही है। विरोधी दलों के कुछ माननीय सदस्यों ने इस बजट की टीका टिप्पणी की है। यह स्वाभाविक था क्योंकि उनको विरोध करके ही जिन्दा रहना है। उनसे समर्थन की आशा नहीं की जा सकती है। उन्होंने इसको एक कैपिटलिस्ट बजट बताया है। उनको इसमें समाजवाद की गंध भी नहीं आती। कुछ तीखी टीका टिप्पणी भी उन्होंने इस बजट की की है। इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन इस तरफ से बोलने वाले एक माननीय सदस्य श्री अंसार हरवानी ने उनसे दो कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि इस बजट से लोगों का समाजवाद में और प्लानिंग में विश्वास घट गया है। इससे ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बात मैं समझता हूं, दूसरी नहीं हो सकती है। समाजवाद ऐसी चीज़ नहीं है, कोई धर्म या मत नहीं है जिस की रूपरेखा या जिस की परिभाषा ठीक ठीक की जा सके। प्रत्येक देश की स्थिति अलग अलग होती है, वहां का इतिहास, वहां की सामाजिक स्थिति, वहां के लोगों का रहन सहन अलग अलग होता है और उस सब पर उसके विकास

[श्री रावेलाल व्यास]

का कार्य निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक देश में जो भी कदम समाजवाद की ओर उठाया जाता है, वह भिन्न भिन्न ही हो सकता है।

आज़ादी के बाद संविधान सभा ने जब संविधान बनाया, तो उसने राज्य की नीति के निदेश सूचक जो व्यवस्था उस में की, जो निदेश दिए, वे हमें बतलाते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। सही मानों में उन्हें कार्यान्वित करने का जो कार्य है, वह हमें समाजवाद की ओर ले जाएगा।

समाजवाद के सम्बन्ध में यह शंका की गई है कि हमारे यहां बहुत थोड़े से पूंजीपति हैं जो काफी मालदार हो गए हैं। कुछ ने काफी पैसा कमाया, काफी मुनाफा बांटा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने आज देश में मिक्स्ड इकोनोमी को मंजूर किया है। इसके साथ ही जनतांत्रिक पद्धति से हम को अपने कार्य को आगे बढ़ाना है और वह भी लोगों की सहमति से, लोगों की रज़ामन्दी से करना है। लोगों को राजी रखते हुए, कानूनों के द्वारा हमको आगे बढ़ना है। यह डिक्टेटरशिप का नहीं जनतंत्र का तरीका है। जिस समय से पंचवर्षीय योजना को इस माननीय सदन ने स्वीकार किया, एप्रूव किया, तब से यह हमारी जिम्मेवारी हो गई है कि उसी को कार्यान्वित करने के लिए हम बजट बनाये। प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है और इनको प्लान बजट कहा जा सकता है। जो उस वर्ष की योजनायें होती ह, उनको कार्यान्वित करने के लिए और जो टारगट्स निर्धारित किए गए होते हैं, उनको पूरा करने के लिए बजट पेश किए जाते हैं।

आज से चौदह वर्ष पहले हमारे देश की जो हालत थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इन चौदह वर्षों में हम आगे बढ़े हैं यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ेगा कि हमारे देश ने काफी तरक्की की है, काफी उत्पादन हमारा बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में भी। लेकिन जहां सारे देश की तरक्की को हमें देखना है वहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में कुछ हिस्से हैं, कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं, जो अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं कई दृष्टियों से। यह प्रसन्नता की बात है कि प्लानिंग कमिशन ने एक स्टडी टीम मुकर्रर की है और उसके सुपुर्द यह काम किया गया है कि वह देखे, अध्ययन करे, कि अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, कोई राज्य ज्यादा पीछे तो नहीं रह गए हैं, वहां पर विकास जितना होना चाहिये, हुआ है या नहीं हुआ है। इस टीम को मुकर्रर हुए दो साल होने को मेरे खयाल में आए हैं। स्टडी टीम ने क्या काम किया है, अपने काम में क्या प्राग्रेस की है, कितना आगे वह बढ़ी है, कितने आंकड़े एकत्रित किए हैं, अभी मालूम नहीं हो सका है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वह टीम अपना कार्य पूरा करे और रिपोर्ट पेश करे ताकि सदन के सामने वह रिपोर्ट आ सके और सही चित्र जो देश का है, अलग अलग राज्यों का है, उसका हमें पता चल सके और हम निश्चय कर सकें कि और कौन कौन सी कारवाई करने की आवश्यकता है जिससे जो प्रदेश बहुत ज्यादा पिछड़े रह गए हैं, वे कुछ आगे बढ़ सकें।

समाजवाद को लाने के लिए सर्वतोमुखी विकास आवश्यक है। एक दम वह नहीं आएगा। एक साल के बजट में या दो साल के बजट में समाजवाद अगर कोई समझता है कि आ जाएगा तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। अगर कोई समझता है कि अगले चार पांच साल में समाजवाद आ जाएगा तो यह भी उसकी बहुत बड़ी भूल है। समाजवाद लाने के लिए चौथी योजना, पांचवी योजना और शायद और भी योजनाओं को हमें कार्यान्वित करना होगा। तब कहीं सही मानों में समाजवाद की स्थापना हो सकेगी। समाजवाद को लाने के लिए शिक्षा का प्रबन्ध हमें करना होगा। काफी शिक्षा का प्रबन्ध हुआ है। हम देखते हैं कि कितने ही स्कूल, कितने ही कालेज, कितनी ही यूनिवर्सिटियां देश में खुली हैं। लेकिन एक बात की ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं। शासन ने व्यवस्था की

है कि जहां शिक्षा महंगी है वहां गरीबों के बच्चे जो योग्य हैं, वे शिक्षा पाने से पैसे के अभाव में वंचित न रह जायें, इसलिए उनको स्कालरशिप दिये जायें। लेकिन मुझे जहां तक मालूम हुआ है। जो फर्स्ट क्लास में पास होते हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा सात आठ परसेंट को ही स्कालरशिप मिल पाते हैं सैंकड़ों और हज़ारों की संख्या में गरीब विद्यार्थियों को जो महंगी शिक्षा है, इंजीनियरिंग की, मेडीकल की या एग्रीकलचर की, नहीं मिल पाती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं। मैं मानता हूं कि स्कालरशिप प्रत्येक विद्यार्थी को तो नहीं दिया जा सकता और न ही इतने रुपये की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन कुछ ऐसा रुपया जरूर आप निकालें जोकि उन लोगों को कर्ज के रूप में दिया जा सके और बाद में जिस समय वे अपनी शिक्षा पूरी कर लें और किसी व्यवसाय में लग जायें, नौकरी पर लग जायें, किसी धंधे में लग जायें, तो उस रुपये को इंस्टालमेंट में वापिस दे सकें। यदि यह व्यवस्था कर दी जाए तो जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो मध्यम वर्ग के विद्यार्थी हैं और जो साइंटिफिक और टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त करने से पैसों के अभाव में वंचित रह जाते हैं, वे उससे वंचित नहीं रहेंगे। यह केवल फर्स्ट क्लास में जो पास होते हैं, उनके लिए ही नियम नहीं होना चाहिये बल्कि जो सकिंड क्लास में भी होते हैं और जो आगे दो तीन महीनें पढ़ने के बाद यह बता सकें कि उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की है, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिये।

हमें रिजनल डिसपेरिटीज़ की ओर भी ध्यान देना होगा। मध्य प्रदेश आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिहाज़ से सब से बड़ा और मोटा राज्य है हमारे कुछ मित्रों ने अपने राज्यों की कुछ बातें कही हैं। किसी को यह शिकायत है कि वहां रेलें नहीं है और किसी को यह शिकायत है कि वहां हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मध्य प्रदेश पर भी विचार करें। यह बीच का एक बड़ा प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी वह कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे है। हमारे यहां इरिगेशन फैसिलीटीज़ बहुत कम हैं—केवल ७.३ हैं—इसलिए उत्पादन भी बहुत कम होता है। वहां पर खेती मानसून पर ही निर्भर करती है। सिंचाई के साधन नहीं हैं। जहां हमको डिसपैरिटी को हटाना है, आर्थिक असमानता को दूर करना है और विकास करना है, वहां हम को मध्य प्रदेश जैसे राज्य की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। वहां काफी आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं, काफी फारेस्ट हैं। सड़क आदि के साधन नहीं हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वहां ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, जहां रेल का जाना तो दूर मोटर गाड़ियां वगैराह भी नहीं जा सकती हैं। वहां पर सड़कें नहीं हैं। इस तरह के वहां कई बड़े-बड़े हिस्से हैं। उनके विकास की अगर उचित व्यवस्था नहीं की गई तो दूसरे प्रदेश बहुत आगे बढ़ जायेंगे, दूसरे राज्य बहुत आगे बढ़ जायेंगे और हमारा बहुत बड़ा प्रदेश जो अभी भी पीछे है वह और भी पीछे रह जाएगा। इस वास्ते उसकी ओर विशेष ध्यान आपका जाना चाहिये।

हमें देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, असमानता को दूर करना है। यहां पर एतराज किया गया है कि थोड़े से बिजिनस हाउसिस जो हैं वे बड़े मालदार होते जा रहे हैं। जबकि हमने मिक्स्ड इकोनोमी को स्वीकार किया है तो हम को एक दम उनको समाप्त नहीं करना है। हमने सिद्धान्त मंजूर किया है कि प्राइवेट और पब्लिक और कोओप्रेटिव सैक्टर, इन तीनों को साथ साथ लेकर हम चलना चाहते हैं। इन तीनों के सहारे हम देश का विकास करना चाहते हैं। अगर उनकी अभी कमर तोड़ दी जाए तो मैं समझता हूं कि जो हमारी आशायें हैं, वे पूरी नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर भी देश को इंडस्ट्रियलाइज़ करने में अपना योगदान करें। लेकिन जहां उसका विकास हो उससे देश का किसी सूरत में अहित नहीं चाहिये। टैक्सों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उनसे वसूल किया जाना चाहिये लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिये जिससे इनिसियेटिव और कैपिटल फार्मेशन में बाधा उत्पन्न हो। ऐसा कोई कदम उठाना देश के लिए बहुत ही घातक होगा।

[श्री राधेलाल व्यास]

अब जो और कुछ आवश्यक बातें हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। लोग अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन बिता सकें, इसके लिए कुछ बातें प्लान में निर्धारित की गई हैं। उन कुछ बातों में से एक बात यह भी है कि पीने का पानी लोगों को सुलभ हो। आज कई गांव ऐसे हैं जहां पर कि पीने के पानी के साधन बिल्कुल नहीं हैं। इस के लिये बहुत थोड़ा रुपया रक्खा गया है। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह जरूर वादा किया गया है कि हम पानी पीने के साधन हर एक गांव में बढ़ायेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां मीलों तक पानी नहीं मिलता है, वहां कुएं नहीं हैं और इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। अगर सब गांवों में नहीं तो कम से कम ७५ फी सदी गांवों में पानी मुहैया करना चाहिये और इस के लिये काफी खर्च की व्यवस्था करनी होगी।

इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है। इंडस्ट्रीज के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। यह जरूर है कि हेवी एलेक्ट्रिकल्स और स्टील प्लान्ट यह दो बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे यहां कायम की गई हैं, लेकिन इनसे जनसाधारण को कोई लाभ नहीं मिल सकता है जब तक कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज का फैलाव नहीं होगा। हम देखते हैं कि हमारे यहां शिकायत है नान फेरस मेटल वगैरह का जो कोटा होना चाहिये मध्य प्रदेश के लिये वह मध्य प्रदेश को नहीं मिलता है। नई इंडस्ट्रीज के लाइसेन्स के लिये जो एप्लिकेशन्स दी जाती हैं उन में काफी टाइम लग जाता है। उन के लिये जितनी इजाजत मिलनी चाहिये वह नहीं है। इस मामले में मध्य प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है और इस बात की उस को खास तौर से शिकायत है। मैं समझता हूं कि इस ओर भी हमारे माननीय मंत्रियों को और शासन को ध्यान देना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि कल हमारे वित्त मंत्री जी ने राज्य सभा में यह घोषणा की कि कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये एक ही तरीका है कि कंज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज ज्यादा से ज्यादा बनें। यह एक स्वागत योग्य बात है। लेकिन साथ ही हम कुछ वस्तुयें बाहर से मंगाते हैं। देखना यह होगा कि जो वस्तुएं बाहर से मंगाते हैं और जिन के लिये हम फारेन एक्स्चेन्ज की व्यवस्था करते हैं, उन के लिये जो कीमत हम अदा करते हैं और जो मूल्य कंज्यूमर्स से लिये जाते हैं उन में बड़ा अन्तर है। जैसे स्टेनलेस स्टील को ले लीजिये या किसी और चीज को ले लीजिये, जो भी चीज बाहर से मंगाई जाती है वह कंज्यूमर्स को बहुत महंगी मिलती है। जिस इंडस्ट्री को आप लोभ देते हैं उत्पादन के लिये उन से ऐसा ऐग्रीमेंट होना चाहिये, जिनकी इम्पोर्ट लाइसेन्स देते हैं उन से एग्रीमेंट होना चाहिये कि वह निश्चित मुनाफे के अलावा और मुनाफा नहीं लेंगे। यह व्यवस्था की गई तो मुझे विश्वास है कि कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी।

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, बजट के मुताल्लिक मेरे जो विचार थे, इस हाउस के अन्दर कुछ स्पीचेज सुन कर उन में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। हमारे अपने साइड के मेम्बर साहबान ने कहा है कि इस बजट को कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। इस से मैं सहमत हूं कि विशाल भारत का यह बजट एक विशाल समुद्र है। किसी शायर ने किसी और मौके के लिये कहा होगा लेकिन यह शेर इस जगह मौजूं आता है :

"एक आंख से क्या बुलबुला कुल बाहर को देखे,
साहिल को, मझधार को या लहर को देखे।"

एक मेम्बर ने यहां तक कह दिया कि कोई तरक्की किसी पहलू में हुई ही नहीं। इत्तफाक से हमारे पास कुछ फिगर्स थे पंजाब के बारे में कि हर सूबे में, हर तरफ तरक्की हुई है। जहां नहीं हुई वह भी

में बतलाऊंगा। पंजाब में ३६ हजार किलोवाट से ४$^1/_4$ लाख किलोवाट बिजली हो गई है और २५ हजार किलोवाट और पैदा करने का इन्तजाम है। पहले सिर्फ ५० गांवों में बिजली थी अब ३११ गांवों में बिजली और ४$^1/_4$ हजार गांवों में और बिजली का इन्जाम इस फाइव इअर प्लैन में किया गया है। प्रोडक्शन के बारे में यह है कि जहां ३२ लाख टन अनाज पैदा होता था पंजाब में, और पंजाब अनाज के सिलसिले में एक घाटे का सूबा था, वहां ६८$^1/_2$ लाख टन अनाज पैदा हुआ है, और यह फक्र की बात है कि १२ या १३ लाख टन अनाज दूसरे सूबों में भेजा गया है। एक बात की तरक्की यह भी हुई है कि लोगों में कांफिडेन्स पैदा हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने इतना कांफिडेंस पैदा न किया होता तो इतनी तरक्की नहीं होती। जहां तक मुझे वार्डर के जिले अमृतसर का पता है जो कि मेरी कांस्टिट्एन्सी भी है, एक वक्त ऐसा था कि लोगों में जरा भी इत्मीनान नहीं था। लेकिन हमारे जो किसान हैं वह अब वार्डर के सिरे तक अपने कन्धों पर बन्दूक रखते हैं और हल जोतते हैं। यानी पाकिस्तान वालों की जमीन की हद्द उस के साथ मिलती है। हमारे किसान तो हद्द पर जा कर काश्त करते हैं लेकिन दूसरी तरफ के लोग वहां पर कोई काश्त करते हैं इसका पता भी नहीं लगता है। उन्होंने दूर तक जमीन को खाली छोड़ा हुआ है। यह तो कांफिडेन्स की बात है।

हमारे काश्मीर साइड के भाई ने कहा कि हमारा इलाका पसमांदा है। अमृतसर तो काश्मीर के साथ लगता है, लेकिन उसे पसमांदा नहीं कहा जा सकता। मगर मुझे यह डर जरूर है कि कहीं वह पसमांदा हो न जाय।

कुछ माननीय सदस्य : पसमांदा के क्या माने हैं?

श्री गु० सिं० मुसाफिर : इस के माने हैं बैकवर्ड इलाका, पिछड़ा हुआ इलाका। इस सिलसिले में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे डर है कि जो हमारा बना बनाया खेल है पंजाब का कहीं बिगड़ न जाय। पंजाब के लोग किसान हैं, तब भी अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वे ऐसे ढंग से काम चलाते हैं जिस का ठिकाना नही है। वहां पर कोई बड़ जमीदार नहीं हैं। वहां न बड़े बड़े लैंडलार्ड हैं और न पंजाब में कोई बड़ी हेवी इंडस्ट्री है। वहां इंडस्ट्रीज हैं तो काटज इंडस्ट्रीज हैं और अगर वहां किसान हैं तो मालिक किसान हैं जिसके पास थोड़ी सी जमीन होती है और वह खुद ही उस पर काश्त करता है, मिट्टी के साथ मिट्टी होता है तब भी उसने कुछ उसपर नामाफिक हालात में भी प्रोडक्शन बढ़ाया है। मेरा मकसद यह है कि अमृतसर मेरी कांस्टिटुएंसी है, मुझे वहां का इल्म है। वहां ज्यादातर काटेज इंडस्ट्रीज हैं। सारे हिन्दुस्तान में जितनी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन में से ९० फीसदी अमृतसर में हैं। कुल हिन्दुस्तान में कोई २६६८ यानी २७०० के करीब गर्म कपड़े के लूम्ज हैं उनमें से ९०० स्माल स्केल इंडस्ट्री में हैं और उनके १७६८ यानी १८०० के करीब यूनिट्स हैं। इन ९०० इंडस्ट्रीज में २५० कारखाने ऐसे हैं जिन में चार चार लूम्स हैं और २०० के करीब कारखाने ऐसे हैं जिन में एक एक लूम है। इन ४ लूम्स पर भी और १ लूम पर भी पहले कोई एकसाइज ड्यूटी नहीं थी। उस के बाद ही कम्पाउंडेबल लेवी के लिहाज से ३ या ४ परसेंन्ट की एकसाइज ड्यूटी लग गई। उसका यह नतीजा निकला जैसा कि पिछले बजट के वक्त पर भी मैं ने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाई थी और उन्होंने बड़ी मेहरबानी भी की, कि ३ या ४ परसेन्ट से भी, करीब आधे कारखाने अमृतसर में बन्द हो गये थे। अब वह ३ या ४ परसेन्ट से बढ़ कर १० परसेन्ट हो गई है। मेरा मतलब यह है कि जो बड़े कारखाने हैं उनके ऊपर तो वह ११$^1/_4$ परसेन्ट से १० परसेन्ट आ गई है लेकिन फ्लैट एक्साइज ड्यूटी करने से ३ या ४ परसेट वालों की बढ़ कर १० परसेन्ट हो गई। यहां तक कि जो एक एक लूम वाले हैं वह भी एकसाइज ड्यूटी की जद से नहीं बच सके। तो अमली तौर पर इस वक्त स्माल स्केल इंडस्ट्री के कारखाने हैं वह बंद पड़े हैं।

[श्री गु० सिं० मुसाफिर]

श्री मनुभाई शाह ने ठीक कहा था पालियामेंट में और मैं उनसे इत्तिफाक करता हूं कि जो लोग स्ट्राइक की धमकी देते हैं उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। आज हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है तो हमको उसे एक दिन के लिए भी काम नहीं रोकना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। इस बात से मुझे इत्तिफाक है। मगर मेरा कहना है कि उनकी मजबूरी पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री मुरारजी देसाई ने एक तकरीर में कहा था कि जो यूनिट चार चार की थी उन्होंने भी एक्साइज ड्यूटी से बचने के लिए अपनी यूनिट को कम करने की कोशिश की है। तो इससे यह समझ लेना चाहिए कि वह चार की यूनिट से भी अपना काम नहीं चला सकते इसीलिये वे मजबूर हैं कि अपनी यूनिट को छोटा करके एक्साइज ड्यूटी से बचें। मगर इनमें से सौ सवा सौ के करीब एक एक लूम के कारखाने हैं, उनको परमिट ही एक एक का है। जिस रोज से यहां बजट पेश हुआ है उनका माल जो फिनिशिंग के लिए गया हुआ था वह भी पड़ा है, वापस नहीं मिल रहा है। इसलिए अमली तौर पर जो छोटे कारखाने वाले हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है। बड़े कारखानों में और छोटे कारखानों में फर्क को कायम रखना चाहिए। लेकिन एक्साइज ड्यूटी के सिलसिले में उनका फर्क नहीं रखा गया। दूसरी जगह रखा गया है।

आइल मिल, जो बड़े बड़े एक्सपैलर हैं, उन पर ड्यूटी है मगर जो स्माल स्केल के कोल्हू और छोट एक्सपैलर हैं उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है। और अगर है तो बहुत कम है। इसलिये वह बड़ी मिलों का मुकाबला कर सकते हैं। वहां उस फर्क को कायम रखा गया है लेकिन खास करके गर्म कपड़े के स्माल स्केल के कारखानों में उस फर्क को नहीं रखा गया है। इस लिए यह चीज ज्यादा नुकसानदेह हो रहे है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह धागे के सिलसिले में है। श्री मनुभाई शाह ने इस बात को बड़े ध्यान से सुना है और मुझे उम्मीद है कि वह इसका कुछ इलाज करेंगे। मगर यह बात स्पष्ट है कि सारे हिन्दुस्तान में २५—३० के करीब मानापालिस्ट हैं जो स्पिनिंग करते हैं, यानी ६ करोड़ का लाइसेंस सरकार उन्हें देती है। जो यार्न उनको घर में ८ रुपये पाउंड पड़ता है उसको वह १६ रुपये पाउंड बेचते हैं। तो सीधी बात है कि इतने बड़े कारखानों से १६ रुपये पाउंड ले कर छोटे लोग कैसे काम कर सकते हैं।

पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी से एक लाख ७० हजार पाउंड यार्न सस्ते भाव पर यानी ११—१२ रुपये पाउंड पर देने की बात कही थी। ७० हजार पाउंड तो उनको पहले भी मिलता था। लेकिन आज मुझे इस हाउस में यह कहना पड़ता है कि उनको अभी तक सिर्फ परमिट ही मिला है लेकिन यार्न का एक धागा तक नहीं मिला। इसलिए वे लोग अपने कारखाने बन्द करने के लिए मजबूर हैं और १५ हजार आदमी बेकार पड़े हैं और एक करोड़ की मैशीनरी आइ-डिल पड़ी है। तो मेरा कहना है कि इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए।

टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट आए डेढ़ साल हो गया। जब से टैरिफ कमीशन बैठी है उस वक्त से उनको ११—१२ रुपये पाउंड में कहीं से कुछ धागा मिल जाता था वह भी मिलना बन्द हो गया।

इसी तरह से हमारे लुधियाने में साइकिल इंडस्ट्री है। वह फर्म स्टील ट्यूब और स्टील पाइप बनाती है। लुधियाने की साइकिल पार्ट्स की इंडस्ट्री बड़ी मशहूर है। उन पर भी जो ड्यूटी लग गई है उससे उनको बड़ी मुश्किल हो गई है। उनकी तरफ से बहुत से डेपुटेशन और मैमोरेंडा आए हैं।

इस वजह से मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ध्यान पंजाब की तरफ देना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, गो कि पंजाब में तरक्की हो रही है और सरकार हिन्द ने काफी मदद की है, लेकिन जो यह काम करते हैं उनको बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है।

मैं अब शेडी यार्न के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं जिनका कुछ थोड़ा सा इशारा पंडित अमर नाथ जी ने अपनी तकरीर में किया था। सरकार हिन्द ने २५ लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट को दिया था शेडी यार्न हैंडलूम की तरक्की के लिए। और जो बहुत से शरणार्थी लोग आए थे अमृतसर में उनको ट्रेनिंग दी गयी इस काम के लिए और उन्होंने इस काम को खड़ा किया और बड़ी मेहनत से काम किया। और मैं यह भी बता दूं कि शेडी यार्न के हैंडलूम का भी ज्यादातर काम, यानी ९० पर सेंट के करीब काम अमृतसर में होता है। इसके बारे में एक स्टेज पर जाकर जो ड्यूटी लगा दी गयी है उसकी वजह से उसकी कोई चार गुनी कीमत बढ़ जाती है। यही हालत काश्मीर की है जहां सारा काम काटेज इंडस्ट्री में होता है। वहां वह रफल पर काम करतेहैं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी तरफ देखते तो नहीं मगर कान भी नहीं देते कि घंटी तीन बार बज चुकी है।

श्री गु० सि० मुसाफिर : माफ करना सचमुच मैंने सुना नहीं। बस एक मिनट में मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं।

पंजाब में पहले ही काफी तकलीफें हैं। पहले वहां हिन्दी मूवमेंट चलता रहा, फिर उसके बाद अकाली आन्दोलन चलता रहा। मैं यह बात फख्र के साथ कहता हूं कि हमारी तरक्की हुई है। मैं उन मेम्बर साहिबान से इत्तिफाक नहीं करता जो कहते हैं कि हमारी तरक्की नहीं हुई। लेकिन उनकी एक बात से मैं इत्तिफाक करता हूं कि हमारी माकूस तरक्की हुई है, हमारे यहां प्राविंशियलिज्म बढ़ गया है, कम्युनलिज्म बढ़ गया है और कास्टीज्म बढ़ गया है यह हर तरफ बढ़ा है।

मरीजे इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो यह चीज तो हर तरफ बढ़ी है। पंजाब में हालात खराब रहे। और पंजाब सरकार को काफी कशमकश में मुब्तिला होना पड़ा। यह तहरीक इतनी बढ़ी कि २६ लाख रुपया तो आन्दोलन करने वालों को रोटियां खिलाने पर खर्च हो गया। लेकिन फिर भी आसाम जैसा प्राविंशियलिज्म वहां नहीं हुआ और जबलपुर जैसा कम्युनलिज्म वहां नहीं हुआ। फिर भी पंजाब में शान्ति रही है। तो अब लोगों को बेकार करके वहां अशान्ति न पैदा की जाए यही मेरी तजवीज है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** आपने बजट पर चर्चा आरम्भ करने से पहले आपने सुझाव दिया था कि यह अधिक उपयोगी होगा यदि आयकर प्रस्तावों पर अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक विचार किया जाये।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : एक औचित्य प्रश्न है। माननीय वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बजट का उत्तर दे दिया है जो कि इस सभा की परम्परा के प्रतिकूल है। पहले उन्हें इस सभा में उत्तर देना चाहिये था। वित्त मंत्री ने जो रवैया अपनाया है वह ठीक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य महोदय कुछ दिनों से अनुपस्थित हैं इसलिये उन्हें यह मालूम नहीं है कि यह प्रश्न यहां उठाया गया था और यह निश्चित हो गया है कि इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : जब मुझ से बोलने के लिये कहा जाता है तभी मैं उत्तर दे देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन एक बात यह है कि यदि करों में कोई छूट देने की घोषणा अथवा अपने भाषण में कोई परिवर्तन करने की घोषणा वित्त मंत्री को करनी है तो उसके बारे में सब से पहले इस सभा में विचार व्यक्त करना चाहिये। इनके अतिरिक्त अन्य बातें यहां कही जायें अथवा वहां कोई अन्तर नहीं पड़ता।

†**श्री त्यागी (देहरादून)** : इसके अलावा अच्छी प्रथा तो यह है कि बजट का उत्तर पहले इस सभा में दिया जाया करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यक्रम बताते समय कभी कभी यह संभव नहीं होता। हमें चर्चा के लिये अधिक समय की आवश्यकता थी और वहां उन्हें उत्तर कल ही देना था अतः ऐसा हुआ। सामान्यतः हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि यह आपत्ति उठे ही नहीं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने कोई भूल नहीं की है और न भविष्य में करने का ही इरादा है। वहां करों में छूट देने के बारे में मैंने कोई घोषणा नहीं की है और न मैं यहां कोई इस प्रकार की घोषणा करने वाला हूं। कुछ और भी ऐसे मामले हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

चर्चा के दौरान में बहुत सी बातें कही गई हैं जिनमें से सभी का उत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों ने बजट की जो आलोचना की है मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि इन आलोचनाओं से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि कर प्रस्तावों के बारे में सभी की राय यह है कि ये ठीक हैं और उनका लगाना औचित्यपूर्ण है। और सभी ने इस बजट का स्वागत किया है।

चर्चा के दौरान में कुछ लोगों ने मुझ पर अप्रत्यक्षतः आरोप लगाते हुए यह कहा है कि कांग्रेस की समाजवादी नीति में मेरा विश्वास नहीं है। अच्छा होता कि वे लोग ये आरोप मुझ पर प्रत्यक्षतः लगाते। मेरी आदत यह है कि जो कुछ मैं करता हूं उसके बारे में कहता नहीं क्योंकि कहने से तो उसका महत्व ही कम हो जाता है।

यह बजट जो मैंने यहां प्रस्तुत किया है वह मेरा निजी बजट तो है नहीं। यह तो सरकार का है और सरकार ने ही इसे बनाया है। और कांग्रेस द्वारा इसकी पूर्ति की जानी है क्योंकि कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करने के कारण सरकार बनाई है। कांग्रेस ने नीति बनाई है। वह भी इस वर्ष नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से। कांग्रेस ने समाजवाद के बारे में १९३१ में करांची में अधिवेशन में अपनी नीति निर्धारित कर दी थी और तब से वह उससे कभी विमुख नहीं हुई है। स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे लिये यह आवश्यक हो गया कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। इसमें कुछ समय लगा क्योंकि कांग्रेस उस बात से पीछे नहीं हटना चाहती थी जोकि उसने कहा है। कांग्रेस का यह सिद्धान्त रहा है कि जो कुछ यह कहती है वह करती भी है। लेकिन कहती कम है। हो सकता है कि व्यक्तिगत आधार पर लोग भले ही भूल करें लेकिन कांग्रेस एक संस्था के नाते कोई भूल नहीं करती एवं जो कुछ कहती है उससे पीछे नहीं हटती। कुछ कठिनाइयों के कारण कार्यक्रमों में विलम्ब का होना सम्भव है, परन्तु सरकार ने उसके प्रति कभी उपेक्षा नहीं दिखाई है। ऐसी स्थिति में जब कि उसे अपनी नीति में कोई परिवर्तन करना होता है तो वह साहसपूर्वक कहती है कि इस नीति में परिवर्तन करना जरूरी है अतः हम परिवर्तन कर रहे हैं। कांग्रेस को ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि वह जो भी काम करती है वह जाहिरा तौर पर करती है। वह जो भी काम करती है

---

†मूल अंग्रेजी में

सच्चाई और ईमानदारी से तथा ठीक ढंग से करती है। और यही कारण है कि मैं कांग्रेस में विश्वास रखता हूं उसमें मेरी निष्ठा है। महात्मा गांधी के 'सर्वोदय' में भी मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति चाहना से दूर और डर से मुक्त हो। और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो जाता। यही कारण है कि कांग्रेस ने समाजवाद का सिद्धान्त अपनाया है। कांग्रेस सर्वोदय भी चाहती है किन्तु वह लक्ष्य इतने थोड़े समय में प्राप्त नहीं हो सकता। सरकार का समाजवाद उस दिशा में प्रथम कदम है। लेकिन इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के विचारों का समाजवाद साम्यवादी समाजवाद से भिन्न है। लेकिन मेरा उन से इस बारे में कोई विवाद नहीं है। किन्तु इतना अवश्य है कि जो कुछ वे करते हैं उसमें घृणा एवं हिंसा है जो मैं पसन्द नहीं करता।

इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि यह बजट समाजवादी नहीं है उन्हें ऐसा कहने से पहले सोचना चाहिये। यह बजट ऐसा है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिये। यह बजट ठीक दिशा में ले जाने वाला है। ठीक दिशा से मेरा अभिप्राय यह है कि उन लोगों पर ही कर लगता है जो कर देने के लिये सक्षम हैं। और उनसे ही अधिक कर लेता है जो अधिक से अधिक कर दे सकते हैं।

जहां तक कि अप्रत्यक्ष करों की बात है यह कल्पना गलत है कि समाजवादी देशों में कोई अप्रत्यक्ष कर नहीं है। सोवियत रूस में भी करों का भार निरंतर बढ़ रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। जब कोई मेरे विरुद्ध बोलता है, तो मैं नाराज़ नहीं होता। इसलिये उनको मेरी बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिये। लेकिन लोग सही बात सुनना नहीं चाहते। उनको डर लगता है कि वास्तविकता जान लेने पर उनको अपने तौर तरीके बदल देने पड़ेंगे। और वे अपने तौर तरीके बदलना नहीं चाहते। यह उनका अपना दोष है। खैर, मैं उसके बारे में झगड़ा नहीं करना चाहता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इसीलिये आपके दल के लोग दूसरे दलों में चले जाते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : उनका चले जाना हमारे दल के लिये अच्छा ही रहता है। इस लिये कि मेरे दल को उनसे छुटकारा मिल जाता है। उससे दल को कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि हमारे दल में काफी प्राणवंता है। कांग्रेस अपने पथ पर इसीलिये अविचल बनी रहेगी। और दृढ़ निश्चय के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ती रहेगी।

मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। उनसे कई नये तथ्य प्रकट होंगे। सोवियत संघ में करों का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा है। १९२६ से १९३६ तक करों का भार काफी बढ़ता गया है। हमारे देश की परिस्थिति से सोवियत के इसी काल की तुलना की जा सकती है। इन दस वर्षों के काल में प्रत्येक परिवार ने अपनी आय का ६० प्रतिशत करों के रूप में राज्य को दिया था। १९४८ में वह लगभग ६९ प्रतिशत तक पहुंच गया था। बाद में कुछ कम हुआ, लेकिन १९५३ में फिर ५७ प्रतिशत हो गया था। इससे पता चलता है कि कम्युनिस्टों की कथनी और करनी मे कितना अन्तर है।

मैं यह आंकड़े हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित हाल्समैन की पुस्तिका **सोवियत कराधान** से उद्धृत कर रहा हूं। मैंने अपनी रूस यात्रा के समय भी वहां यही देखा था।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : लेकिन माननीय मंत्री ने वहां कितने बेरोजगार लोग देखे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य यह प्रश्न उस सोवियत संघ के बारे में पूछ रहे हैं, जो ४४ वर्षों से एक तानाशाही के नीचे रह चुका था। इतने पर भी वहां अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके रहन-सहन की दशा हमारे देश के कुछ लोगों से अच्छी नहीं है। यदि तुलना करनी ही हो तो इस देश के चालीस वर्ष के विकास के बाद के भारत से सोवियत संघ की तुलना की जानी चाहिये। गलत ढंग से तुलना करना तो अनुचित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब श्री अ० क० गोपालन ने हमारी सरकार की पूरी नीति की निन्दा के साथ अपना भाषण शुरू किया। लेकिन मैं उनके इस साहस की दाद देता हूं कि उन्होंने खुले आम कह दिया कि इस देश में कोई भी कांग्रेस पर यह विश्वास नहीं करता कि वह समाजवाद ला सकेगी। लेकिन साधारण जनता ने पिछले आम चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया है और कम्युनिस्ट दल को ठुकरा दिया है। (**अन्तर्बाधायें**)

यदि यह नहीं होता तो आज हम यहां नहीं होते। मेरे राज्य में कांग्रेस को ५२ प्रतिशत मत विधान सभा के लिये मिले हैं।

संसद् के लिये हमें ५१ प्रतिशत मत मिले हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि कांग्रेस बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मेरा भी एक कम्युनिस्ट समर्थित उम्मीदवार ने विरोध किया था। लेकिन मुझे उससे लगभग एक लाख वोट अधिक मिले। फिर भी वे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करने की धृष्टता करते हैं।

श्री अ० क० गोपालन ने कुछ आंकड़े भी पेश किये हैं। श्री मसानी ने आंकड़ों की तुलना ओठों पर लगाई जाने वाली लिपस्टिक से की है। लेकिन श्री गोपालन के आंकड़े वास्तविकता को छिपाने भर के साधन नहीं हैं, उनका इशारा कुछ ऐसी चीजों की ओर भी है जिसका कहीं अस्तित्व नहीं है।

मैं खुले आम कहता हूं कि मुझे और मेरे दल को अपनी कारगुजारी, अपने रिकार्ड पर गर्व है। हमें जनता पर भरोसा है। हम अपनी गलतियां स्वयं स्वीकार करते चलते हैं। हम जानते हैं कि पिछले दस-बारह वर्ष के काम और अपनी सफलताओं के बाद भी हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिये काफी लम्बा रास्ता तय करना है। हमें मेहनतकश जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाना है, सभी को समान अवसर जुटाना है, असमानतायें मिटानी हैं और राज्यों की आर्थिक सक्रियता तथा जनता की पहलकदमी बढ़ाते हुए समाजवादी समाज तक पहुंचना है। हम अपनी गति से संतोष नहीं है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि हमने ठोस सफलतायें प्राप्त नहीं की हैं, या हम पूरे संकल्प के साथ अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिये तत्पर नहीं हैं।

हमसे कहा जाता है कि पहली दो योजनाओं के काल में वास्तविक राष्ट्रीय आय में केवल ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति आय केवल १.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ी है। शताब्दियों की दासता और जड़ता के बाद, इतनी प्रगति भी नगण्य तो नहीं मानी जा सकती। और इन आंकड़ों से पूरी बात पता भी नहीं चलती। इनसे यह पता नहीं चलता कि पिछले दस वर्षों में हमने जनता के दृष्टिकोण में किस तरह क्रमशः परिवर्तन किया है, अर्थव्यवस्था को एक नयी गतिशीलता दी है और रोगों को पराजित करके जनता के स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि की है। हमारी जनता के जीवन को हर क्षेत्र में सुधार के लक्षण स्पष्ट दिख रहे हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है और सब से पहले निचले वर्गों में ही सुधार शुरू हुआ है।

देश में विलास-सामग्री, जैसे मोटर कारों की वृद्धि को ले कर काफी कुछ कहा गया है। लेकिन साथ ही, साइकिलों, सिलाई की मशीनों, खाद्य, वस्त्र और चीनी का उत्पादन भी बहुत काफी बढ़ा है। प्रथम योजना के आरम्भ के समय हम केवल एक लाख साइकिलें बनाते थे और उसमें दस

†मूल अंग्रेजी में

गुनी प्रगति हो गई है। खाद्यान्न और वस्त्रों के उत्पादन में दो योजनाओं के काल में लगभग ५० प्रतिशत और चीनी के उत्पादन मे १६८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । क्या इससे साधारण जनता के रहन-सहन के स्तर में सुधार नहीं हुआ है ? फिर भी श्री गोपालन कहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में १९४७ और १९५८ के बीच ५० प्रतिशत वृद्धि होने पर भी मजदूरों की वास्तविक मजूरी में केवल २७ प्रतिशत वृद्धि हो पाई है । मैं तो समझता हूं कि ग्यारह वर्षों में २७ प्रतिशत वृद्धि होना कोई मामूली बात नहीं है ।

और यह विचार बड़ा भ्रामक है कि यदि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के समान ही वास्तविक मजूरी में वृद्धि न हो तो मजदूरों का शोषण हो रहा है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैंने केवल इतना तो नहीं कहा था। मैंने यह भी कहा था कि पहले यदि मजदूर एक रुपये के मूल्य की वस्तु का निर्माण करते थे, तो अब २ रुपये ३९ नये पैसे की वस्तु का निर्माण करते हैं, फिर भी उनको इस वृद्धि का पूरा अंश नहीं मिलता ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : थोड़ा धैर्य रखिये । मैं उस पर आ रहा हूं । प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि में, श्रम के साथ-साथ उद्योग द्वारा प्रयुक्त अधिक पूंजी का भी हाथ है । बुनियादी और भारी उद्योगों के लिये अधिक पूंजी दरकार होती है । पिछले दस वर्षों मे भारतीय उद्योगं में बड़ी विविधता आई है और प्रति मजदूर निर्धारित पूंजी विनियोजना १९५० में १७५८ रुपये से बढ़ कर १९५८ में ३९४४ रुपये हो गया है । उत्पादन की वृद्धि प्रति इकाई पूंजी की वृद्धि से भी सम्बंधित है और उसी अनुपात में प्रति इकाई श्रम की मात्रा घट जाती है । इसलिये यह आशा तो नहीं करनी चाहिये कि उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में वास्तविक मजूरी की वृद्धि भी होगी । सोवियत संघ में भी ऐसा नहीं हुआ है । श्री गोपालन उसका विश्लषण कर देखें ।

श्री गोपालन ने रक्षित बैंक द्वारा जुटाये गये आंकड़े पेश करते हुए यह भी कहा था कि १९५५ से १९५९ तक के बीच समवायों का शुद्ध लाभ ४१ प्रतिशत बढ़ा है । लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बीच समवायों का शुद्ध मूल्य भी ३१ प्रतिशत बढ़ा है और उनकी निर्धारित आस्तियां के ७१ प्रतिशत बढ़ी हैं । इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया । इसी तरह उन्होंने बताया कि १९५५ और १९५९ के बीच चाय बागान का लाभ १४९ प्रतिशत बढ़ गया है । लेकिन यदि श्री गोपालन बारीकी से देखें तो उनको पता चलेगा कि हर वर्ष लाभ की राशि उतनी ही नहीं रहती । १९५६ और १९५९ लाभ की दृष्टि से अच्छे वर्ष थे । फिर भी १९५६ के मुकाबले १९५९ में लाभ कम रहा था ।

इस प्रकार श्री गोपालन के आंकड़े पूरी वास्तविकता को ले कर नहीं चलते । वह कुछ तथ्यों को छिपा कर एक ग़लत तसवीर पेश करना चाहते हैं । समवायों द्वारा दिये जाने वाले लाभांशों के बारे में भी उन्होंने इसी तरह एक ग़लत तसवीर पेश की है । उन्होंने लाभांशों का सम्बन्ध केवल प्रदत्त पूंजी से जोड़ा है । जब कि सभी जानते हैं कि पुराने समवायों में प्रदत्त पूंजी का मूल्यांकन काफी निचले मूल्यों पर किया जाता है । अधिकांश समवायों में प्रदत्त पूंजी कुल पूंजी का बहुत छोटा सा अंश होती है । इसलिये प्रदत्त पूंजी के अनुपात में लाभ का हिसाब लगाने से यह पता नहीं चल सकता कि लाभ उचित है या अनुचित । रक्षित बैंक द्वारा किये गये जिस अध्ययन का श्री गोपालन ने उल्लेख किया है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि १००१ समवायों ने अपनी आस्तियों पर ५-६ प्रतिशत लाभांश दिया है । लेकिन श्री गोपालन ने जानबूझ कर उसका उल्लेख नहीं किया ।

इसका मतलब यह भी नहीं कि सभी लाभ सर्वथा उचित हैं या यह कि कुछ समवाय अत्यधिक लाभ नहीं कर रहे हैं । हमने अत्यधिक लाभ को मूल्य-नियंत्रण या उत्पादन शुल्कों द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

कम करने की कोशिश की जाती है । कुछ क्षेत्रों में हम ने राज्य व्यापार का भी सहारा लिया है। यदि समवायों की दशा बहुत अच्छी हो, तो हम उन पर अधिक कर भी लगा सकते हैं। इन्हीं साधनों द्वारा हम अत्यधिक लाभ की रोकथाम करते हैं, और हमने की भी है ।

लेकिन मैं यह नहीं मानता कि सभी लाभ अनुचित होते हैं। हम जहां सरकारी क्षेत्र के विकास को महत्व देते हैं, वहीं गैर-सरकारी क्षेत्र को भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योग देने का अवसर देते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र उचित लाभ की प्रेरणा के बिना काम नहीं कर सकता। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड से देखा जाये तो हमारे देश के गैर-सरकारी क्षेत्र ने बेतरह लाभ नहीं कमाया है। इंगलैण्ड के मुकाबले तो वह बहुत कम है। हमें गैर-सरकारी क्षेत्र को उचित लाभ का अवसर तो देना ही चाहिये। तभी वह देश के विकास में ईमानदारी से योग दे सकेगा।

१९४८ में प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प स्वीकार करते समय ही हम ने महसूस कर लिया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को देश के विकास में योग देने का अवसर दे कर हम सम्पदा और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण का खतरा उठा रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र लाभ की प्रेरणा के बिना चल नहीं सकता। और लाभ का मतलब होता है एक हद तक सम्पदा का केन्द्रीकरण। यही सोच कर हमने सरकारी क्षेत्र आरम्भ किया था। इसीलिये हमने औद्योगिक प्रगति और अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के लिये इतने कदम उठाये हैं।

हम बुनियादी उद्योगों—इस्पात कारखानों, उर्वरक कारखानों, भारी मशीनी उद्योग, और तैल-परिष्करण के क्षेत्रों में काफी प्रगति कर रहे हैं। और सरकारी क्षेत्र की प्रगति के साथ साथ सम्पदा और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण भी दिन दिन कम होता जायेगा। दूसरी ओर यदि हम गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ ज्यादती करने लगें तो उससे देश की हानि होगी।

मैंने अपने आय-व्ययक भाषण में कहा था कि अब समय आ गया है कि गैर-सरकारी उद्योग अपनी सामान्य पूंजी का स्वामित्व अधिकाधिक लोगों में फैलायें। इस प्रकार जनता को अपना रहन-सहन का स्तर उठाने का अधिक अवसर मिलेगा। समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण का हमारा यही दृष्टिकोण, यही मार्ग है। मैं जानता हूं कि कम्युनिस्ट दल और उसके वक्ताओं का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। वे गैर-सरकारी क्षेत्र का एकदम गला घोंट देना चाहते हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : केवल बुनियादी उद्योगों के क्षेत्र में।

†श्री मोरारजी देसाई : मुझे यह कहते थोड़ी भी हिचक नहीं कि सरकार का दृष्टिकोण श्री अ० क० गोपालन के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। और देश की जनता ने चुनावों में हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया है। इसलिये अगले चुनावों तक यही नीति रहेगी।

जो लोग आय-व्ययक के समाजवादी होने या न होने की बातें करते हैं। वे बड़ी सरलता से प्रत्यक्ष करों को समाजवाद और अप्रत्यक्ष करों को समाजवाद और योजनाकरण-विरोधी बता देते हैं। इसीलिये मैंने अपने आय-व्ययक भाषण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में इतना सब विस्तार बताया था। कुछ लोग तो हठधर्मी से अड़े रहना चाहते हैं। उनको कोई समझा ही नहीं सकता कि अप्रत्यक्ष कराधान भी उचित ढंग प्रयुक्त होने पर प्रगतिशील हो सकता है। कम्युनिस्ट दल के सदस्य बड़ी आसानी से यह बात नजरन्दाज कर जाते हैं कि सोवियत संघ ने समाजवादी

---

†मूल अंग्रेजी में

देश की अर्थ-व्यवस्था में माल के लेनदेन पर लगने वाले कर जैसे अप्रत्यक्ष की बड़ी अहमियत होती है ।

वाद-विवाद के दौरान ही श्री अ० चं० गुह और श्री मुरारका ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था । मैं यह भी बता दूं कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के बावजूद कुल अप्रत्यक्ष कराधान कुल राष्ट्रीय आय का केवल ६ प्रतिशत बैठता है । सोवियत संघ में अप्रत्यक्ष करों का राष्ट्रीय आय के साथ २२ प्रतिशत का अनुपात है। इसलिये भारत के मुकाबले सोवियत संघ में अप्रत्यक्ष कराधान चार गुना अधिक है । मैं यह नहीं कहता कि यह सोवियत संघ की कोई खामी है । उसने अपने विकास के लिये जो मार्ग सब से ठीक समझा उसी को अपनाया है । माननीय सदस्य इन तथ्यों को जानते हैं फिर भी पता नहीं क्यों कहते रहते हैं कि अप्रत्यक्ष कराधान समाजवाद-विरोधी है ।

यह कहा गया है—मेरे ख्याल में श्री अ० क० गोपालन ने कहा है—कि व्यक्तिपरक कराधान पिछली दसाब्दी में २०.५ रुपये से ३१.१ रुपये तक बढ़ गया है। उसने उसी अवधि में १९५१-५२ में २७४ रुपये से १९६०-६१ में ३२७ रुपये तक व्यक्तिपरक आमदनी का जिक्र नहीं किया। निःसन्देह १९५१–५२ में ७.४ प्रतिशत से १९६०–६१ में ९.४ प्रतिशत तक कराधान का राष्ट्रीय आय से अनुपात बढ़ गया है। परन्तु भारत में करों से प्राप्त राजस्व का राष्ट्रीय आय से अनुपात बहुत देशों से कम है । तृतीय पंचवर्षीय योजना पर प्रतिवेदन यह स्पष्ट करता है कि यदि सरकारी क्षेत्र समाज की ओर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है तो यह अनुपात बढ़ना चाहिये। कराधान से राजस्व में वृद्धि का उल्लेख यह सिद्ध नहीं करता कि कराधान से गरीब और गरीब नहीं होते जाते हैं । कराधान की दो तरफें होती हैं । यदि किसी को कर देना पड़ता है तो उससे जो खर्च किया जाता है उससे उसे लाभ भी होता है ।

यह कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कराधान उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिये । जब हम ने मुनासिब समझा है तो हमने काफी प्रत्यक्ष कर लगाया है । इस वर्ष की मेरी प्रस्तावनाओं में प्रत्यक्ष-कराधान में पर्याप्त वृद्धि है। इस वर्ष की प्रस्तावनाओं का जिक्र न करके श्री ए० के० गोपालन यह साबित करने के लिये दूसरे देशों के मुकाबिले में भारत में निगम-कर का आपात कम था १९५७ तक पीछे चले गये । इस वर्ष की प्रस्तावनाओं के फलस्वरूप भारतवर्ष में निगम-कर का आपात ५० प्रतिशत होता है जो कि अमेरिका से थोड़ा ही कम या लगभग उसके बराबर और इंगलैंड में ४२.१५ प्रतिशत, कनेडा में ४४ प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में ४० प्रतिशत, पश्चिम जर्मनी में ४०.५ प्रतिशत जापान में ३८ प्रतिशत और नैदरलैंड्स में ४३ प्रतिशत जैसे बहुत से देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है । कुछ मित्र कहेंगे कि निगम-कर बहुत ज्यादा है, अतः इसे कम करना चाहिये यह भी उचित नहीं है क्योंकि निगमें भी सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के कारण लाभ उठाती हैं। इसलिये सरकार के लिये निगमों पर कर बढ़ाना जैसे कि इस वर्ष किया है उचित है ।

श्री गोपालन ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी निर्धारित आय पर निर्धारित किये गये कर १९५१–५२ में १६.९ प्रतिशत से १९५९–६० में १३ प्रतिशत तक नीचे आ गये हैं। इसका विशेष कारण यह है कि १९५१–५२ से १९५९–६० तक की अवधि में निर्धारित आय में वृद्धि अधिकतर निचली आय वाले वर्गों में हुई थी । व्यक्तियों की कुल निर्धारित आय १९५१–५२ में ४७५ रुपये से १९५९–६० में ७४२ करोड़ रुपये तक बढ़ गई । ८ वर्ष में २७० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का तीन चौथाई भाग उन व्यक्तियों से सम्बन्धित था जिनकी आय २५,००० रुपयों से कम थी। इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि कर की निर्धारित आय से समस्त अनुपात में कमी हुई है और श्री गोपालन ने यह नोट कर लिया है । जो कुछ हुआ है यह आय-कर देने वाले वर्गों में अधिकतर न्याय विभाजन के फलस्वरूप हुआ है । श्री गोपालन ने जो मतलब निकाला है वैसा सोचना ठीक नहीं है ।

[श्री मोरारजी देसाई]

आय कर के आपात के आधार पर तुलना गलत है। १९५७-५८ से अमीर लोग सम्पदा कर भी देते रहे हैं। यदि हम आयकर और सम्पदाकर के इकट्ठे बोझ को देखें तो पता चलता है कि यह बोझ उन व्यक्तियों के लिये जिन की निर्धारित आय १ लाख रुपयों से अधिक है १९५१ में लगभग ६७ प्रतिशत से १९५९-६० में ५१ से ७० प्रतिशत तक बढ़ गया है और इस वर्ष का प्रस्तावनाओं से यह अनुपात और भी बढ़ जायगा।

अब मैं व्यक्तिगत आय के बारे में कुछ आंकड़े बताता हूं कि नीची आमदनी वाले वर्गों में वे किस तरह बढ़े हैं और ज्यादा आमदनी वाले वर्गों में कम हुए हैं। मैंने इन आंकड़ों को देखा और पिछले तीन चार वर्षों का ध्यान रखते हुए आंकड़े निकाले और मुझे पता चला है कि ३,००० रुपये और ५,००० रुपये के बीच के करदाताओं की संख्या जो १९५७-५८ में १५१,५११ थी अब २७२,८५९ हो गई है। इस वर्ष के लोगों की आमदनी नीचे की आमदनी से बढ़ी है। फिर ५,००० से १०,००० रुपये वाले वर्ग में उनकी संख्या १७७,००० लगभग २८९,००० तक बढ़ गई है; १०,००० से १५,००० रुपये के वर्ग में ५०,००० से ६०,००० तक; १५,००० से २५,००० रुपयों तक के वर्ग में ३४,००० से ५८,००० तक; २५,००० से ४०,००० रुपयों के वर्ग में १६,००० से २५,०००; ४०,००० से ७०,००० रुपय के वर्ग में उन की संख्या ८,००० से १२,००० तक बढ़ी है, ७०,००० से १ लाख रुपये तक के वर्ग में २,१०० से २,७०० तक बढ़ी है और १ लाख से ऊपर उनकी संख्या २,२२४ से २,१५९ रह गई है। अतः १ लाख से अधिक वर्ग में उनकी संख्या कम होती जा रही है और कम आमदनी वाले वर्ग में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। कम आमदनी वाले वर्ग में अधिक वृद्धि इसलिये हुई क्योंकि जिन लोगों की आमदनी बहुत कम थी अधिक हो गई है। ३,००० रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्तियों में यही कार्यवाही होती रही है। इस तरह से लोगों की हालत अच्छी होती जा रही है।

यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों की हालत उतनी अच्छी हो गई जितनी हम चाहते हैं। परन्तु रोम एक दिन में नहीं बना था और समाजवाद एक दिन में, पांच या दस वर्ष में नहीं लाया जा सकता। यह तो मिल कर लगातार काम करने से होगा और एक दूसरे से दुश्मनी करके नहीं और न ही गलत कहानियां कि गरीबी बढ़ रही है और धनी लोग लाभ उठा रहे हैं इत्यादि फैला कर लोगों का नैतिक पतन करके। इससे जन साधारण का नैतिक पतन होता है उत्थान नहीं।

इसी तरह से मूल्यों के बढ़ जाने की बात है। अभी मेरे मित्र बनर्जी ने बताया कि पार्लियामेंट कैन्टीन में दियासलाई ७ नये पैसे की मिलती है। मुझे पता चला है कि कैन्टीन तो इसे नहीं बेचती। मुझे पता चला कि कोई बाहर बेच रहा है। मैंने किसी को भेजा और दियासलाई ६ नये पैसे में खरीदी। इस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री शर्मा ने भी कहा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसलिये मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिये; आप पीते हैं और जो हो बन रहो। यह दियासलाई मैंने खरीदी है।

†**श्री अ० कृ० गोपालन** : वित्त मंत्रीजी हौसले से कहें कि बजट पेश करने के बाद कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लोग इसे समझ लेंगे।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हौसले का एकाधिकार मेरे मित्र को ही नहीं दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० क० गोपालन : आप इस तरह से बातें कहते रहे हैं मैं चुप रहा हूं। क्या मैं इनका जवाब नहीं दे सकता।

†श्री मोरारजी देसाई : मैं ने माननीय सदस्य के भाषण में दखल नहीं दिया। वे भी मेरे भाषण में दखल न दें।

†श्री अ० क० गोपालन : क्योंकि आप ने उस तरह से बात नहीं की जैसे मैंने की। आप कह रहे हैं "सचाई को छुपा रहे", "निर्लज्जता" इत्यादि।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान से देखता रहा हूं। उन्होंने सुझावों के सम्बन्ध में कहा, भाषण के बारे में नहीं। "झूठ की कोशिश" सुझावों के बारे में है। लोकतन्त्र में बर्दाश्त करना पहली आवश्यक बात है। यदि कोई शब्द आपत्तिजनक हो, तो उस समय बतलाना चाहिये। यह कहना कि यह उस व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है हानिकारक नहीं है। इस में कुछ आपत्तिजनक नहीं है।

†श्री मोरारजी देसाई : कल मेरे सहयोगी ने मूल्यों के सम्बन्ध में आंकड़े दिए और सब बातों की व्याख्या की। उन्होंने फजूल खर्च, विकास के अतिरिक्त व्यय, योजना के लक्ष्य, सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं, उनके लाभों, बैंकों से उधार और मूल्यों के बारे में कहा। चूंकि उन्होंने इन सब बातों के बारे में कहा इसलिये मैं उन को दौहराना नहीं चाहता। यदि वे चाहते हैं तो मैं जानकारी दे सकता हूं। दिल्ली के बाजारों से मूल्य लिए गए हैं। कल ही लिए थे। तीन चीजें आम आदमी पर प्रभाव डालती हैं।

†अध्यक्ष महोदय : कल यह आपत्ति करी गई थी कि क्या मल्यों की जांच राजस्व प्राधिकारियों द्वारा कराई गई थी ? कल यह आरोप लगाया गया था कि फुटकर व्यापारी आम व्यक्ति को महंगी चीज देता है।

†श्री मोरारजी देसाई : आधा घण्टा पहले मैं किसी को बाहर भेजा है और उसे फुटकर व्यापारी से खरीदने को कहा।

†श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : क्या आपके पास रसीद है ?

†श्री मोरारजी देसाई : आप देख सकते हैं। कल भी मैं ने यही कहा। एक किस्म की खुली चाय का मूल्य ८.६० रुपए प्रति किलोग्राम थी और यही मूल्य रहा है, साफ की हुई चाय का मूल्य ४.२५ रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। चीनी पर कोई कर नहीं लगाया है। चीनी का मूल्य १.१५ रुपए से १.१७ रु० प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया है। कुछ दिनों तक दियासलाई का मूल्य ७ नए पैसे हो गया था। अब फिर ६ नए पैसे हो गया है। मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि इतने विशाल देश में कहीं भी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। आम तौर पर मैंने पता किया है। इन चीजों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। दूसरी चीजों की बढ़ गई हों, उसका मैं झगड़ा नहीं करता। मैं उन वस्तुओं का जिक्र कर रहा हूं जिनका बजट से सम्बन्ध है।

गोल्ड फ्लेक के सिगरेटों की कीमत ०.९२ रु० से १ रु० हो गई है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कैंची के सिगरेटों की कीमत नहीं बढ़ी है। चार मीनार की ०.१५ रु० से ०.१६ रु० हो गई है।

†कोई माननीय सदस्य : आम आदमी का सिगरेट।

†श्री मोरारजी देसाई : अच्छा है यदि साधारण व्यक्ति चार मीनार सिगरेट न पीए। लन्दन नेवीकट की कीमत ०·१५ रु० से ०·१९ रु० हो गई है। बीड़ियों की कीमत नहीं बढ़ी है। १० की कीमत

---

†मूल अंग्रेजी में

६ नए पैसे रही है और २५ की १५ नए पैसे। इन मामलों में हौसले वाला होना या न होने का प्रश्न कहां है? जब उन्होंने कहा "वे हौसले से कहें" तो मैंने तो एतराज नहीं किया। जब मने कहा कि उनका विशषाधिकार नहीं है तो वे एतराज करते हैं।

जो मैंने कहा है उससे किण हुआ गया है। क्योंकि तन्दुरुस्त चमड़े पर तो कोई तकलीफ नहीं होती।

हम ५,००० की आमदनी पर ४२ रुपए कर लगाते हैं। ४,९५८ रुपए उस के पास रह जाते हैं। १०,००० रुपए की आय पर हम केवल ४९० रु० लेते हैं और ९,५१० रु० उसके पास रह जाते हैं। २०,००० रु० पर हम २,३२८ रु० लेते हैं और १७,६७२ रु० उसके पास रह जाते हैं। ४०,००० रु० पर ११,००० रु० लेते हैं और उस के पास २८,००० रु० रह जाते हैं। ७०,००० रुपयों पर ३१,००० रु० लेते हैं और लगभग ३८,००० रु० उसके पास रह जाते हैं। १ लाख रु० पर हम ५४,३३२ रु० लेते हैं और उसके पास ४५,६६८ रु० रह जाते हैं, २ लाख की आमदनी पर हम १,३७,७०७ रु० लेते हैं और ६२,२९३ रु० रह जाते हैं। ३ लाख की आय पर हम २,२१,०८२ रु० लेते हैं और ७८,५१८ रु० उसके पास रह जाते हैं, ५ लाख की आय पर ३,८७,००० रु० लेते हैं और १,१३,००० रु० रह जाते हैं। १० लाख की आय पर ८,०४,००० रु० लेते हैं और १,९५,००० रु० रह जाते हैं। २० लाख की आय पर १६,३८,००० रु० लेते हैं और ३,६२,००० रु० रह जाते हैं। यदि हम सारा ही ले जायें तो कोई २० लाख रु० नहीं कमाएगा। इसका मतलब भी यह होगा कि कुछ गलत बात है।

इस सम्बन्ध में व्यय कर हटाने की आलोचना की गई थी। यदि व्यय कर ने वह काम किया होता जो हम चाहते थे तो मैं इसे न हटाता। मैंने व्ययकर को उठाया है जिससे ज्यादा से ज्यादा मुझे ८५ लाख रुपये मिले और उन्हीं लोगों के लिये सम्पदा-कर बढ़ा दिया है। मैंने उनके आय-कर का खंड बढ़ा दिया है और मैंने ८५ लाख रुपयों की बजाए ४.८८ करोड़ रुपये लिए हैं। ८५ लाख रुपए छोड़ कर मैंने लोगों से ४.८८ करोड़ रुपए ले लिए हैं। यह समाजवादी कदम है या ८५ लाख रुपयों को कायम रखना और दूसरे को न लेना समाजवादी कदम है? यदि व्ययकर से कमियों को दूर करने में सहायता मिलती तो मैं इसे समझ सकता, परन्तु इसने अधिक कमियां पैदा कर दी हैं, क्योंकि इससे बचने के लिये लोगों ने नकदी को हिसाब में न लाने की कोशिश की। वे उसे खर्च कर देते हैं ताकि इसे व्यय के फार्मों में नहीं दिखलाना है और इसलिये इसका पता नहीं चल सकता। इसका मतलब है, मुझे आयकर का नुकसान होता है। न मुझे आयकर मिलता है, न सम्पदा कर, न व्यय कर। कम्पनी के व्यय में भी उनकी आय का हिसाब होता है। व्ययकर से ऐसा करने का प्रोत्साहन मिलता था। इसी लिए इसे हटा दिया गया। किसी के लाभ के लिये नहीं हटाया गया।

मेरे पीछे जो माननीय मित्र बैठे हैं ये १,५०,००० रु० व्यय-कर के रूप में देते थे। उन्हें १,५०,००० रु० का लाभ हुआ है और २,५०,००० रु० वे देंगे।

इसी सम्बन्ध में यह कहा गया था कि जो आय कर बनाते हैं उनकी सूचियां छापेंगे, परन्तु हमने ऐसा नहीं किया है। जिन लोगों को कर से बचने के लिय सजा मिली थी उनकी सूची अधिनियम के अनु-सार मार्च में सभा पटल पर रखदी गई थी। १९६० में अधिनियम पास हुआ था। पहली सूची इसी वर्ष में तैयार होनी थी और मार्च में रख दी गई। अगली सूची अगले मार्च में रख दी जाएगी। मेरे से और

क्या आशा की जाती है। यदि वे तथ्यों के विरुद्ध कहते जाएं और मैं कह दूं कि वे तथ्यों को छुपाते हैं तो उस पर एतराज़ किया जाता है। मैं इसे कैसे कह सकता हूं। झूठ को सच कहना मेरे लिये बहुत कठिन है। मैं ने यह कभी भी नहीं कहा और न कहता हूं कि मेरे माननीय मित्र झूठे हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य को ऐसे तरीके अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे तो तरीकों पर एतराज था, परन्तु उन्होंने ऐतराज नहीं किया, क्योंकि वे इस विषय में किसी तरह से ईमानदार हैं। सचाई की यह परिभाषा होगी : सचाई वह है जो काम आए।

†श्री ए० के० गोपालन : वे कहते हैं "वह कम से कम उसमें ईमानदार हैं।" दूसरे मामलों में ईमानदार नहीं हैं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं गोपालन जी से सहमत हूं। ऐसा नहीं कहना चाहिये।

†श्री मोरारजी देसाई : मैं यह नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूं कि उसमें वे पूर्णतया ईमानदार हैं। मै "उस मामले में" शब्द वापस लेता हूं, क्यों मैं यह नहीं कहना चाहता।

†श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : केवल उसी मामले में इसकी परीक्षा की गई और वह ईमानदार है। और मामलों में इसकी परीक्षा नहीं की गई।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस समय इस मामले पर चर्चा नहीं हो रही।

श्री मोरारजी देसाई : अपनी बात को समाप्त करने से पहिले मैं तुलनात्मक विकास दरों का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे जिस माननीय मित्र ने इस बात का उल्लेख किया है उन्होंने प्रथम और द्वितीय योजना के काल में भी इस बात की चर्चा की थी। उस समय राष्ट्रीय आय में कुल तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और प्रति व्यक्ति आय डेढ़ प्रतिशत ही बढ़ी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विकास की गति बढ़ाई जानी चाहिये ताकि १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। परन्तु यह समझना ठीक नहीं होगा कि भारत की प्रगति अन्य विकासशील देशों की प्रगति के सामने हेय है। यदि हम विनियोजन की वृद्धि, बढ़ती हुई घरेलू बचतों, सरकारी क्षेत्र के विकासशील पूंजी निर्माण और कुल सरकारी व्यय में निश्चित विनियोजन के अंश में वृद्धि को देखें तो ज्ञात होगा कि हमारी प्रगति अन्य समान देशों से कम नहीं है। वास्तव में हमारा कार्य उनसे अच्छा रहा है। हमारी घरेलू बचतों में वृद्धि हुई है। प्रथम योजना में यह लगभग ५ प्रतिशत था जो कि द्वितीय योजना के अन्त तक साढ़े आठ प्रतिशत हो गया। सरकारी व्यय में जो पक्की पूंजी लगाई गयी थी उसके अंश में भी वृद्धि हुई है।. यह १९५०–५२ में ३१ प्रतिशत था। जो कि काफी बढ़ गया है : सरकारी क्षेत्र में विनि-योजन २६७ करोड़ रुपये से बढ़ कर ६०० करोड़ रुपये हो गया है।

यद्यपि और देशों के मुकाबले में हमारी प्रगति बहुत अच्छी है परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। गत १० वर्षों में जो कुछ हमने किया है यह तो आरम्भ है, बस हमें इतना सन्तोष है कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। और इसी रास्ते पर चल कर हम प्रगतिशील समाज और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सकेंगे जिसके द्वारा सभी नागरिकों को जीवन की विविध दिशाओं में एक समान अवसर प्राप्त होते रहेंगे।

अन्त में मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा कि मेरी इच्छा किसी के हृदय पर आघात पहुंचाने की नहीं है। मुझे कोई अपने पर अभिमान नहीं है पर नीति की बात तो करनी ही पड़ती है। नीति की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

बात करते हुए ही मने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे हमारे कुछ माननीय मित्रों को कुछ दुःख पहुंचा है, यद्यपि उन्हें किसी प्रकार का दुःख पहुंचाने की मेरी कामना कभी नहीं थी। मैं इतना जानता हूं कि सच्ची बात किसी समय दुखदायी होती है। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सच्ची बात को ऐसे ढंग से कहूं कि वह कड़वी प्रतीत न हो। और किसी माननीय मित्र को मेरी अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायत न हो।

अध्यक्ष महोदय : आय व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई। अब सभा स्थगित होती है।

[इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ११ मई, १९६२/वैशाख २१, १८८४ (शक) के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १० मई, १९६२ / २० वैशाख १८८४ (शक)]

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — १७२५—५०

तारांकित प्रश्न संख्या

६१०	गोबर से बनने वाली गैस . .	१७२५
६११	ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	१७२५–२६
६१२	फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा .	१७२७–२८
६१३	फास्फोरस संयंत्र	१७२८–२९
६१४	गोआ में परती भूमि . . .	१७२९–३०
६१५	ओखला स्थित भारत-जर्मन नमूना केन्द्र में दुर्घटना . .	१७३०—३२
६१७	रेल व सड़क परिवहन में समन्वय	१७३२—३४
६१८	लघु उद्योग सेवा संस्था .	१७३४–३५
६१९	कांच का सामान बनाने वाले कारखाने.	१७३५
६२०	मद्रास राज्य में जिप्सम का कारखाना .	१७३५–३६
६२३	लंका से निष्कासित भारतीय राष्ट्रजन	१७३६—३९
६२६	सामाजिक-आर्थिक विषयों का अनुसन्धान . .	१७३९–४०
६२७	शाहजहां रोड (नई दिल्ली) के समीप क्वार्टरों का निर्माण	१७४०—४२
६२८	पाकिस्तानी जेलों में भारतीय	१७४२–४३
६२९	माप की मीटरिक प्रणाली	१७४३—४५
६३०	तृतीय पंचवर्षीय योजना .	१७४५–४६
६३१	अस्पृश्यता निवारण उसम्बन्धी फिल्म .	१७४६–४७
६३२	राज्य व्यापार निगम .	१७४७–४८
६३८	कर्नल भट्टाचार्य	१७४८—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

६१६	श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति . . .	१७५०–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
६२१	भारत सरकार के मुद्रणालय	१७५१
६२२	खान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ की कार्यान्विति	१७५१–५२
६२४	मद्रास में केन्द्रीय सरकार के दफ्तर . .	१७५२
६२५	दलाई लामा की प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात . .	१७५२
६३३	नये बांटों के बारे में पश्चिम बंगाल के व्यापारियों की कठिनाई .	१७५२–५३
६३४	पीने के पानी की योजना के सम्बन्ध में भारत-नेपाल करार	१७५३
६३५	मूलभूत रसायनों तथा मध्यवर्ती पदार्थों का कारखाना	१७५३–५४
६३६	कर्मचारी भविष्य निधि . . .	१७५४
६३७	गंगा के सम्बन्ध में दूसरी फिल्म . .	१७५४
६३९	आकाशवाणी	१७५५
६४०	चिनाकुरी कोयला खान में दुर्घटना . . .	१७५५
६४१	"नान-न्यूक्लियर क्लब"	१७५५–५६
६४२	चैकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधिमंडल द्वारा केरल का दौरा .	१७५६
६४३	रोजगार दफ्तर	१७५६–५७
६४४	दक्षिण अफ्रीका के भारतीय	१७५७
६४५	अमरीका को भारतीय चाय शिष्टमंडल . . .	१७५७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०२८	शाहदरा (दिल्ली) में घड़ी का कारखाना . . .	१७५७–५८
१०२९	पंजीयित बेरोजगार	१७५८
१०३०	मतदाताओं के लिये चलचित्र	१७५८
१०३१	हथकरघे के कपड़े का निर्यात . . .	१७५८–५९
१०३२	अखबारी कागज	१७५९
१०३३	साइकिलों का निर्यात	१७५९–६०
१०३४	उद्योगों में विदेशी पूंजी	१७६०
१०३५	आकाशवाणी में हिन्दी का प्रयोग . . .	१७६१
१०३६	विदेशी औषधियों का आयात . . .	१७६१
१०३७	कांगो में भारतीय सेना	१७६२
१०३८	ब्रह्माण्ड किरणों का अध्ययन	१७६२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

अतारांकित प्रश्न संख्या

१०३९	कानपुर के चमड़ा उद्योगों के श्रमिकों के लिये भविष्य निधि	१७६२-६३
१०४०	बोनस आयोग . .	१७६३
१०४१	कानपुर में औद्योगिक आवास योजना	१७६३
१०४२	काली मिर्च के दाम . . .	१७६४
१०४३	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये भवन	१७६४
१०४४	हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी . .	१७६४
१०४५	फ्रांस को सिलाई की मशीनों का निर्यात .	१७६५
१०४६	भारत में समाचार माध्यमों का सर्वेक्षण .	१७६५
१०४७	हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड . . .	१७६५-६६
१०४८	आकाशवाणी . . .	१७६६
१०४९	बिहार में कृषक . .	१७६७
१०५०	उड़ीसा में कृषक	१७६७-६८
१०५१	आसाम में कृषकों के लिये रोजगार . . .	१७६८-६९
१०५२	पश्चिमी बंगाल में कृषकों के लिये रोजगार	१७६९-७०
१०५३	वायदा बाजार आयोग . . .	१७७०
१०५४	प्रैस आयोग	१७७०
१०५५	आन्ध्र प्रदेश अभ्रक कर्मचारी सम्मेलन . . .	१७७०-७१
१०५६	कोलया खानों के लिये माल लादने की सुविधायें . .	१७७१
१०५७	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली के पंखे .	१७७१
१०५८	नागपुर में केन्द्रीय सरकार के दफ्तर . .	१७७२
१०५९	हज यात्री	१७७२
१०६०	उड़ीसा में भूमि विषयक विधान . . .	१७७२-७३
१०६१	चुराई हुई मोटरगाड़ियां . . .	१७७३
१०६२	होजरी उद्योग	१७७३
१०६३	बीकानेर में कांच के सामान का कारखाना . .	१७७४
१०६४	राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र . .	१७७४
१०६५	सिंघभूम में यूरेनियम की खानें .	१७७४-७५
१०६६	भारतीय श्रम सम्मेलन . . .	१७७५
१०६७	तीसरी योजना के लिये पंजाब में उद्योगों के लिये आवंटन .	१७७५-७६

विषय

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०६८	साबुन का उत्पादन . :	१७७६–७७
१०६९	योजना की परियोजनाओं पर खर्च	१७७७
१०७१	मध्य प्रदेश का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण	१७७७
१०७२	आकाशवाणी के "स्टाफ आर्टिस्ट" .	१७७७–७८
१०७३	भारत सरकार के मुद्रणालय में पदों की श्रेणियां	१७७८
१०७४	कम्पोजीटरों के वेतन क्रम का संशोधन	१७७८–७९
१०७५	भारत सरकार का मुद्रणालय नई दिल्ली .	१७७९
१०७६	भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१७७९–८०
१०७७	विदेशों के बच्चों के लिये उपहार	१७८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १७८३–८४

श्री उमानाथ ने मद्रास में छपाई के कागज की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने इस संबंध में वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४

भारतीय बायलर्स अधिनियम, १९२३ की धारा २८-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ में प्रकाशित पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रक्रिया नियम, १९६१ की एक प्रति ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १७८४–१८२८

सामान्य आय व्ययक, १९६२–६३ पर सामान्य चर्चा जारी रही तथा चर्चा समाप्त हुई ।

शुक्रवार, ११ मई, १९६२/२१ वैसाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

अनुदानों की मांगों पर चर्चा, तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

GMGIPND—LSIII—759(Ai)LSD—12-7-62—150